दैनिक जागरण
समाधान प्राय: समस्या के इर्दगिर्द ही होता है

एथनाल मिश्रित पेट्रोल

यह अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि ई-20 ईंधन अर्थात एथनाल मिश्रित पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज भले ही कुछ कम होता हो, लेकिन यह ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए भी लाभकारी है। इसके अतिरिक्त यह विदेशी मुद्रा की बचत में भी सहायक है। और भी अच्छा होता कि यह स्पष्टीकरण पहले ही आ जाता, क्योंकि एक अर्से से इस तरह की अपुष्ट खबरें डिजिटल मीडिया में तैर रही थीं कि 20 प्रतिशत एथनाल वाले पेट्रोल से माइलेज में अच्छी-खासी कमी आने के साथ ही वाहन के इंजन को भी नुकसान पहुंचता है। कुछ लोगों ने तो ऐसे फर्जी वीडियो शेयर किए कि ई-20 पेट्रोल से उनकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई। इस दुष्प्रचार को देखते हुए सरकार और विशेष रूप से पेट्रोलियम मंत्रालय को समय रहते सक्रिय होना चाहिए था और वस्तुस्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। देर से ही सही, यह काम किया गया, लेकिन अभी इस बारे में स्पष्टता की अपेक्षा है कि क्या पांच-छह साल पुरानी गाड़ियों के लिए भी ई-20 पेट्रोल उपयुक्त है? उचित यह होगा कि इस तरह का कोई स्पष्टीकरण देने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ ही आटो कंपनियां भी आगे आएं। यह ठीक है कि कुछ कार कंपनियों के अधिकारियों ने लोगों को आश्वस्त किया है, लेकिन बेहतर होता कि इस मामले में आटो कंपनियों के संगठन सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स की ओर से भी अपनी बात कही जाती। वैसे भी इस संगठन का मुख्य कार्य सरकार के साथ मिलकर आटो सेक्टर की नीतियों, सुरक्षा मानकों और उत्सर्जन संबंधी नियमों को तय करना है।

ई-20 मामले से सरकार को यह सीख लेनी चाहिए कि कोई नई पहल करने के साथ ही हितधारकों को भरोसे में लेना और आम लोगों को उसके उद्देश्यों से परिचित कराना आवश्यक होता है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि एक एजेंडे के तहत किसी लाबी की ओर से ई-20 ईंधन के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाया गया। नीति-नियंताओं को ऐसे एजेंडाधारियों के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। यदि यह पहले दिन से ही स्पष्ट होता कि ई-20 ईंधन से माइलेज में महज 3-4 प्रतिशत की कमी आती है और इसके इस्तेमाल से इंजन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता तो शायद एथनाल मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों को सक्रिय होने का अवसर ही नहीं मिलता। आखिर इसके पहले ई-10 पेट्रोल का उपयोग हो ही रहा था और उसे लेकर कोई शिकायत भी नहीं थी। इस तथ्य की भी अनदेखी न की जाए कि विश्व के कई देशों में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनाल मिलाया जाता है। ब्राजील तो बायोफ्यूल के मामले में वैश्विक लीडर है। यहां सामान्य पेट्रोल में 27 से 30 प्रतिशत तक एथनाल मिलाया जाता है।

शिक्षा की गुणवत्ता

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की परफार्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फार डिस्ट्रिक्ट्स तथा यू-डाइस प्लस रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन राज्य की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता का प्रमाण है। देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में स्थान बनाना और हमीरपुर जिले का प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ जिला बनना गर्व का विषय है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों से किए गए निवेश और लागू किए गए सुधारों का सकारात्मक परिणाम प्राप्त किया है। हिमाचल की सबसे बड़ी ताकत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, पर्याप्त शिक्षक उपलब्धता और विद्यार्थियों तक शिक्षा की सहज पहुंच है। छात्र-शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर होना संकेत है कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण मिल रहा है। उपलब्धियों के साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी सामने हैं। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या घट रही है। डिजिटल शिक्षा, आधुनिक आधारभूत सुविधाओं और छात्र सुरक्षा के क्षेत्र में भी निरंतर सुधार की आवश्यकता है। सरकारी विद्यालयों के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत करना, नई तकनीकों को शिक्षा से जोड़ना तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाना समय की मांग है। यदि इन पहलुओं पर गंभीरता से कार्य किया गया तो प्रदेश देश के लिए शिक्षा का आदर्श भी बनेगा।

हिमाचल का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन लागू किए सुधारों का सकारात्मक परिणाम है

समय के अनुरूप बदली विदेश नीति

प्रो. गौरव वल्लभ

प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश में बसे भारतीयों को केवल प्रवासी समाज नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत शक्ति का विस्तार माना हैं

अवधेश राजपूत

अपनी तीन देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंडोनेशिया और आस्ट्रेलिया में भारतीयों को संबोधित किया। इसके बाद वे न्यूजीलैंड में भी ऐसा करने वाले हैं। इसके पहले 28 जून को सेशेल्स की नेशनल असेंबली में उन्होंने अपने संबोधन में अगस्त 1770 में सेंट ऐनी द्वीप पहुंचे पांच भारतीयों का उल्लेख किया था। किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने सेशेल्स की संसद में पहली बार यह संदेश दिया कि भारत और सेशेल्स के संबंध केवल राजनयिक इतिहास से नहीं, बल्कि साझा सभ्यतागत स्मृतियों और भारतवंशियों की पीढ़ियों से निर्मित विश्वास से जुड़े हैं। यह केवल अतीत का स्मरण नहीं, अपितु भारत की बदलती विदेश नीति की उद्घोषणा थी। प्रधानमंत्री के इस संदर्भ को समझने के लिए गिरमिटिया इतिहास को समझना आवश्यक है। 1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा दास प्रथा समाप्त किए जाने के बाद ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी उपनिवेशों में श्रमिकों का संकट उत्पन्न हुआ। इसका समाधान इंडेंटर्ड लेबर सिस्टम के रूप में निकाला, जिसमें एग्रीमेंट शब्द भोजपुरी-अवधी अपभ्रंश में 'गिरमिट' बन गया और अनुबंधित श्रमिक 'गिरमिटिया' कहलाए।

10 सितंबर, 1834 को पहला जहाज कलकत्ता से मारीशस के लिए रवाना हुआ और 2 नवंबर, 1834 को पोर्ट लुईस पहुंचा। इस मोर्चे पर मार्च 1917 आते-आते भर्तियों पर रोक लगी और 1922 तक यह व्यवस्था व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गई। इस दौरान लगभग 11.2 लाख भारतीय मारीशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, नटाल और अन्य उपनिवेशों में भेजे गए। आज उनके वंशजों की संख्या लगभग 70-80 लाख है। देखा जाए तो गिरमिट केवल शोषण का इतिहास न होकर पीड़ा से प्रतिष्ठा और परिश्रम से पराक्रम की यात्रा है। कभी 'कुली' और 'जहाजी' कहे जाने वाले लोगों की संतानों ने आज अनेक देशों की राजनीति, न्यायपालिका, उद्योग, शिक्षा और प्रशासन आदि में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी ने भी इस प्रश्न को राष्ट्रीय चेतना का विषय बनाया।

स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताएं राष्ट्र निर्माण, गुटनिरपेक्षता और नव स्वतंत्र देशों के साथ संबंधों पर केंद्रित थीं। उस समय यह दृष्टिकोण उभरा कि विदेशों में बस चुके भारतीय जिस देश के नागरिक हैं, उन्हें उसी राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए। नेहरू और बाद में इंदिरा ने भी इसी नीति को आगे बढ़ाया। परिणामस्वरूप गिरमिटिया समुदाय लंबे समय तक भारत की विदेश नीति के केंद्र में स्थान नहीं बना सका। सांस्कृतिक संबंध बने रहे, लेकिन संस्थागत प्राथमिकता सीमित रही। फिजी में 1987 और 2006 के राजनीतिक संकटों ने भारतीय मूल के लोगों की असुरक्षा को उजागर किया। उस दौर ने यह प्रश्न खड़ा किया कि क्या भारत केवल उनकी स्मृतियों में है या उनके वर्तमान के साथ भी खड़ा है? पिछले एक दशक में इस प्रश्न का उत्तर भारत की विदेश नीति ने नए रूप में दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गिरमिटिया समुदाय को केवल प्रवासी समाज नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत शक्ति का विस्तार माना। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत किसी से उसकी नागरिकता या राष्ट्रीय निष्ठा बदलने की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि इतना चाहता है कि वे अपने देश के आदर्श नागरिक बने रहकर भी अपनी भारतीय सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहें। यही भारत की नई विदेश नीति का सबसे बड़ा परिवर्तन है। यही परिवर्तन गिरमिटिया समुदाय के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव लेकर आया है कि भारत ने उन्हें छोड़ा नहीं, बल्कि उनके सम्मान, सांस्कृतिक पहचान और विरासत का नैतिक गारंटर बनकर उभरा है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रवासी भारतीयों के हितों में कई कदम उठाए गए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन जीवंत हुए हैं। ओवरसीज सिटिजन आफ इंडिया यानी ओसीआइ व्यवस्था को अधिक सुगम बनाया गया और गिरमिट देशों के साथ उच्चस्तरीय संवाद बढ़ा। फोरम फार इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स को-आपरेशन, वैक्सीन मैत्री, मिशन सागर, जल एंबुलेंस, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, स्वास्थ्य सहयोग, क्षमता निर्माण और जलवायु साझेदारी ने छोटे द्वीपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को नई ऊंचाई दी है। कोविड-19 के दौरान भारत इन तमाम देशों में सबसे पहले सहायता पहुंचाने वाले देशों में था।

यह परिवर्तन केवल विकास और सहयोग तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक गहरा रणनीतिक सोच भी है। मारीशस, सेशेल्स, फिजी, गुयाना, सूरीनाम और अन्य देश आज हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बदलती भू-राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, ब्लू इकोनमी, समुद्री संसाधनों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं और बहुपक्षीय संस्थाओं में सहयोग के मोर्चे पर इन देशों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत की वर्तमान विदेश नीति ने समय रहते इस महत्व को पहचाना और इन देशों के साथ अपने संबंधों को केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया। आज कई देशों में भारतीय आगमन दिवस तथा गिरमिट स्मृति दिवस राष्ट्रीय सम्मान के साथ मनाए जाते हैं। जिन लोगों को कभी अपमानित किया गया था, आज उनके सम्मान में राष्ट्रीय समारोह आयोजित होते हैं। यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति और गिरमिटिया समुदाय की असाधारण यात्रा का ही प्रमाण है।

गिरमिट गाथा अंततः भारत के उदय का भी आख्यान है, जिसमें संघर्ष से सफलता, विस्थापन से विश्वास और पीड़ा से प्रतिष्ठा जैसे बिंदुओं का समावेश है। पीएम मोदी की हालिया यात्राएं इस परिवर्तन को ही रेखांकित करती हैं कि उन्होंने गिरमिटिया समुदाय को मात्र इतिहास का विषय नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति, सांस्कृतिक कूटनीति और वैश्विक साझेदारी का अभिन्न अंग बनाया है। भारत ने अपने बिछड़े परिवार को केवल याद नहीं किया, अपितु यह विश्वास भी दिलाया है कि विश्व के किसी भी कोने में रहने वाला भारतवंशी अकेला नहीं है।

(लेखक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य हैं)

response@jagran.com

संतुलित होता असंतुलित विकास

मुनि शंकर पाण्डेय

पारंपरिक रूप से कम विकसित रहे उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर में बीते एक दशक से तेज विकास हो रहा हैं

स्वतंत्रता के बाद की सरकारों की नीतियों के कारण भारत में आधारभूत संरचना के विकास का दायरा केवल दक्षिण भारत, महानगरों और बड़े शहरों तक सीमित रहा। परिणामस्वरूप कभी बड़े साम्राज्यों के केंद्र रहे उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों के लिए 'बीमारू' शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। 1980 के दशक में जनसांख्यिकीविद् आशीष बोस ने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को 'बीमारू' कहा। यह अविकसित अर्थव्यवस्था, कमजोर अवसंरचना विकास, निर्धनता, निरक्षरता के परिणामस्वरूप जनसंख्या-विस्फोट, उच्च शिशु-मृत्यु तथा दुर्बल स्वास्थ्य से ग्रस्त प्रदेशों की संरचनात्मक जड़ता के सांकेतिक बोधक के रूप में रहा। वास्तविकता में इस स्थिति का विस्तार उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों तक रहा। जहां भारत की बड़ी आबादी विकास के पैमानों में पीछे रही। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार राज्यों के सहयोग से इन क्षेत्रों की बदहाली को दूर करने में बहुत हद तक सफल रही है।

हवाई संपर्क की बात करें तो 2014 से पहले देश में लगभग 74-75 परिचालन हवाई अड्डे थे। आज यह संख्या बढ़कर 160 से अधिक हो चुकी है। इनमें कई नए या पुनर्जीवित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे शामिल हैं, जैसे नोएडा (जेवर), मोपा (गोवा), शिवमोग्गा (कर्नाटक), होल्लोंगी (अरुणाचल प्रदेश), राजकोट (हिरासर) और अयोध्या प्रमुख हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हवाई संपर्क का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2014 तक भारत में लगभग 1,000-1,300 किलोमीटर एक्सप्रेसवे थे, जबकि अब यह नेटवर्क 6,000 किमी से अधिक हो चुका है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा, दिल्ली-देहरादून और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट उत्तर भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। पहले जहां आधुनिक एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा पश्चिमी और दक्षिणी भारत में केंद्रित था, वहीं अब उत्तर और पूर्वी भारत भी तेजी से इस नेटवर्क का हिस्सा बन रहे हैं। केंद्र सरकार ने विकेंद्रित ढांचागत निर्माण की नीति को ऊर्जा क्षेत्र में भी लागू किया। देश रिफाइनरियों का विस्तार किया गया है। विशेष रूप से जोधपुर में रिफाइनरी का शिलान्यास, बरौनी रिफाइनरी का उन्नयन, पानीपत रिफाइनरी का विस्तार और पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश इस बदलाव के उदाहरण हैं। इसके साथ ही ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन, जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइपलाइन, नार्थ-ईस्ट गैस ग्रिड और अन्य परियोजनाओं ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर राज्यों तक प्राकृतिक गैस पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड जैसी भारत सरकार की कंपनियों को आगे किया।

नए हवाई अड्डों के विकास से बढ़ी प्रगति की आस। फाइल

वर्तमान भारत के औद्योगिक राजनीतिक भूगोल में इस समय एक बड़ा परिवर्तन चुपचाप आकार ले रहा है। लंबे समय से देश के आटोमोबाइल उद्योग का केंद्र दक्षिण और पश्चिम भारत रहा है। तमिलनाडु को डेट्रायट आफ इंडिया कहा गया, जबकि गुजरात ने बीते डेढ़ दशक में गतिशील औद्योगिक नीति के बल पर वैश्विक वाहन कंपनियों को आकर्षित कर देश के सबसे बड़े आटो हब में अपनी जगह बना ली, परंतु अब उत्तर भारत में एक नया औद्योगिक भूगोल तेजी से उभर रहा है, जिसके केंद्र में उत्तर एवं मध्य के राज्य और पूर्वोत्तर भारत हैं। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से इन कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार एक्सप्रेसवे, समर्पित मालवाहक गलियारों, बहुस्तरीय परिवहन केंद्रों, हवाई अड्डों तथा औद्योगिक समूह क्षेत्रों का विस्तार किया है, उसने राज्य की आर्थिक छवि को परिवर्तित करना आरंभ कर दिया है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के जापान सहित अन्य प्रमुख वैश्विक वाहन विनिर्माता देशों के साथ हुए समझौते केवल निवेश आकर्षित करने का प्रयास नहीं हैं। इनके पीछे उत्तर प्रदेश की वह दीर्घकालिक रणनीति है, जो राज्य को केवल असेंबल इकोनमी से आग ले जाते हुए समेकित निर्माण व्यवस्था में रूपांतरित करना चाहती है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र इस परिवर्तन के सबसे बड़े प्रतीक बन चुके हैं। एक समय यह क्षेत्र केवल आवासीय विस्तार और भू-संपदा के लिए चर्चित था, किंतु आज यहां इलेक्ट्रानिक उपकरण, ऊर्जा संचयन प्रणाली, वाहन कलपुर्जे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स-ईवी जैसे उद्योग तीव्र गति से विकसित हो रहे हैं। इस संपूर्ण परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गुजरात को समुद्री बंदरगाहों का लाभ प्राप्त हुआ, तमिलनाडु को चेन्नई बंदरगाह ने सामर्थ्य प्रदान की।

पिछले एक दशक में नीति का फोकस अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर की ओर बढ़ा है। इससे परिवहन सुविधाएं बढ़ी हैं, क्षेत्रीय असमानताएं कम हुई हैं, निवेश आकर्षित हो रहे हैं और संतुलित आर्थिक विकास सुनिश्चित हुआ है। बड़े बंदरगाह, औद्योगिक गलियारे और ऊर्जा अवसंरचना पश्चिमी और दक्षिणी भारत के साथ उत्तर भारत में दस्तक दे रहे हैं।

(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार और लोक-नीति विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सच्चा ज्ञान

ज्ञान अपने आप में न शुभ है, न अशुभ। वह तो अग्नि की तरह है, जिस हाथ में जाए, उसी का स्वरूप धारण कर लेता है। यदि उसे आत्मा का आलोक मिले, तो वह यज्ञ बनता है। यदि अहंकार का अंधकार मिले, तो वही दावानल बन जाता है। आज संसार में सूचनाओं का समुद्र है, परंतु चेतना की नदियां सूख रही हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में तथ्य भरते जा रहे हैं, किंतु हृदय रिक्त होता जा रहा है। परिणाम यह है कि बुद्धि तीव्र है, पर दिशा नहीं। गति प्रचंड है, परंतु गंतव्य निर्धारित नहीं।

स्पष्ट है कि विवेकविहीन ज्ञान उस तलवार के समान है, जिसे चलाना तो सीख लिया गया हो, पर यह न सीखा गया हो कि उसे कब म्यान में रखना है? ऐसा ज्ञान मनुष्य को विनम्र नहीं बनाता, बल्कि उसे अपनी ही बुद्धि का बंदी बना देता है। तब वह संसार को समझने के स्थान पर उसे नियंत्रित करना चाहता है। यही कारण है कि इतिहास में सबसे बड़े विनाश केवल अज्ञानियों ने नहीं किए। अनेक बार ऐसे विनाश का माध्यम अत्यंत शिक्षित-प्रशिक्षित लोग बने, क्योंकि उन्हें ज्ञान तो था, परंतु विवेक नदारद रहा। तथ्य अपने आप में ज्ञान नहीं होते। वे सत्य के केवल कण हैं। जिस प्रकार ईंटों का ढेर अपने आप घर नहीं बन जाता, उसी प्रकार तथ्यों का संचय अपने आप प्रज्ञा नहीं बनता। प्रज्ञा वह अदृश्य स्थापत्य है, जो तथ्यों को अर्थ देता है। प्रज्ञा का सृजन पुस्तकों से नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरने से होता है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं पढ़ पाया, उसके द्वारा पढ़ी गई हजारों पुस्तकें भी अंततः उसके अहंकार का ही विस्तार बन जाती हैं। ऋषियों ने इसलिए ज्ञान से पहले अंतःकरण की शुद्धि पर बल दिया। वे जानते थे कि अशुद्ध पात्र में अमृत भी रखा जाए, तो वह भी दूषित हो जाता है। इसलिए उन्होंने पहले मन को निर्मल करने की साधना सुझाई, फिर ज्ञान का अधिकार दिया।

ट्विंकल तोमर सिंह

जनसंख्या प्रबंधन की आवश्यकता

देवेंद्रराज सुथार

भारत के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि नहीं, बल्कि मानव संसाधन का बेहतर विकास हैं

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 146 करोड़ है और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 रह गई है, जबकि जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए 2.1 का स्तर आवश्यक माना जाता है। हालांकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में प्रजनन दर अभी प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है, जबकि केरल, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे राज्य इस स्तर से नीचे पहुंच चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत की चुनौती राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या विस्फोट नहीं, बल्कि क्षेत्रीय असमानता है।

केवल जनसंख्या का आकार किसी देश की समृद्धि तय नहीं करता। अनेक छोटे और घनी आबादी वाले देश भारत से अधिक समृद्ध हैं। दूसरी ओर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के सामने आज चुनौती घटती जन्मदर और बढ़ती वृद्ध आबादी की है। चीन को अपनी एक-संतान नीति समाप्त करने के बाद जन्मदर बढ़ाने के उपाय करने पड़े हैं। इससे स्पष्ट है कि अत्यधिक कम प्रजनन दर भी दीर्घकाल में नई आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां पैदा कर सकती है। भारत के सामने अब सबसे बड़ी उभरती चुनौती वृद्ध होती आबादी है। जन्मदर में गिरावट के साथ आने वाले दशकों में वृद्धजन का अनुपात लगातार बढ़ेगा। इसका अर्थ है कि पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, दीर्घकालिक स्वास्थ्य सेवाओं और देखभाल की मांग भी बढ़ेगी। भारत की जनसंख्या नीति का केंद्र अब केवल जन्मदर नहीं, बल्कि बदलती आयु संरचना और लोगों की गरिमापूर्ण जीवन-यात्रा होना चाहिए।

यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल और सम्मानजनक रोजगार मिले तो यही आबादी आर्थिक प्रगति का आधार बनेगी, लेकिन यदि शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर पर्याप्त नहीं हुए तो यही जनसंख्या सामाजिक और आर्थिक दबाव का कारण बन सकती है। जनसंख्या से मिलने वाला लाभ अपने आप नहीं मिलता, उसके लिए निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। भारत को आज जनसंख्या नियंत्रण नहीं, बल्कि जनसंख्या प्रबंधन की आवश्यकता है। जन्मदर पहले ही प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच चुकी है। अब वास्तविक चुनौती क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने, महिलाओं को अधिक अवसर देने, युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने तथा वृद्ध होती आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था बनाने की है। भारत के सामने आज जनसंख्या का नहीं, जनसंख्या की गुणवत्ता का प्रश्न है। यदि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और सामाजिक सुरक्षा में समय रहते निवेश करते हैं तो यही विशाल आबादी इक्कीसवीं सदी में भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय शक्ति सिद्ध होगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

फुटबाल पर दिया जाए ध्यान

गिरीश पंकज जी का आलेख 'विश्व फुटबाल में फिसड्डी क्यों हैं हम' केवल फुटबाल की दुर्दशा का विश्लेषण नहीं, बल्कि उस राष्ट्रीय मानसिकता पर तीखा प्रश्नचिह्न है, जो प्रतिभा से अधिक तात्कालिक लोकप्रियता को महत्व देती है। विडंबना यह है कि 140 करोड़ की युवा आबादी वाला भारत फुटबाल में अपनी पहचान नहीं बना पाया। इसका कारण प्रतिभाओं की कमी नहीं, बल्कि दृष्टि का अभाव है। तमाम ऐसे बच्चे हैं, जिनके पैरों में विश्व विजेता बनने का हुनर है, लेकिन उनके पास न गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण है, न पोषण, न संसाधन और न ही भविष्य का भरोसा। स्मरण रहे कि खेल चरित्र गढ़ते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, नेतृत्व पैदा करते हैं और राष्ट्र के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देते हैं। जिस देश में खेल संस्कृति मजबूत होती है, वहां युवाओं की ऊर्जा सकारात्मक दिशा पाती है। अब समय आ गया है कि प्रत्येक जिले में विश्वस्तरीय फुटबाल अकादमियां स्थापित हों, विद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं को औपचारिकता नहीं, अपितु प्रतिभा चयन का आधार बनाया जाए और खिलाड़ियों के चयन में केवल योग्यता ही अंतिम कसौटी हो। जिस दिन यह परिवर्तन आ गया, उस दिन भारत को विश्व फुटबाल में भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकेगा।

बिमलेश कुमार सिंह चौहान, लखनऊ

वीआइपी दर्शन का औचित्य

मंदिर में भगवान की दृष्टि में सभी श्रद्धालु समान हैं। वहां न कोई राजा होता है, न रंक। न कोई छोटा होता है, न बड़ा। न अमीर, न गरीब। भगवान के सामने सब बराबर होते हैं। ईश्वर अमीर-गरीब नहीं देखते वे तो भक्ति और श्रद्धा के भूखे होते हैं। एक अमीर के बराबर ही गरीब भी श्रद्धावान हो सकता है। हमारा संविधान भी सभी नागिरकों को समान अधिकार की बात करता है। फिर भगवान के घर में हम भेदभाव करने वाले नियम क्यों बनाते हैं। फिर वीआइपी दर्शन की व्यवस्था क्यों? इससे लोगों में हीनभावना पैदा होती है। वीआइपी दर्शन की यह व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। जिस प्रकार एक सामान्य श्रद्धालु कतार में खड़े होकर दर्शन की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार चाहे कोई कितना भी साधन-संपन्न या विशिष्ट व्यक्ति क्यों न हो, उसे भी उसी व्यवस्था के अनुसार दर्शन करने चाहिए। इसी से उन्हें लाभ होगा। भगवान के घरों में ऐसे 'चोर दरवाजों' को बंद कर देना चाहिए। हां, जो श्रद्धालु दिव्यांग या बुजुर्ग हैं, उन्हें विशेष प्राथमिकता देते हुए निःशुल्क और सुगम दर्शन की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जिस प्रकार कोई वीआइपी दर्शन व्यवस्था नहीं है, उसी प्रकार की व्यवस्था देश के सभी मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर भी लागू होनी चाहिए। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के प्रभावी प्रबंधन के लिए अन्य सभी तार्किक और व्यावहारिक उपाय अपनाए जाने चाहिए, ताकि सभी श्रद्धालुओं को बिना अनावश्यक परेशानी के दर्शन का अवसर मिल सके।

हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन

इंजीनियरिंग संस्थानों का बंद होना

एआइसीटीई द्वारा देश में 58 इंजीनियरिंग संस्थाओं को बंद करना उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए चिंताजनक है। इंजीनियरिंग शिक्षा औद्योगिक विकास की आधारशिला है। इतने इंजीनियरिंग कालेजों का बंद होना यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि और नामांकन में गिरावट आ रही है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की बढ़ती फीस, रोजगार को लेकर अनिश्चितता, प्रवेश एवं मान्यता संबंधी जटिल नियम इसके प्रमुख कारण हैं। एआइसीटीई और सरकार को इस स्थिति की गंभीर समीक्षा करनी चाहिए। उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप, छात्रवृत्ति, कम फीस तथा बेहतर प्लेसमेंट व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो तकनीकी शिक्षा का यह संकट देश के औद्योगिक विकास और कुशल मानव संसाधन निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

हेमंत कुमार, हवाई नगर, रांची

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

10 करोड़ से अधिक सक्रिय एआइ यूजर हैं भारत में, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े एआइ बाजारों में से एक बनाते हैं।

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था टेली परफार्मेंसेज से संबद्ध

आजकल

सामने आती एआइ की सीमा

एआइ टूल्स अभी इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि वे इंसानी दिमाग की जगह ले सकें। रणनीतिक सोच, संकट प्रबंधन, रचनात्मकता, मानवीय संवेदना और जटिल समस्याओं के समाधान में ये पूरी तरह विफल हैं। यहां तक कि एक अच्छी साहित्यिक रचना उनके वश की बात नहीं है। इसी कारण जिन कंपनियों ने जल्दबाजी में इंसानी प्रतिभाओं को हटाकर पूरी तरह से आटोमेशन पर भरोसा किया, उनके संचालन में गंभीर दिक्कतें आ रही हैं। फोर्ड द्वारा अपने कर्मचारियों को वापस बुलाने की घटना इसका ताजा उदाहरण है

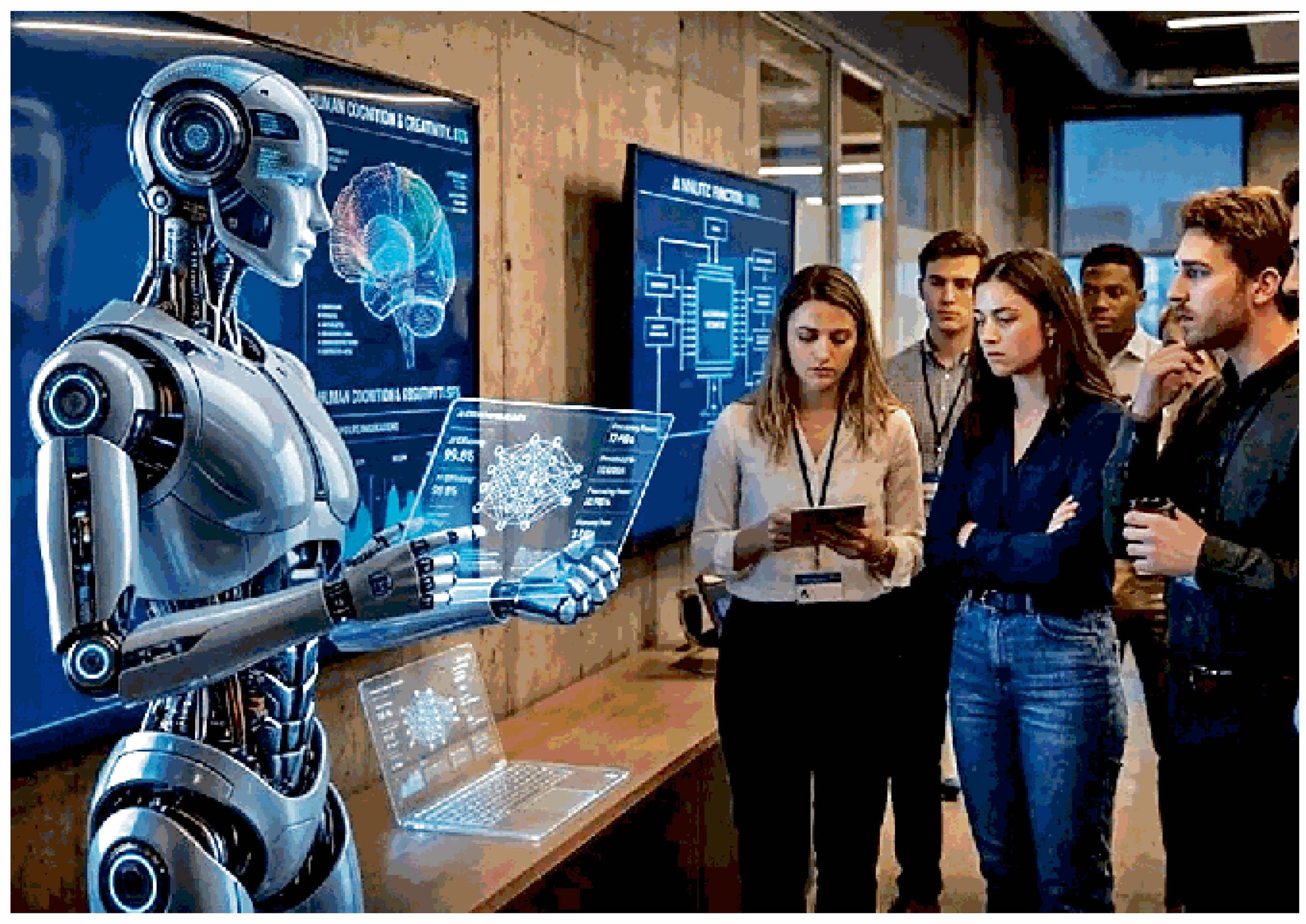

एआइ का अच्छी तरह उपयोग करना सीखें कर्मचारी। प्रतीकात्मक

अमेरिकी कार कंपनी-फोर्ड अपने 300 उन अनुभवी कर्मचारियों को नौकरी पर वापस बुला रही है, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के समर्थक डेवलपरों के कहने से निकाल दिया था। इन विशेषज्ञों ने एआइ को अपनाने से लागत में कमी और उत्पादकता में बढ़ोतरी का जो सपना दिखाया था, कंपनी के लिए वह एक बुरा अनुभव साबित हुआ, लेकिन फोर्ड जैसी मिसालें दुनिया में अपवाद ही हैं। इसके उलट तकनीकी क्रांति के इस दौर में वैश्विक कारपोरेट जगत से आ रही खबरें एक विरोधाभास और भय का वातावरण तैयार कर रही हैं। पिछले कुछ ही अरसे में एमेजान, मेटा, माइक्रोसाफ्ट, ओरेकल और सेल्सफोर्स जैसी कई दिग्गज कंपनियों ने अपने हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। नौकरियों में इस छंटनी के लिए जो प्रमुख तर्क इनके काम आ रहा है, वह यह है कि एआइ के आगमन और इसके कारण कार्यक्षमता में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के कारण कर्मचारियों की फौज की जरूरत नहीं है। वे बड़े गर्व से निवेशकों के सामने घोषणा कर रही हैं कि एआइ टूल्स ने उनके वर्कफ्लो को कुशल बना दिया है, जिससे अब उन्हें पहले जितने मानव श्रम की आवश्यकता नहीं रह गई है। जैसा कि कुछ ही समय पहले फोर्ड ने एआइ को अपनाते समय कहा था।

एआइ वाशिंग का दौर: क्या सच में एआइ टूल्स ने कंपनियों की लागत में भारी कमी ला दी है या उत्पादकता में ऐसी बढ़ोतरी हुई है, जैसी मानव श्रम के चलते मुमकिन नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि कंपनियां इस बारे में पूरा सच नहीं बताना चाहती हैं। कहीं-कहीं तो यह दावा किया जा रहा है कि चूंकि अभी एआइ को अपनाने की लागत ज्यादा है, इसलिए हकीकत का अंदाजा अगले कुछ वर्षों बाद लगेगा। ऐसे दौर में जब कंपनियों के लिए हर साल घाटे-मुनाफे का आकलन करना जरूरी होता है, ताकि उनका संचालन सही ढंग से होता रहे हैं, तब लग रहा है कि कुछ कंपनियां नौकरियों में कटौती के बहाने खोज रही हैं। उनकी इस पूरी कवायद के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छिपा है जिसे वे दुनिया और अपने निवेशकों से छुपाना चाहती हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों और तकनीकी विश्लेषकों के बीच एक नया शब्द 'एआइ वाशिंग' तेजी से प्रचलित होने लगा है। इस शब्द को गढ़ने का तर्क यह है कि जिस तरह कुछ वर्ष पहले कंपनियां खुद को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने के लिए 'ग्रीन वाशिंग' का सहारा लेती थीं, उसी तरह आज अपनी प्रबंधकीय विफलताओं, वित्तीय संकट, गलत व्यावसायिक रणनीतियों और अंधाधुंध नियुक्तियों के फैसलों को छिपाने के लिए एआइ को एक ढाल बनाया जा रहा है।

घाटे का सच छिपाने की कोशिश: यह दावा वैश्विक स्तर पर रोजगार के आंकड़े जुटाने वाली संस्था 'चैलेंजर, ग्रे एंड क्रिसमस' के हालिया आंकड़ों की रोशनी में सच ही लगता है। पिछले साल बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने आधिकारिक तौर पर करीब 54-55 हजार नौकरियों में कटौती के लिए एआइ को जिम्मेदार ठहराया था। साल 2026 की शुरुआत होते ही यह आंकड़ा डराने वाली रफ्तार से बढ़ा है। केवल जनवरी 2026 के महीने में ही अमेरिकी नियोक्ताओं ने एक लाख से अधिक छंटनियों की घोषणा की, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर एआइ के खाते में डाल दिया गया। सवाल है कि आखिर कुछ कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं? इसके पीछे का अर्थशास्त्र बेहद सीधा और कारपोरेट लालच से प्रेरित लगता है। यदि कोई कंपनी सालाना बैठक या शेयर बाजार में यह घोषणा करती है कि हमारा मुनाफा घट रहा है या हमारी वित्तीय स्थिति खराब है, इसलिए हम 10 हजार कर्मचारियों को निकाल रहे हैं तो बाजार में उस कंपनी के शेयर औंधे मुंह गिर जाते हैं। साथ ही उस कंपनी के निवेशकों को लगता है कि कंपनी डूब रही है। इसके उलट अगर उसी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कहता है कि हम भविष्य की अत्याधुनिक तकनीक एआइ को अपना रहे हैं और अपने कार्यबल को सुव्यवस्थित (स्ट्रीमलाइन) कर रहे हैं, ताकि हमारी उत्पादकता और मार्जिन बढ़ सके तो शेयर बाजार उस कंपनी का स्वागत तालियों से करता है। निवेशकों को लगता है कि कंपनी भविष्य की तैयारी कर रही है और आने वाले दिनों में इसका मुनाफा कई गुना बढ़ने वाला है। नतीजतन कर्मचारियों की छंटनी के बावजूद कंपनी के शेयरों की कीमतें बढ़ जाती हैं। यह एआइ वाशिंग का असली खेल है, जहां मानवीय त्रासदी को तकनीकी नवाचार के रंगीन चश्मे से दिखाकर कारपोरेट मुनाफे की इमारत खड़ी की जा रही है।

महामारी के दौर की ओवर-हायरिंग का सच: कोविड-19 महामारी (2020-2022) के दौरान पूरी दुनिया घरों में कैद हो गई थी। डिजिटल सेवाओं, ई-कामर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और वीडियो कांफ्रेंसिंग की मांग में रातों-रात अप्रत्याशित उछाल आया था। उस दौर में टेक कंपनियों ने बिना किसी दीर्घकालिक योजना के अंधाधुंध नियुक्तियां (ओवर-हायरिंग) कीं। उन्हें लगा कि इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का यह दौर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जैसे ही दुनिया पुराने ढर्रे पर लौटी और जनजीवन सामान्य हुआ, डिजिटल सेवाओं की मांग सामान्य स्तर पर आ गई। ब्याज दरें बढ़ने लगीं और कंपनियों पर लागत कम करने का भारी दबाव आ गया। अब सवाल यह था कि इन अतिरिक्त कर्मचारियों का क्या किया जाए? यदि कंपनियां अपनी गलती मानतीं तो नेतृत्व पर सवाल उठते। ऐसे में वर्ष 2022 के अंत में लांच हुए जेनरेटिव एआइ (मुख्यतः चैटजीपीटी, जेमिनी) ने इन कंपनियों को बचाव का एक सटीक रास्ता दे दिया। इस तरह जो छंटनियां असल में महामारी के दौर की गलतियों को सुधारने और लागत कम करने के लिए की जा रही हैं, उन्हें एआइ-संचालित पुनर्गठन का नाम दे दिया गया है।

इंसानों की जगह छीनने के तर्क की हकीकत: एआइ की वर्तमान क्षमताएं और कंपनियों के दावे आपस में मेल नहीं खाते। फारेस्टर की 'फ्यूचर आफ वर्क' रिपोर्ट के अनुसार, एआइ के नाम पर की जा रही छंटनियों में से 50 प्रतिशत से अधिक को आने वाले समय में कंपनियों को चुपचाप वापस लेना पड़ेगा। फोर्ड द्वारा अपने कर्मचारियों को वापस बुलाने की घटना इसका ताजा उदाहरण है। इसकी वजह यही है कि कई कंपनियों ने हवा-हवाई दावों के आधार पर अपने अनुभवी कर्मचारियों को निकाल तो दिया, लेकिन बाद में उन्हें अहसास हुआ कि एआइ टूल्स अभी इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि वे जटिल निर्णय लेने वाले इंसानी दिमाग की जगह ले सकें। एआइ निश्चित रूप से कोडिंग के बुनियादी ढांचे तैयार करने, ईमेल ड्राफ्ट करने, डाटा का संकलन करने या शुरुआती स्तर के कस्टमर केयर या कस्टमर सपोर्ट जैसे कार्यों को तेजी से कर सकती है, लेकिन रणनीतिक सोच, संकट प्रबंधन, रचनात्मकता, मानवीय संवेदना और जटिल समस्याओं के समाधान में यह आज भी पूरी तरह विफल है। यहां तक कि एक अच्छी साहित्यिक रचना उसके वश की बात नहीं है। एक सामान्य लेख के मामले में भी यह फर्क साफ दिख जाता है कि उसे मशीन ने लिखा है या अनुभवी लेखक ने। इस संबंध में फारेस्टर की रिपोर्ट कहती है कि जिन कंपनियों ने जल्दबाजी में इंसानी प्रतिभाओं को हटाकर पूरी तरह से आटोमेशन पर भरोसा किया, उनके संचालन में गंभीर दिक्कतें आ रही हैं।

डाटा सेंटर बनाम मानव संसाधन: आज तकनीकी उद्योग में एक और गंभीर संकट चल रहा है। कई कंपनियां वास्तव में अपने वित्तीय संसाधनों का रुख मोड़ रही हैं। ओरेकल, माइक्रोसाफ्ट और मेटा जैसी कंपनियां इस समय एआइ की इस होड़ में बने रहने के लिए महंगे एआइ चिप्स (जैसे एनवीडिया के जीपीयू), विशाल डाटा सेंटर्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर खरबों डालर खर्च कर रही हैं। हमारे देश पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी प्रतिभा प्रदाता यानी मानव संसाधन देने वाला देश है। हमारी आइटी कंपनियां (जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो) मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप के कारपोरेट जगत के आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स पर निर्भर हैं। जब पश्चिमी देश एआइ का बहाना बनाकर अपनी लागत कम करते हैं तो वे भारत को दिए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के बजट में भी कटौती करते हैं। भारत में भी बैक-आफिस आपरेशंस, डाटा एंट्री और बुनियादी साफ्टवेयर टेस्टिंग से जुड़े युवाओं पर इसका असर दिख रहा है। हालांकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में राहत की बात यह है कि भारतीय कंपनियां इस मामले में अधिक सतर्क और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना रही हैं। वे कर्मचारियों को निकालने के बजाय उन्हें अपस्किल (एआइ टूल्स का उपयोग सिखाने) पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

सह-अस्तित्व ही एकमात्र रास्ता

एआइ कोई मसीहा या खलनायक नहीं है, केवल एक उपकरण है। एआइ कोई रिप्लेसमेंट प्रोसेस (प्रतिस्थापन प्रक्रिया) नहीं है, बल्कि यह एक को-एग्जिस्टेंस प्रोसेस (सह-अस्तित्व प्रक्रिया) है। कंपनियों को यह समझना होगा कि जब वे अपने कर्मचारियों में डर का माहौल पैदा करती हैं तो वे उनमें अपनी संस्था के प्रति ईमानदार, निष्ठा और नवाचार की क्षमता से हाथ धो बैठती हैं। कोई भी डरा हुआ कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। ऐसे में एआइ को एक सहयोगी टूल के रूप में देखा जाना चाहिए। यहां एक सबक खुद कर्मचारियों के लिए भी है। इस अनिश्चित दौर में कर्मचारियों के लिए एकमात्र सुरक्षा कवच 'लगातार सीखना' यानी अपस्किलिंग है। लोगों को एआइ से डरने के बजाय, एआइ का उपयोग करने में महारत हासिल करनी होगी। एआइ की दुनिया में यह एक सूत्रवाक्य बन गया है कि एआइ शायद आपकी नौकरी न ले, लेकिन जो व्यक्ति एआइ का इस्तेमाल करना जानता है, वह आपकी नौकरी जरूर ले सकता है।

-अभिषेक कुमार सिंह

खरी-खरी

एक अनार, सौ बीमार

सुरेश रायकवार

देश में निजी और सरकारी क्षेत्र को मिलाकर कुल नौकरियां 15 करोड़ के लगभग हैं, जिनमें से केंद्र और राज्य सरकारों की नौकरियां अनुमानतः 1.5 करोड़ के आसपास हैं। इसीलिए देखने में आता है कि जब एक मामूली से चपरासी और सिपाही की भर्ती का विज्ञापन निकलता है तो एक-एक पोस्ट के लिए हजारों उम्मीदवार आवेदन करते हैं।

अर्थशास्त्र का एक नियम है कि जो वस्तु मात्रा में जितनी कम होगी बाजार में उसकी मांग उतनी ही अधिक होगी। हमारे देश में उपलब्ध सरकारी नौकरियों पर भी यही नियम लागू होता है। सरकारी नौकरी का महत्व इसलिए भी अधिक होता है कि उसमें वेतन भले ही कम हो, किंतु ऊपर की कमाई आपकी क्षमता अनुसार रहती है। तभी तो कभी-कभार लोकायुक्त के छापों में चपरासी और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के यहां से भी करोड़ों रुपये जब्त होते हैं। सरकारी नौकर का समाज में मान सम्मान और रुतबा अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसीलिए सरकारी नौकरी वाले दूल्हों की मांग भी अधिक होती है। हमारी मानसिकता ही कुछ ऐसी हो गई है कि हम अपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, यात्रा के लिए प्राइवेट बसें चाहिए, हवाई यात्रा के लिए प्राइवेट कंपनी के विमान चाहिए और बीमार होने पर अपना इलाज भी प्राइवेट अस्पताल में ही करवाना चाहते हैं, किंतु देश के हर बेरोजगार को नौकरी केवल और केवल सरकारी चाहिए।

स्वतंत्रता के बाद पढ़ाई-लिखाई के कारण देश के युवाओं का स्टैंडर भी थोड़ा ऊंचा हो गया है, इसलिए वे न तो कोई पैतृक धंधा करना चाहते हैं, ना ही खेती। अब यह तो हमारी सरकारों की ही गलती मानी जाएगी ना कि उन्होंने पहले तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई और ऊपर से युवाओं को शिक्षा ऋण दे-देकर ऊंची पढ़ाई करवा दी। अब पढ़ाई के बाद भी क्या कोई खेती, पुश्तैनी धंधा करेगा। हमारे देश में बेरोजगारी के इस भीषण-काल में संभवतः बेरोजगारों को धैर्य बंधाने के लिए ही देश के एक महान संत लिख गए हैं- अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम। दास मलूका कह गए, सबके दाता राम।

पोस्ट

अकाली दल प्रतिबंधित फिल्म सतलुज के सार्वजनिक प्रदर्शन में सक्रिय है। पंजाब में चुनाव से पहले यह फिल्म भी सियासी मुद्दा बन रही है।
पल्लवी घोष@_pallavighosh

हमें अपने स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली पर दोबारा विचार करना होगा। ये संस्थाएं नए भारत की आकांक्षाओं के साथ कदमताल नहीं कर पा रहीं। हर चुनौती के आगे वे घुटने टेक देती हैं। राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार इसके लिए दोषी हैं। निगम-नगरपालिका-पंचायत के कुछ कार्यों का निजीकरण किया जाए।
अखिलेश शर्मा @akhileshsharma1

जिन स्थानीय निकाय संस्थाओं की वैचारिक और प्रशासनिक नींव ही उधार की हो, उनसे भारतीय समाज की स्वाभाविक आवश्यकताओं के अनुरूप संवेदनशीलता की अपेक्षा कठिन है। इसका समाधान केवल निजीकरण करने में नहीं, संस्थागत भारतीयकरण और वास्तविक विकेंद्रीकरण में भी निहित है। डा. मीना कुमारी@DrMeenaJangid

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम समाप्त होने का कारण ईरान का रवैया भी है?

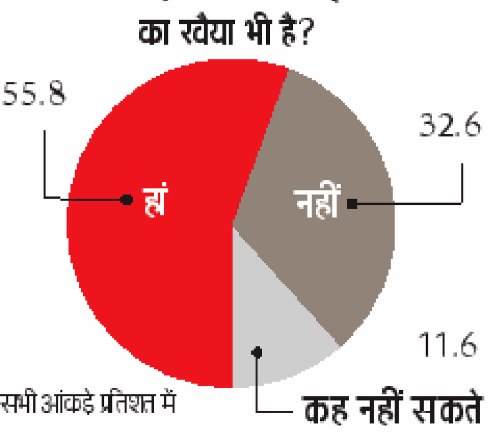

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या कोच गौतम गंभीर की प्रयोगधर्मिता भारतीय टीम पर भारी पड़ रही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

रहे सिखाते आज तक वे औरों को दांव,
पीके जी खुद लड़ रहे अबकी बार चुनाव।
अबकी बार चुनाव नाव आती तैरानी,
अब होगा मालूम नदी में कितना पानी!
बड़े-बड़े उस्ताद यहां गच्चा खा जाते,
जो जीवन भर दांव सभी को रहे सिखाते!!

-ओम प्रकाश तिवारी

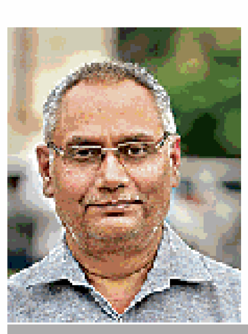

अरुण अशेष
उप राजनीतिक संपादक, बिहार

बिहार डायरी

जनजीवन को आसान बनाने की चुनौती

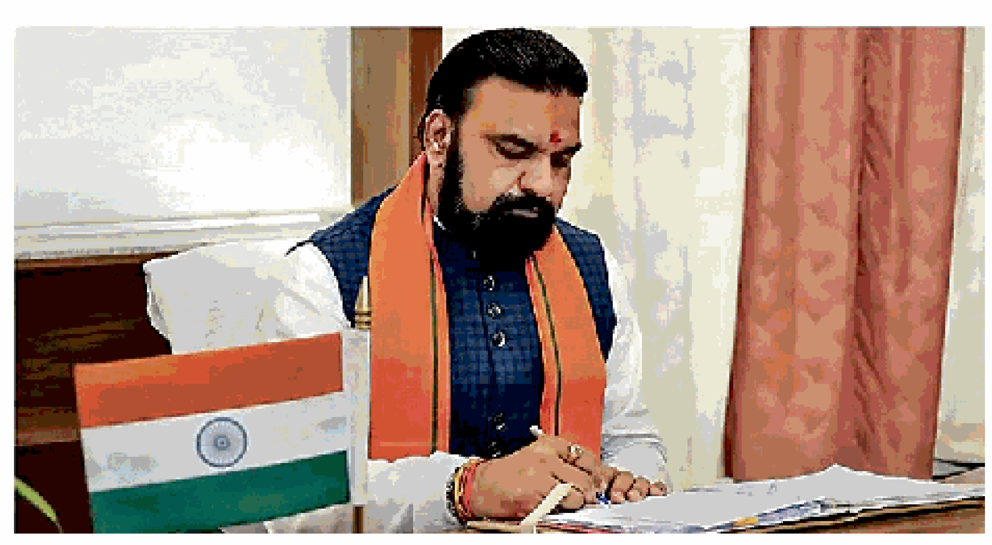

नीतीश कुमार के सात निश्चय को आगे बढ़ा रहे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। फाइल

राज्य सरकार आम लोगों के जीवन को आसान बनाने का प्रयास कर रही है। नीतीश कुमार की सरकार ने विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं को सात निश्चय के रूप में सूत्रबद्ध किया था। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार इस पर अमल कर रही है। सात निश्चय (तीन) का एक सूत्र है-आम लोगों के जीवन को आसान बनाया जाए। निश्चित रूप से यह बहुत आसान कार्यभार नहीं है। एक बड़ी कठिनाई सहज यातायात के मोर्चे पर है। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से बहुत सड़कें बनीं। पुल-पुलियों का निर्माण हुआ। पूर्ववर्ती सरकार के समय में कहा जाता था कि बिहार में यात्रा किलोमीटर के हिसाब से नहीं, घंटे के हिसाब से तय होती है। मतलब 10 किलोमीटर की यात्रा तय करने में भी आपको घंटों लग सकते हैं। यह परिदृश्य बदल तो गया है, लेकिन अवरोध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। पहले दावा किया गया कि राज्य के किसी हिस्से से राजधानी की यात्रा अधिकतम छह घंटे में पूरी हो सकती है। बाद में इसे पांच घंटा किया गया। अब इसे और कम करने का दावा किया जा रहा है।

यह सही है कि राज्य के किसी हिस्से से आप पांच-छह घंटे में राजधानी पटना की सीमा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके बाद राजधानी स्थित गंतव्य तक आप कितनी देर में पहुंचेंगे, इसकी कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है। यह दशा पटना में प्रवेश करने वाले हरेक द्वार की है। आश्चर्य की बात यह है कि बीते 15-20 वर्षों में इस समस्या का निदान नहीं हो सका। सरकार इस दिशा में नए सिरे से प्रयास कर रही है।

अभी राज्य कैबिनेट ने हाई-स्पीड रेल आधारित ट्रांजिट सेवा को स्वीकृति दी है। लक्ष्य यह है कि राजधानी में भीड़ कम हो। क्योंकि पटना से 20-25 किलोमीटर रहने वाले लोग भी नौकरी या अन्य कारोबार के लिए यहीं पर निवास करते हैं। यह उनका शौक नहीं है। मजबूरी है। अगर वे अपने घर से आवागमन करें तो कभी समय पर कार्यस्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे। कारोबारी या सेवक को कार्यस्थल से अधिक समय यात्रा पर व्यय करना होगा। हाई-स्पीड रेल आधारित ट्रांजिट सेवा का लक्ष्य यह है कि 20 से 70 किलोमीटर की परिधि में बसे लोग घंटे-डेढ़ घंटे में पटना पहुंच जाएं। काम करें और शाम को घर लौट जाएं।

अभी हालत यह है कि राजधानी में रहने वाले लोगों को कभी-कभी जाम के कारण 10-15 किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटा-डेढ़ घंटा लग जाता है। वस्तुतः पटना के कई ऐसे इलाके हैं, जहां आज भी दूरी किलोमीटर के बदले घंटे में तय होती है। बिहार की सड़कों पर मची अफरातफरी का सबसे बड़ा कारण यह है कि राज्य के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दिहाड़ी-सबके लिए पटना ही आना पड़ता है। राज्य में नौ प्रमंडलीय मुख्यालय हैं, लेकिन पटना को छोड़ कर किसी प्रमंडलीय मुख्यालय में इलाज ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिस पर लोग विश्वास करें। दूसरे मेडिकल कालेज अस्पतालों और सदर अस्पतालों से रोगियों को सीधे पटना रेफर कर दिया जाता है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने हर रोगी को पटना के बड़े सरकारी अस्पतालों में रेफर करने की प्रवृत्ति पर आपत्ति प्रकट की है। रेफर करने वाले डाक्टरों को कार्रवाई की भी धमकी दी है। रेफर करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का निर्देश देने से पहले सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि दूसरे अस्पतालों में इलाज की समुचित व्यवस्था है या नहीं? सच यह है कि गरीब-गुरबे ही सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। संपन्न लोगों का हाल यह है कि सरकार के मंत्री और अधिकारी भी सर्दी-खांसी तक के इलाज के लिए बड़े निजी अस्पतालों में एडमिट होते हैं।

शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं की चर्चा इन दिनों कोचिंग संस्थानों से शुरू होती है। इसके लिए भी छात्र-छात्राओं को पटना ही आना पड़ता है। पढ़े-लिखे लोग ही नहीं, दैनिक मजदूर भी दिहाड़ी के लिए पटना का रुख करते हैं। हालांकि सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि नागरिकों को जरूरी सेवाएं उनके निवास स्थल के नजदीक ही मिल जाएं। यह हो जाए तो जीवन आसान बनाने का सूत्र सफल हो जाएगा।

आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए बहुत अधिक धन की जरूरत है। राज्य सरकार के लिए संतोष का विषय यह है कि उसे केंद्र सरकार से पूरी मदद मिल रही है। वह आंतरिक संसाधनों से धन जुटाने का भी प्रयास कर रही है। वित्तीय संस्थाएं उदारतापूर्वक कर्ज दे रही हैं। आशा की जा सकती है कि आने वाले दिनों में राज्य आय के कुछ नए स्रोतों का भी सृजन करेगा। आम लोग तो विश्वास कर रहे हैं कि उनकी दैनिक कठिनाइयां दूर करने का प्रयास हो रहा है।

मंथन

श्री राम शा
shriramshaw@nda.jagran.com

भारत-जापान-सेशेल्स की साझेदारी

यदि पूर्व में जापान भारत का एक मजबूत आर्थिक और रणनीतिक स्तंभ है, तो दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित सेशेल्स भारत की 'सागर' नीति का केंद्रीय प्रहरी है

प्रगाढ़ होते जापान-भारत रिश्ते। फाइल

आज हिंद-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक कूटनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है। इस बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत किसी मूक दर्शक की भूमिका में नहीं, बल्कि एक सशक्त रणनीतिक और आर्थिक धुरी के रूप में उभर रहा है। पूर्व में उगते सूरज की भूमि जापान से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के रणनीतिक प्रहरी सेशेल्स तक, भारत की कूटनीति आज असीम, भविष्योन्मुखी और व्यावहारिक परिणामों पर आधारित है। यह तथ्य इन दोनों देशों के साथ भारत के प्रगाढ़ होते संबंधों के हर उस महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है, जो आने वाले समय में विश्व राजनीति की दिशा तय करेंगे।

जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की हालिया भारत यात्रा को केवल एक नियमित राजनयिक जुड़ाव के रूप में नहीं देखा जा सकता। आज के समय में जब वैश्विक स्तर पर सुरक्षा चिंताएं, आर्थिक अनिश्चितता और तकनीकी प्रतिस्पर्धा आपस में जुड़े हुए हैं, तब टोक्यो और नई दिल्ली हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। जापान अब भारत को केवल एक औपचारिक या पारंपरिक भागीदार के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे एशिया में एक रणनीतिक और आर्थिक स्थिरता के आधार के रूप में मान्यता देता है। दोनों देशों का साझा उद्देश्य किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता को रोकना, खुलेपन को बनाए रखना और एक स्थिर क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना है। यह कूटनीति अब अमूर्त विचारों से आगे बढ़कर ठोस परिणामों पर टिकी है। जापान की मुक्त और खुली हिंद-प्रशांत रणनीति अब केवल एक दृष्टिकोण नहीं रही, बल्कि वैश्विक चुनौतियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के विखंडन का मुकाबला करने के लिए एक क्षेत्रीय ढांचा बन चुकी है। बहरहाल भारत और जापान के कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर दोनों देशों ने वर्ष 2027 को 'भारत-जापान साझा क्षितिज वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की है।

यदि पूर्व में जापान भारत का एक मजबूत आर्थिक और रणनीतिक स्तंभ है, तो दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित सेशेल्स भारत की 'सागर' (सागर-क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) नीति का केंद्रीय प्रहरी है। राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सेशेल्स दौरा रणनीतिक, आर्थिक और मानवीय कूटनीति का बेजोड़ उदाहरण बनकर उभरा है। सेशेल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर मोदी का वहां 'गेस्ट आफ आनर' बनना भारत के प्रति उनके सर्वोच्च सम्मान को दर्शाता है। पश्चिम एशिया के संकट के कारण सेशेल्स वर्तमान में जिन बुनियादी ढांचागत और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, भारत ने एक विश्वसनीय मित्र के रूप में उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। भारत ने सेशेल्स की समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को अभूतपूर्व मजबूती दी है। सेशेल्स डिफेंस फोर्स को एक फास्ट पेट्रोल वेसल (तेज गश्ती पोत), 10 उपयोगिता वाहन और पांच लेजर रेडियल क्लास नावें सौंपी गईं। सेशेल्स कोस्ट गार्ड के जहाज 'पीएस जोरोएस्टर' की भारत में सफल मरम्मत का कार्य संपन्न हुआ। सेशेल्स के डोर्नियर विमान को अत्याधुनिक ग्लास काकपिट के साथ अपग्रेड किया गया। सेशेल्स आधिकारिक रूप से भारत की पहल पर बने 'आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन' में शामिल हो गया है। दोनों देशों के बीच अपराधियों और भगोड़ों पर नकेल कसने के लिए एक प्रत्यर्पण संधि पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

मोदी की इस यात्रा का सीधा लाभ सेशेल्स के आम जनमानस तक पहुंचा है। नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया इंटरनेशनल और सेंट्रल बैंक आफ सेशेल्स के बीच हुए समझौते के तहत अब सेशेल्स में भारत का यूपीआइ डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचा लागू किया जाएगा। मेसर्स एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड और सेशेल्स के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच हुए समझौते के तहत भारत की प्रसिद्ध 'जनऔषधि योजना' के माध्यम से सेशेल्स को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं तथा चिकित्सा सामग्री निर्यात की जाएगी। सेशेल्स को केवल एक छोटे देश के रूप में मत देखिए, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति को देखिए जो इसे एशिया, मध्य पूर्व और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को जोड़ने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक हब बनाती है। भारतीय व्यवसायी सेशेल्स का उपयोग 'अफ्रीका के प्रवेश द्वार' के रूप में कर सकते हैं और एक बहुत बड़े क्षेत्रीय बाजार तक अपनी पहुंच बना सकते हैं।

भारत आज वैश्विक मंच पर एक अत्यंत परिपक्व, संवेदनशील और सुदृढ़ शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। अपनी इस त्रि-आयामी सोच - व्यक्तिगत जुड़ाव, रणनीतिक दृढ़ता और वैश्विक लोक-कल्याण के बल पर भारत पूर्व से लेकर दक्षिण तक वैश्विक शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि का सबसे मजबूत स्तंभ बन गया है।

पहली तिमाही में इंडियन बैंक का लाभ 10 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) तिमाही के दौरान 3,273 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। यह पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 2,973 करोड़ रुपये के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा है। बैंक ने रेग्युलेटरी फाइलिंग में बताया कि बीती तिमाही के दौरान उसकी कुल आय 20,724 करोड़ रुपये रही है, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 18,721 करोड़ रुपये थी। बीती तिमाही में ब्याज आय भी 16,283 करोड़ रुपये से बढ़कर 18,090 करोड़ रुपये रही है। (प्रेट्र)

इलेक्ट्रानिक्स से जुड़े कलपुर्जों पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने से लागत में कमी आएगी, प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता बेहतर होगी और वैल्यू चेन में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
– अशोक चांडक, प्रेसिडेंट, इंडिया इलेक्ट्रानिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन

संसेक्स	77,569.39	▲ 827.57
निफ्टी	24,206.90	▲ 244.10
सोना प्रति दस ग्राम	₹1,48,500	▲ ₹400
चांदी प्रति किलो ग्राम	₹2,37,000	▲ ₹5,000
डालर	₹95.38	▼ ₹0.09
क्रूड प्रति बैरल	$76.07	

एक नजर में

भारत ने चीन के पाइप पर डंपिंग-रोधी शुल्क बढ़ाया

नई दिल्ली: भारत ने चीन से आयात होने वाले कुछ ट्यूब्स और पाइप्स पर जारी डंपिंग-रोधी शुल्क की अवधि को बढ़ाकर 27 जनवरी 2027 तक के लिए कर दिया है। वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, घरेलू निर्माताओं को सस्ते आयात से बचाने के उद्देश्य से डंपिंग-रोधी शुल्क की अवधि बढ़ाई गई है। भारत ने पहली बार लोहे, मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु स्टील से बने सीमलेस ट्यूब व पाइप पर 28 अक्टूबर, 2021 को पांच वर्ष के लिए डंपिंग-रोधी शुल्क लगाया था। इन उत्पादों पर 961.3 से 1,610.67 डालर प्रति टन शुल्क लगाया जा रहा है। (प्रेट्र)

विदेशी मुद्रा भंडार में 7.26 अरब डालर की वृद्धि

मुंबई: बीते सप्ताह देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 7.26 अरब डालर की बढ़ोतरी हुई है। आरबीआइ की ओर से जारी डाटा के अनुसार, तीन जुलाई को समाप्त सप्ताह में कुल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 674.19 अरब डालर रहा है। डाटा के अनुसार, पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा आस्तियों में 4.51 अरब डालर की वृद्धि हुई है और अब यह 545.578 अरब डालर हो गई हैं। इसी तरह, स्वर्ण भंडार 2.66 अरब डालर बढ़कर 105.205 अरब डालर हो गया है। (प्रेट्र)

एसबीआइ ने अपनी एएमसी की 1.42% हिस्सेदारी बेची

नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआइ ने अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) एसबीआइ फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड की 1.42 प्रतिशत हिस्सेदारी 1,655 करोड़ रुपये में बेची है। बैंक ने बताया कि यह हिस्सेदारी 574 रुपये प्रति शेयर पर बेची गई है, जो आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) मूल्य सीमा के उच्चतम स्तर के बराबर है। एसबीआइ फंड्स का 11,600 करोड़ रुपये का आइपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 14-16 जुलाई तक खुलेगा। यह पूरा आइपीओ आफर फार सेल यानी प्रमोटर शेयरों की बिक्री पर आधारित है। (प्रेट्र)

विनिवेश ने पिछले तीन वर्षों का रिकार्ड तोड़ा

अप्रैल-जून 2026 तिमाही में विनिवेश से सरकार को 20,000 करोड़ से अधिक का राजस्व मिला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में ही विनिवेश के तीन साल का रिकार्ड टूट गया। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जून माह में 20,272 करोड़ का विनिवेश किया जा चुका है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में मात्र 16,885 करोड़ तो वित्त वर्ष 2024-25 में 10,163 करोड़ का विनिवेश किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 में 16,507 करोड़ रुपये का विनिवेश हो पाया था। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार ने विनिवेश के माध्यम से 80,000 करोड़ का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में विनिवेश लक्ष्य से अधिक हो सकता है। विनिवेश के लिए केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकार को चालू वित्त वर्ष में अब तक सबसे अधिक 5,542 करोड़ की राशि कोल इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचनी से मिली है। आफर फार सेल (बिक्री पेशकश) के माध्यम से कोल इंडिया में अपनी दो प्रतिशत हिस्सेदारी सरकार ने बेची है। इसके बाद कोल इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 61.13 प्रतिशत रह गई है। एनएचपीसी में भी ओएफएस के माध्यम से सरकार ने 6.01 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है, जिससे 4357 करोड़ रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त हुए। पश्चिम एशिया संकट के कारण सब्सिडी पर दी जाने वाले खाद से लेकर गैस तक का आयात सरकार को काफी बढ़ी हुई कीमत पर करना पड़ा। इससे सरकार का अनुमान से अधिक राजस्व खर्च हो गया। इसकी भरपाई के लिए भी पहली तिमाही में विनिवेश में तेजी रही। चालू वित्त वर्ष में सरकार को विनिवेश के अलावा लाभांश राजस्व से 2025 करोड़ तो संपदा के मोनेटाइजेशन से 6,367 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

- सबसे अधिक 5,542 करोड़ की राशि कोल इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचनी से सरकारी को मिली
- विनिवेश के अलावा लाभांश राजस्व से 2025 करोड़ तो संपदा मोनेटाइजेशन से 6,367 करोड़ मिले

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में विनिवेश से मिले 2,266 करोड़ रुपये

कोल इंडिया और एनएचपीसी के अलावा अन्य पांच कंपनियों का विनिवेश चालू वित्त वर्ष में किया गया है।। इनमें सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन व कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड शामिल हैं। सेंट्रल बैंक के विनिवेश से 2,266.13 करोड़, एनएलसी इंडिया से 1223.57 करोड़, जनरल इंश्योरेंस से 3090.47 करोड़, रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन से 2081.27 करोड़ तो कोचीन शिपयार्ड से 1711 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त हुए।

कई अन्य कंपनियों में भी हिस्सेदारी कम कर सकती है सरकार

सूत्रों का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में सरकार कई अन्य सार्वजनिक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को कम कर सकती है। 68 सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों में सरकार की जो हिस्सेदारी है, उसका मूल्य 23 लाख करोड़ से अधिक है। वहीं बैंक को मिलाकर 19 सूचीबद्ध विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में सरकार की हिस्सेदारी का अनुमानित मूल्य 19 लाख करोड़ रुपये है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

जून में इक्विटी एमएफ में निवेश 26.5% बढ़ 28,973 करोड़ रहा

नई दिल्ली, प्रेट्र: भू-राजनीतिक तनाव में कमी और खुदरा निवेशकों की मजबूत भागीदारी के चलते जून में इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड (एमएफ) स्कीम 28,973 करोड़ रुपये का निवेश आया। यह पिछले महीने के मुकाबले 26.5% ज्यादा है। इस तरह, 2026 की पहली छमाही में इक्विटी स्कीम में शुद्ध निवेश 1.81 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यह 2025 की समान अवधि के 1.61 लाख करोड़ से 12 प्रतिशत ज्यादा है। जून में मासिक एसआइपी योगदान बढ़कर 31,781 करोड़ हो गया, जो मई में 30,954 करोड़ रुपये था।

एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के मुताबिक, कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में शुद्ध निकासी जून में घटकर 52,949 करोड़ रुपये रह गई, जबकि मई यह 64,131 करोड़ रुपये थी। इस तरह उद्योग का परिसंपत्ति आधार जून के आखिर में बढ़कर 82.22 लाख करोड़ हो गया, जो एक महीने पहले 81.6 लाख करोड़ था। इक्विटी श्रेणी में मिड-कैप फंड्स में सबसे ज्यादा 6,090 करोड़ का निवेश आया, इसके बाद स्मालकैप फंड्स में 5,602 करोड़ और फ्लेक्सी-कैप फंड्स में 5,231 करोड़ का निवेश हुआ। लार्ज-कैप फंड्स में 2,067 करोड़ का निवेश आया। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में जून में 3,443 करोड़ का शुद्ध निवेश आया जबकि मई में 725 करोड़ की निकासी दर्ज की गई थी। 2026 के पहले छह महीनों में गोल्ड ईटीएफ में 37,319 करोड़ का शुद्ध निवेश हुआ।

2026 की पहली छमाही में इक्विटी स्कीम में शुद्ध निवेश 12 प्रतिशत बढ़कर 1.81 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

कच्चे तेल में नरमी से सेंसेक्स 828 अंक बढ़ा

मुंबई, प्रेट्र: प्रमुख कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज, आइसीआइसीआइ बैंक और एचडीएफसी बैंक में लिवाली और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई संसेक्स 827.57 अंक चढ़कर 77,569.39 पर बंद हुआ। दिन के दौरान, एक समय यह 900.41 अंक बढ़कर 77,642.23 तक पहुंच गया था। वहीं एनएसई निफ्टी 244.10 अंक बढ़कर 24,206.90 पर बंद हुआ। विश्लेषकों के मुताबिक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के जून तिमाही के बेहतर नतीजों के बाद सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) शेयरों में आई तेजी से भी बाजार को मजबूती मिली।

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रानिक्स, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील और इन्फोसिस प्रमुख रूप से बढ़त बनाने वाली कंपनियां रहीं। देश की सबसे बड़ी आइटी सर्विस कंपनी टीसीएस के शेयर एक प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए। गुरुवार को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ 4.61 प्रतिशत बढ़कर 13,349 करोड़ रुपये हो गया था।

77,569.39 पर बंद हुआ
बीएसई का बेंचमार्क सूचकांक

244.10 अंक बढ़कर 24,206.90 पर आया एनएसई निफ्टी

2,883 शेयरों में बढ़त रही
1,377 शेयरों में गिरावट आई
174 शेयरों में कोई बदलाव नहीं

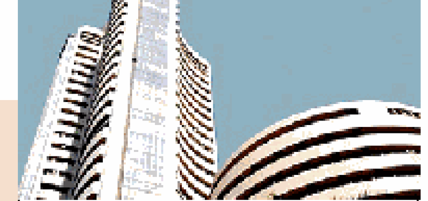

हाल की भारी बिकवाली के बाद भारतीय इक्विटी बाजारों में लगातार दूसरे सत्र में रिकवरी देखी गई और व्यापक स्तर पर खरीदारी के रुझान ने इस तेजी को सहारा दिया। टीसीएस के बेहतर नतीजों ने आइटी सेक्टर में उत्साह बढ़ाया जबकि बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में जोरदार खरीदारी के साथ मेटल, आयल एंड गैस और डिफेंस शेयरों में बढ़त ने बाजार की तेजी को और मजबूती दी।
–पोनमुडी आर, सीईओ, एनरिच मनी

सेक्टरवार तेजी (प्रतिशत में)	
रियल्टी	3.40
पीएसयू बैंक	3.26
फोकस्ड आइटी	2.29
सूचना-प्रौद्योगिकी	2.01
मेटल	1.55
सर्विसेज	1.50

अब केवल उमंग एप से ही एक्टिवेट हो सकेगा यूएएन

14470 है ईपीएफओ का हेल्पडेस्क नंबर, यहां मिलेगा हर समस्या का समाधान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने यूनिफाइड पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ को डाटाबेस कंसोलिडेशन और साफ्टवेयर अपग्रेड के बाद फिर से शुरू कर दिया गया है। नए पोर्टल में कई प्रमुख बदलाव किए गए हैं, जिनका सीधा असर ईपीएफओ के सदस्यों पर पड़ेगा। इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, वह यह है कि अब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) इस पोर्टल से न तो एक्टिवेट हो सकेगा और न ही नया यूएएन जेनरेट हो सकेगा। ईपीएफओ के बदलावों पर पढ़िए **मनोज कुमार** की रिपोर्ट...

अब ऐसे एक्टिवेट होगा यूएएन

ईपीएफओ की वेबसाइट के अनुसार, अब यूएएन को केवल उमंग एप के जरिये एक्टिवेट (सक्रिय) किया जा सकेगा। इसके अलावा, नया यूएएन नंबर भी उमंग एप के जरिये जेनरेट हो सकेगा। आइए जानते हैं यूएएन को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया

- सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एपल एप स्टोर से उमंग एप डाउनलोड करें।
- अब उमंग एप में ईपीएफओ सर्विसेज सेक्शन खोलें।
- यह यूएएन सर्विसेज थ्रू फेस आथेंटिकेशन के तहत यूएएन एक्टिवेशव विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद आधार आधारित फेस आथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
- अब स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रक्रिया पूरी करें। आपका यूएएन एक्टिवेट हो जाएगा।

पोर्टल का नया इंटरफेस भी बनाया

ईपीएफओ ने पोर्टल को अपग्रेड करने के साथ इसका इंटरफेस भी नया बनाया है। संगठन का कहना है कि इसका उद्देश्य आनलाइन सेवाओं को पहले से ज्यादा तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है। नए इंटरफेस में कई सुविधा को होम पेज पर ही लाया गया है, ताकि सदस्य सीधे इन सेवाओं का लाभ ले सकें। सभी सदस्यों और नियोक्ताओं के लिए सेवाओं के चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया है। ईपीएफओ का कहना है कि शुरुआती दो हफ्तों के दौरान सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सत्यापन जांच के साथ दावों और सेवा आग्रहों को चरणबद्ध व व्यवस्थित तरीके से प्रोसेस किया जाएगा।

क्या है उमंग एप

यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फार न्यू-एज गवर्नेंस यानी उमंग भारत सरकार का एक आल-इन-वन डिजिटल प्लेटफार्म है। इसे इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन ने डेवलप किया है। यह एप लोगों को केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारी विभागों की 1,700 से अधिक सेवाओं का लाभ एक ही जगह उठाने की सुविधा देता है। यह एप करीब 22 भाषाओं में उपलब्ध है ताकि देश का हर नागरिक इसे आसानी से समझ सके। यह एप आधार-बेस्ड वेरिफिकेशन और एन्क्रिप्टेड फार्मेट का उपयोग करता है जिससे आपका पर्सनल डाटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है।

जागरण इन्फो

राष्ट्रीय फलक

आइवीएफ क्लीनिक के लिए तैयार होंगे नए नियम

नई दिल्ली, प्रेट्र : तेजी से बढ़ रहे फर्टिलिटी सेक्टर में गड़बड़ियों की चिंताओं के बीच आइवीएफ क्लीनिक, सहायक प्रजनन तकनीक (एआरटी) क्लीनिकों और अंडाणु-शुक्राणु बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियमों व कानूनों की व्यापक समीक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति बनाई है। इसका मकसद महिलाओं के प्रजनन अधिकारों व सम्मान की रक्षा और उनकी सुरक्षा करना है। इस समिति की अध्यक्षता दिल्ली हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त जज आशा मेनन करेंगी।

आयोग ने एक बयान में कहा कि सभी एआरटी क्लीनिकों और अंडाणु-शुक्राणु बैंकों के लिए हालांकि नेशनल एआरटी एंड सरोगेसी रजिस्ट्री के तहत पंजीकरण आवश्यक है, लेकिन सिर्फ नियमों का पालन करना ही अनैतिक तरीकों को रोकने के लिए काफी नहीं रहा है। फर्टिलिटी सेक्टर में मेडिकल टूरिज्म बढ़ने से भारत के कानूनी सुरक्षा उपायों के संभावित उल्लंघन को लेकर चिंताएं भी पैदा हुई हैं। इनमें लिंग चयन को रोकने के उपाय भी शामिल हैं। आयोग के अनुसार, अलग-अलग राज्यों में इलाज के एक जैसे प्रोटोकाल नहीं होने की वजह से महिलाओं को अनावश्यक प्रक्रियाओं, देखभाल के असमान मानकों और आर्थिक शोषण से बचाने के लिए मजबूत निगरानी की आवश्यकता महसूस की गई है।

आयोग का कहना है कि समिति असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलाजी (रेगुलेशन) एक्ट-2021, सरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट-2021 और 2026 में अधिसूचित संबंधित संशोधन नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। यह सहमति, निजता और बायोलाजिकल ट्रेसिबिलिटी से जुड़े मौजूदा सुरक्षा उपायों की जांच करेगी, ऐसी नियामक व प्रक्रियात्मक कमियों की पहचान करेगी जिनसे शोषण या धोखाधड़ी हो सकती है और संस्थागत जवाबदेही मजबूत करने के लिए सुधारों की सिफारिश करेगी। समिति एआरटी क्लीनिकों और आइवीएफ क्लीनिकों के लिए एसओपी व सर्वश्रेष्ठ तरीके भी सुझाएगी ताकि पूरे सेक्टर में नैतिक इलाज के तरीकों, स्टैंडर्ड क्लीनिकल प्रोटोकाल एवं अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके। इन सुधारों का मकसद फर्टिलिटी का इलाज कराने वाली महिलाओं को प्रक्रिया के हर चरण में मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

- राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसके लिए गठित की उच्च स्तरीय समिति
- दिल्ली हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त जज आशा मेनन होंगी समिति की अध्यक्ष

प्रतीकात्मक

समिति में सदस्य : पूर्व आइपीएस अधिकारी सुंदरी नंदा, एनसीडब्ल्यू की पूर्व सदस्य अर्चना मजूमदार, एनसीडब्ल्यू की सलाहकार समिति की सदस्य डा. शिप्रा धर, वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पावनी, सफदरजंग अस्पताल के डा. सर्वेश टंडन, एम्स की स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. नीता सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता डा. नयना सहस्रबुद्धे, फेडरेशन आफ आब्सटेट्रिक एंड गायनेकोलाजिकल सोसाइटीज आफ इंडिया के डा. रजनीकांत कान्ट्रैक्टर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एआरटी डिवीजन का एक प्रतिनिधि और एनसीडब्ल्यू की वरिष्ठ समन्वयक कंचन खट्टर।

ओएनजीसी मंगलुरु में 17.5 लाख टन पेट्रोलियम का भंडार विकसित करेगी

नई दिल्ली, प्रेट्र: सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनी ओएनजीसी ने शुक्रवार को कहा, उसके निदेशक मंडल ने मंगलुरु में 17.5 लाख टन की रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण क्षमता विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे देश की आपातकालीन कच्चा तेल भंडारण क्षमता बढ़ेगी। कंपनी ने इस परियोजना की लागत और समयसीमा की जानकारी नहीं दी है।

भारत का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत आपात हालात के लिए कच्चे तेल का भंडार रखा जाता है, जिसका इस्तेमाल आपूर्ति में रुकावट या वैश्विक बाजार में कीमतों में तेजी आने पर किया जा सकता है। ये भंडार, तेल कंपनियों और रिफाइनरियों द्वारा रखे जाने वाले परिचालन स्टाक के अलावा होता है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के पहले चरण में भारत ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, कर्नाटक के मंगलुरु और पादुर में लगभग 53 लाख टन क्षमता वाली जमीन के नीचे चट्टानों में बनी गुफाएं बनाईं। इन सुविधाओं का संचालन इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड करती है। सरकार ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें पादुर सुविधा का विस्तार और ओडिशा के चांदीखोल में एक नया रणनीतिक भंडार बनाना शामिल है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक एवं उपभोक्ता देश भारत अपनी जरूरत का 88 प्रतिशत से अधिक तेल आयात करता है। ऐसे में वैश्विक तनाव और वैश्विक तेल बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच सामरिक भंडार देश की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा है।

- सरकार ने कुछ दिनों पहले ही रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के दूसरे चरण को दी है मंजूरी

हाइड्रोजन परिवहन उद्योग का भविष्य, 10 रूटों पर चल रहा ट्रायल : गडकरी

गांधीनगर, प्रेट्र: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि परिवहन उद्योग का भविष्य हाइड्रोजन है। सरकार ईंधन के तौर पर इसका ट्रायल कर रही है। ग्रेटर नोएडा-दिल्ली-आगरा, भुवनेश्वर-कोणार्क-पुरी, अहमदाबाद-वडोदरा-सूरत, साहिबाबाद-फरीदाबाद-दिल्ली, पुणे-मुंबई, जमशेदपुर-कलिंग नगर, तिरुअनंतपुरम-कोच्चि, कोच्चि-एडप्पल्ली, जामनगर-अहमदाबाद व विशाखापत्तनम-बय्यावारम समेत 10 रूटों पर ट्रायल चल रहे हैं। वह गुरुवार को गांधीनगर में 'प्रवास 5.0' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि परिवहन उद्योग का भविष्य हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन ही भविष्य का ईंधन है। हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं।" गडकरी ने आगे कहा कि उद्योग वैकल्पिक फ्यूल और बायोफ्यूल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है और भारत अपनी तकनीक और लागत के मामले में दुनिया में आगे रहेगा।

12 करोड़ लोगों को ड्रग्स के विरुद्ध 18 अगस्त को शपथ दिला सकते हैं पीएम

नई दिल्ली, आइएएनएस : पीएम नरेन्द्र मोदी 18 अगस्त को 'नशा मुक्त भारत अभियान' की छठी वर्षगांठ के मौके पर 12 करोड़ से अधिक नागरिकों को ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक शपथ दिला सकते हैं। इस देशव्यापी सामूहिक शपथ कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

मंत्रालय के संयुक्त सचिव (ड्रग रोकथाम) संदीप रेवाजी राठौड़ ने इस संबंध में कार्यान्वयन रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नशा मुक्त भारत अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप भौतिक और आनलाइन माध्यमों से देशव्यापी शपथ में तय संख्या में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना और व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई।

भोपाल में 10 साल तक कागजों में चलता रहा बीएड कालेज, होगी जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) भोपाल से संबद्ध निजी बीएड कालेजों की मान्यता और संबद्धता को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। विश्वविद्यालय से संबद्ध 127 निजी बीएड कालेजों ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन किया था। जांच में 30 कालेजों में गंभीर अनियमितताएं मिलीं। औचक निरीक्षण में विदिशा रोड स्थित श्रीराम कालेज आफ एजुकेशन का धरातल पर कोई अस्तित्व ही नहीं मिला, जबकि विश्वविद्यालय के रिकार्ड में कालेज दस वर्षों से संबद्ध है। विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने अनियमितताओं की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने का निर्णय लिया है। जांच में उन मामलों को भी शामिल किया जाएगा, जिनमें निरीक्षण बिना कालेजों की प्रोफाइल कार्यपरिषद की मंजूरी से पूर्व ही ई-पोर्टल पर ओके कर अपलोड कर दी गई।

- बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध 30 महाविद्यालयों में मिली अनियमितता
- दो का नहीं मिला अस्तित्व, कार्यपरिषद की बैठक में लिया गया जांच का फैसला

विवि से संबद्धता व निरंतरता के लिए 127 कालेजों के आवेदन आए थे। इसमें से 125 कालेजों को ईसी ने सशर्त संबद्धता दे दी थी। अब ईसी ने 116 कालेजों की जांच रिटायर जज से कराने की अनुशंसा की है। **–समर बहादुर सिंह, कुलसचिव, बीयू**

शिकायत के बाद खुला पूरा मामला : सामाजिक कार्यकर्ता भगवान सिंह राजपूत ने मार्च में उच्च शिक्षा विभाग व विश्वविद्यालय को शिकायत भेज श्रीराम कालेज की वैधता पर सवाल उठाए थे। निरीक्षण में यह भी पता चला कि एचएल अग्रवाल बीएड कालेज, एचएल अग्रवाल कालेज आफ एजुकेशन, इटारसी एक ही पते पर संचालित दर्शाए गए हैं। , जबकि निरीक्षण में वहां भवन तक नहीं मिला।

1600 नंबर सीरीज वाली फोन काल को नहीं कर सकते ब्लाक : ट्राई

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि कोई भी एप 1600 नंबर सीरीज से आने वाली फोन काल को ब्लाक नहीं कर सकता है। ये काल पंजीकृत संस्थाओं और सरकारी संचार के लिए होती हैं। ट्राई का यह बयान कालर की पहचान करने वाले एप ट्रूकालर के साथ चल रहे विवाद के संदर्भ में आया है, जिसमें 1600 नंबरों की पहचान को लेकर मतभेद हैं।

ट्राई ने कहा, 140 नंबर सीरीज से आने वाली प्रचारात्मक काल को डीएनडी रजिस्ट्री की ओर से ब्लाक किया जा सकता है। 1600 सीरीज से आने वाली काल के कोई टैगिंग या फिल्टरिंग की अनुमति नहीं है। इन नंबरों का उपयोग बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जो आरबीआइ, सेबी, इरडा और पीएफआरडीए द्वारा विनियमित हैं।

सरकार का सवाल, हजारों करोड़ रुपये के निवेश का क्या होगा

प्रथम पृष्ठ से आगे

केंद्र सरकार का कहना है के इतने वर्षों में इस क्षमता निर्माण के बाद अगर हम देश ई-10 पर लौट जाता है तो सवाल उठेगा कि इन निवेशों का क्या होगा? अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का क्या होगा? किसानों, सहकारी समितियों, उद्यमियों, वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय नीति के आधार पर सद्भावनापूर्वक निवेश किए गए हजारों करोड़ रुपये का क्या होगा? इसके अलावा इस कार्यक्रम से कच्चे तेल के आयात में कमी आई है, विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है और किसानों को काफी आमदनी हुई है। वर्ष 2014-15 के बाद से अभी तक एथनाल का इस्तेमाल बढ़ाने से देश ने 1.97 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचाई है। बड़ी चुनौतियां पार कर पाया यह लक्ष्य : असली चुनौती यह थी कि भारत पर्याप्त मात्रा में एथनाल उत्पादन कैसे कर सकता है। उस समय देश इसके लिए पूरी तरह गन्ने पर निर्भर था, जिससे वार्षिक एथनाल उत्पादन क्षमता

लगभग 400 करोड़ लीटर थी। यह स्तर मिश्रण लक्ष्यों के लिए अपर्याप्त था। लिहाजा मई, 2018 में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के शुभारंभ के साथ सरकार ने बड़े पैमाने पर एथनाल उत्पादन के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण शुरू किया।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, भारतीय रेलवे और कई अन्य मंत्रालयों ने कच्चे माल के विस्तार, बुनियादी ढांचे के निर्माण, प्रौद्योगिकी को समर्थन देने, सामग्री को सुव्यवस्थित करने, मांग की निश्चितता पैदा करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया। यह यात्रा दो दशकों से अधिक समय तक चली है और इसमें काफी निवेश किया गया है। इसलिए यह कहना गलत है कि इसमें जल्दबाजी की गई है। आटोमोबाइल निर्माताओं, तेल कंपनियों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ कई वर्षों के विचार-विमर्श के बाद ई-20 को अपनाया गया है। ई-20 से वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंचने के दावों को भी सरकार ने गलत बताया है। उसका कहना है कि ई-20 में अगर सुरक्षा से जुड़ी कोई चिंता होती, तो वाहन निर्माता कंपनियां ई-20 अनुकूल वाहनों को स्वीकृति नहीं देतीं या वारंटी जारी नहीं रखतीं। मारुति सुजुकी ने कहा है कि वर्ष 2024-25 में कुल 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विस दी और इसमें से 1.5 करोड़ कारें ई-20 लागू होने से पहले की थीं, लेकिन किसी भी वाहन में ई-20 से संबंधित समस्या नहीं मिली। हीरोमोटोकार्प ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। कार कंपनियों का यह भी मानना है कि ई-20 से पिकअप बेहतर होता है और इंजन ज्यादा अच्छी तरह काम करता है।

संपादकीय

धरा थरथरली, प्रश्न उरले!

यंदा वरुणराजाने पाठ फिरवल्यामुळे मराठवाडा आधीच भीषण दुष्काळाच्या छायेत आहे. पाण्याचे आटलेले स्रोत, कोरडा चाललेला खरीप हंगाम आणि चाऱ्याअभावी होरपळणारे पशुधन यामुळे इथला शेतकरी आभाळाकडे डोळे लावून बसला आहे. अशातच आता धरणीकंप झाल्याने आधीच संकटात सापडलेले नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या चिंतेत आणखीच भर पडली आहे. भूकंपामुळे ग्रामीण भागात भीतीचे वातावरण आहे. अस्मानी संकटाने आर्थिक संकटात सापडलेला शेतकरी आता रात्र जागून काढत आहे. लातूरच्या (किल्लारी) ऐतिहासिक भूकंपाच्या आठवणी ताज्या झाल्याने अनेकांवर मानसिक दडपण आले आहे. हिंगोली, नांदेड आणि लातूर या मराठवाड्याच्या तीन प्रमुख जिल्ह्यांत गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास जाणवलेले भूकंपाचे तीव्र धक्के केवळ जमिनीच्या किरकोळ हालचालीपुरते मर्यादित नसून, ते या संपूर्ण परिसराच्या भूगर्भीय सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहेत. रिश्टर स्केलवर ४.४ ते ४.६ च्या दरम्यान नोंदवली गेलेली तीव्रता आणि त्यानंतर लागोपाठ बसलेल्या दुय्यम धक्क्यांनी (आफ्टर शॉक्स) नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले. सुदैवाने यात जीवितहानी झाली नसली, तरी हा धरणीकंप नागरिकांच्या मानसिकतेवर आघात करणारा आहे. मराठवाडा आणि भूकंपाचा इतिहास पाहिला तर ३० सप्टेंबर १९९३ चा किल्लारी (जि. लातूर) येथील महाविनाशकारी भूकंप डोळ्यांसमोर उभा राहतो. ६.२ रिश्टर स्केलच्या त्या भूकंपाने हजारो निष्पाप लोकांचा बळी घेतला होता आणि संपूर्ण गावेच्या गावे मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली होती. तोपर्यंत दक्षिण पठार किंवा दख्खनचे पठार हे भूगर्भीयदृष्ट्या स्थिर मानले जात होते; परंतु किल्लारीच्या घटनेने हा समज खोटा ठरवला. तेहतीस वर्षांनंतरही या भूगर्भातील अस्वस्थता अद्याप शमलेली नाही, हेच या ताज्या धक्क्यातून दिसून येते. भूगर्भशास्त्रज्ञांनी काढलेले निष्कर्षही याला पुष्टी देणारेच आहेत. भूगर्भतज्ज्ञांच्या मते, भारताचा द्वीकल्पीय पठारी भाग हा भूगर्भीय दोष रेषा (फॉल्ट लाइन्स) आणि भूपट्ट्यांच्या अंतर्गत हालचालींमुळे संवेदनशील बनत चालला आहे. भारतीय भूपट्टा हा उत्तरेकडे आशियाई भूपट्टाकडे सरकत असताना अंतर्गत भागात प्रचंड ताण निर्माण होतो. हा ताण जेव्हा खडकांच्या सहनशक्तीपलीकडे जातो, तेव्हा तो ऊर्जेच्या स्वरूपात बाहेर पडतो आणि धरणीकंप होतो. मराठवाड्यातील लातूर, नांदेड आणि हिंगोली परिसर हा 'कुर्डूवाडी फॉल्ट लाइन'च्या क्षेत्राजवळ येतो. त्यातच पावसाळ्यात किंवा त्यानंतर जमिनीखाली मुरणारे पाणी आणि भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत होणारे बदल यामुळेही स्थानिक पातळीवर 'हायड्रो-सेस्मिसिटी'मुळे सौम्य ते मध्यम स्वरूपाचे धक्के बसतात. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाची भूमिका अत्यंत संवेदनशील आणि तत्पर असणे आवश्यक आहे. मात्र, दुर्दैवाने या घटनेच्या वेळी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेशी नागरिकांचा संपर्क होऊ शकला नाही. ही बाब प्रशासकीय ढिसाळपणावर बोट ठेवणारी आहे. जेव्हा भूकंप होतो, तेव्हा अफवांचे पीक वेगाने पसरते. अशावेळी अचूक माहिती देणे आणि नागरिकांना धीर देणे हे शासनाचे पहिले कर्तव्य असते. सरकारने केवळ भूकंपमापक यंत्रांवर नोंदी घेण्यापलीकडे जाऊन या भागातील सातत्यपूर्ण धक्क्यांचा सखोल वैज्ञानिक अभ्यास करण्यासाठी 'राष्ट्रीय भूभौतिकीय संशोधन संस्था' किंवा आयआयटीच्या तज्ज्ञांची विशेष समिती तातडीने नियुक्त करणे गरजेचे आहे. भूकंप ही अशी नैसर्गिक आपत्ती आहे जिचा अचूक अंदाज वर्तवणे आजही विज्ञानाला शक्य झालेले नाही. त्यामुळे 'प्रतिबंध आणि सज्जता' हाच एकमेव प्रभावी उपाय ठरतो. मराठवाड्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागांत 'भूकंपरोधक बांधकाम' नियमावलीची काटेकोर अंमलबजावणी करणे कायद्याने बंधनकारक केले पाहिजे. शाळा, महाविद्यालये आणि गावागावांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन पथकांद्वारे नियमित सराव करून नागरिकांना अशावेळी काय करावे आणि काय करू नये, याचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्यात २४ तास कार्यरत असणारी आणि उपग्रहावर आधारित सक्षम आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष यंत्रणा उभी राहिली पाहिजे, जेणेकरून आपत्कालीन स्थितीत संपर्क यंत्रणा कोलमडणार नाही. बुधवारी मध्यरात्रीच्या या धक्क्यांनी निसर्गाने आपल्याला पुन्हा एकदा सूचक इशारा दिला आहे. या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करणे भविष्यात आत्मघातकी ठरू शकते. केवळ कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष जमिनीवर कृती करण्याची हीच ती वेळ आहे. सरकारने तत्काळ बाधित भागातील पडझड झालेल्या घरांचे पंचनामे करून मदत द्यावी आणि कायमस्वरूपी उपाययोजनांसाठी वैज्ञानिक संशोधनाला गती द्यावी, तरच भविष्यातील संभाव्य अनर्थ टाळता येईल.

...अशाने सहकारी बँकांची ओळखच पुसली जाईल!

नागरी सहकारी बँकांच्या आदर्श उपविधींकरिता रिझर्व्ह बँकेचा पुढाकार ही सहकारी बँकांचे स्वरूप कॉर्पोरेटसदृश होण्याची नांदीच म्हटली पाहिजे.

विद्याधर अनास्कर
प्रशासक,
राज्य सहकारी बँक

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशातील नागरी सहकारी बँकांसाठी 'आदर्श उपविधी'चा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. वास्तविक सहकार हा राज्याच्या अखत्यारितील विषय असताना आणि सहकारातील विविध प्रकारच्या संस्थांसाठी आदर्श उपविधी तयार करण्याचे अधिकार राज्यांच्या सहकार कायद्यात फक्त आणि फक्त सहकार निबंधकांनाच दिलेले असताना रिझर्व्ह बँक हा अधिकार स्वत:कडे कसा घेऊ शकते?

सहकारी बँकांची नोंदणी महाराष्ट्र राज्य सहकार कायद्यांतर्गत राज्याच्या सहकार निबंधकांकडे होते. मात्र नागरी सहकारी बँकांकडे व्यावसायिकतेचा अभाव आहे, असा घोष करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेने उचललेले हे पाऊल म्हणजे नागरी सहकारी बँकांचे स्वरूप सहकारी न राहता कॉर्पोरेटसदृश होण्याची नांदी आहे. सहकारी बँकिंगचे मॉडेल आणि व्यापारी बँकिंगचे मॉडेल यामध्ये फरक करण्यास रिझर्व्ह बँक तयार नाही. सर्वांना बँकिंगबाबतचे निकष समान असावेत हा रिझर्व्ह बँकेचा प्रथमपासून अट्टहास. मोठ्या सहकारी बँकांनी स्वत:चे रूपांतर स्मॉल फायनान्स बँकेमध्ये करावे आणि लहान अशक्त बँकांनी, विलीनीकरण अथवा एकत्रीकरणाच्या रूपाने स्वत:चे अस्तित्व नष्ट करावे याकरिता यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने प्रयत्न केले आहेतच. व्यापारी बँकांचे मॉडेल हेच खरे यशस्वी बँकिंगचे मॉडेल होय, असा रिझर्व्ह बँकेचा सरसकट निष्कर्ष दिसतो.

रिझर्व्ह बँकेच्या या आदर्श उपविधींमधील संभाव्य तरतुदींचा विचार केल्यास काही व्यावसायिक फायदे या क्षेत्राला निश्चितच मिळतील.

१) संचालक मंडळ, बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट, उपसमित्या, व्यवस्थापन यांच्या भूमिका स्पष्ट होतील.

२) रिझर्व्ह बँक आणि राज्याच्या सहकार कायद्याशी सुसंगत असे उपविधी तयार होतील. निरीक्षण आणि लेखापरीक्षणातील त्रुटी कमी होतील; परंतु आपल्या संचालक मंडळामध्ये रिझर्व्ह बँकेचा प्रतिनिधी अथवा निरीक्षक नेमण्याचे अधिकारही रिझर्व्ह बँकेस द्यावे लागतील.

३) रिझर्व्ह बँकेकडून व्यवसायासाठी कोणतीच नवीन परवानगी मिळणार नसल्याने सर्वांनाच हे आदर्श उपविधी स्वीकारावेच लागतील. देशभरातील सहकारी बँकांमध्ये नियमांची एकरूपता येईल व नियामकांना या बँकांवर देखरेख करणे सोपे जाईल.

४) बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील तरतुदींनुसार शेअर्स, प्रेफरन्शिअल शेअर्स, डिबेंचर्स या मार्गाने भांडवल उभारणीची प्रक्रिया सुलभ होऊ शकेल. 'एक सभासद, एक मत' हे सहकारातील परमोच्च तत्त्व पाळावे लागेल. तसेच या शेअर्सच्या खरेदी-विक्री व मूल्यांकनासाठी 'सेबी'सारखी स्वतंत्र यंत्रणा सहकार तत्त्वांवर उभी करावी लागेल.

५) तज्ज्ञ संचालक, युवा संचालक, समित्या व कौशल्याधारित प्रशासनाला प्रोत्साहन मिळेल. जोखीम व्यवस्थापन सक्षम होईल. सहकारातील 'जरूरीपुरता नफा' हे तत्त्व मागे पडून 'जास्तीत-जास्त नफा' हे व्यापारी तत्त्व अंगीकारले जाईल.

६) रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण मजबूत झाल्यास ठेवीदारांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल.

या फायद्यांबरोबरच काही तोटेही होतील :

१) 'सभासदांनी, सभासदांसाठी चालविलेली संस्था' ही सहकारी संस्थांची ओळख पुसली जाऊन 'रिझर्व्ह बँकेने चालविलेली संस्था' अशी ओळख निर्माण होईल. सभासदांचे नियंत्रण कमी होईल.

२) राज्याचा सहकार कायदा आणि केंद्राचा बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट या दोन वेगवेगळ्या कायद्यांच्या उद्देश व तरतुदी भिन्न असल्याने अंमलबजावणीत अडचणी येऊ शकतात. नवीन नियम, समित्या, अनुपालन खर्च इ. लहान बँकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या जड ठरू शकेल.

४) संचालकांचे पात्रता निकष, त्यांचा कालावधी या पार्श्वभूमीवर अनुभवी संचालकांना कमी संधी मिळू शकेल.

५) हे आदर्श उपविधी स्वीकारायचे अथवा नाही अथवा त्यापैकी कोणत्या तरतुदी स्वीकारायच्या यासंबंधी निर्णय बँकांच्या सभासदांनी घ्यावयाचा असला तरी रिझर्व्ह बँकेच्या रेट्यापुढे ते स्वीकारावेच लागतील. रिझर्व्ह बँकेने नेमलेली समिती हे नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता, व्यावसायिकता, सुशासन आणि नियामक शिस्त वाढविण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे; परंतु याची अंमलबजावणी करताना सहकार चळवळीची मूलभूत तत्त्वे, सदस्यांचे नियंत्रण आणि स्वायत्तता यांचे संरक्षण करणे तितकेच महत्त्वाचे व आवश्यक आहे.

v_anaskar@yahoo.com

अन्वयार्थ

...म्हणजे खासगी रुग्णालये डॉक्टरांनी बंदच करावीत का?

डॉक्टरांवर सरसकट आरोप करून वैद्यकीय व्यवसायाला अंकित करू पाहणारे विधेयक घाईघाईने पारित करण्यामागे महाराष्ट्र सरकारचा उद्देश नेमका काय आहे?

डॉ. अविनाश भोंडवे
वैद्यकीय विश्लेषक,
माजी राज्य अध्यक्ष, आयएमए

वैद्यकीय व्यवसाय प्रशासनाच्या पूर्णपणे अधीन व्हावा आणि कायमचाच बंद व्हावा, अशी महाराष्ट्र सरकारची मनीषा दिसते. कारण - विधानसभेच्या सध्याच्या सत्रामध्ये महाराष्ट्र सरकार पारित करून घेत असलेले विधेयक. 'वैद्यकीय आस्थापना (नोंदणी व नियमन) अधिनियम, २०१०' मध्ये आमूलाग्र बदल करून वैद्यकीय व्यवसायाला अंकित करू इच्छिणाऱ्या तरतुदी या विधेयकात आहेत.

'महाराष्ट्र राज्यात सध्या बाह्यरुग्ण तपासणी (म्हणजे जनरल प्रॅक्टिशनर्सचे दवाखाने) आणि क्लिनिक्स (स्पेशालिस्ट डॉक्टरांचे दवाखाने) आणि आंतररुग्ण देखभाल या दोन्हीवर खाजगी क्षेत्राचे वर्चस्व आहे,' असे या विधेयकाच्या प्रास्ताविकात म्हटले आहे.

वस्तुस्थिती काय आहे?

१. सरकारी हॉस्पिटलमधील खाटांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अतिशय तुटपुंजी असल्यामुळे सर्वसाधारण नागरिकाला खाजगी हॉस्पिटलमध्येच भरती व्हावे लागते.

२. अत्यवस्थ रुग्णांना आवश्यक असलेली व्हेंटिलेटर्ससारखी अनेक प्राणरक्षक उपकरणे अगदी ऑक्सिजनसारख्या प्राथमिक गरजा सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये नसल्यामुळे गरीब रुग्णांनाही खाजगी हॉस्पिटल्सची पायरी चढावी लागते.

३. हृदयाच्या किंवा मेंदूच्या शस्त्रक्रिया; मूत्रपिंडे, यकृत, हृदय, फुफ्फुसे या महत्त्वाच्या अवयवांच्या प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया, आयव्हीएफ असे अतिविशेष विकारांचे उपचार करू शकणाऱ्या सरकारी हॉस्पिटल्सची संख्या अगदीच नगण्य आहे.

४. सरकारी हॉस्पिटल्सचे अपुरे बाह्यरुग्ण विभाग, डॉक्टरांची संख्याही अपुरी, महत्त्वाच्या औषधांचा तुटवडा यामुळे नागरिकांना खाजगी दवाखाने आणि क्लिनिक्सशिवाय पर्याय नाही.

५. 'खाजगी हॉस्पिटल्सवर कोणतेच नियंत्रण नाही,' असे हे विधेयक म्हणते. प्रत्यक्षात खाजगी हॉस्पिटल्सवर बॉम्बे नर्सिंग होम ॲक्टनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पूर्ण नियंत्रण असते. सर्व डॉक्टर्सवर त्यांच्या मेडिकल कौन्सिलचे नियंत्रण असते.

६. 'महाराष्ट्रातल्या रुग्णांना दुय्यम दर्जाचे निदानोपचार, उपचाराच्या हलक्या दर्जाच्या सुविधा, अपुरे उपचार, विनाकारण जास्त औषधे लिहून देणे, अनावश्यक तपासण्या व ढवळाढवळ, अनैतिक आणि तर्कशून्य प्रथा वाढीला लागल्या आहेत.'

-हे या विधेयकातले विधान हे सर्व शाखेच्या डॉक्टरांवर चिखलफेक करणारे, पूर्णपणे निषेधार्ह आहे. महाराष्ट्रात एकूण पाच लाख डॉक्टर्स आहेत. त्यामधील किती डॉक्टर वरील आरोपांमधील कृत्ये करतात, अशी खात्रीलायक वस्तुनिष्ठ आकडेवारी सरकारकडे आहे?

थोडक्यात, हा कायदा रुग्णांच्या हितासाठी नसून हॉस्पिटल्स आणि डॉक्टर्स यांच्या कार्यामध्ये 'इन्स्पेक्टर राज' आणण्याचा प्रयत्न आहे.

याच हेतूने तयार केलेल्या या विधेयकामुळे-

१. अवास्तव निकष, कठोर दंडात्मक कारवाई, हॉस्पिटलचे पंजीकरण रद्द केले जाण्याची टांगती तलवार आणि या सर्वासाठी प्रशासनाला दिलेले वारेमाप अधिकार, यामुळे ५ ते ५० बेड्स असलेल्या छोट्या रुग्णालयांचे अस्तित्व धोक्यात येईल.

२. या विधेयकामधील तरतुदीनुसार, कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये अत्यवस्थ रुग्ण गेल्यास त्याच्यावर त्वरित उपचार करून त्याला सामान्य स्थितीत आणणे बंधनकारक ठरणार आहे. अत्यवस्थ रुग्णाच्या उपचारासाठी लागणारी उपकरणे अगणित असतात आणि त्यासाठी लागणारी कौशल्येदेखील विविध प्रकारची असतात. प्रत्येक हॉस्पिटलला हे उपचार करणे शक्य नसते.

अत्यवस्थ रुग्णावर तातडीचे उपचार न झाल्यास त्या रुग्णालयाला मोठ्या दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल. शिवाय, रुग्णाची स्थिती आणखी गंभीर झाल्यास, रुग्ण दगावल्यास, रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या रोषास किंवा होऊ शकणाऱ्या हिंसाचाराला त्या हॉस्पिटलला वरचेवर सामोरे जावे लागणार.

अशाप्रकारचे अव्यवहार्य परंतु सक्तीचे कायदे आणल्यास असंख्य छोटी हॉस्पिटल्स बंद करण्यावाचून डॉक्टरांना गत्यंतर राहणार नाही.

३. या विधेयकाच्या तरतुदी आधुनिक वैद्यक, आयुर्वेद, होमिओपाथी, युनानी अशा सर्व डॉक्टरांना लागू होतील. मात्र या कायद्यातून सरकारी इस्पितळे, सरकारी दवाखाने वगळले आहेत. आरोग्य हा भारतीय नागरिकांचा संविधानिक हक्क आहे. मात्र त्यांना दर्जेदार उपचार करण्यासाठी फक्त खाजगी रुग्णालयांवर अंकुश चालवला जातो आहे. याचा अर्थ, सर्व प्रकारची खाजगी रुग्णालये बंद व्हावीत अशाच इच्छेने हा कायदा आणला जातो आहे.

म्हणजे मग गरीब मध्यमवर्गीय रुग्णांना उपचारांसाठी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सना शरण जाणे आणि कित्येक पटीने अधिक खर्च करण्यावाचून तरणोपाय राहणार नाही.

उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा या राज्यांमध्ये हा कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र या सर्व राज्यांत ५० पेक्षा कमी बेड्स असलेल्या रुग्णालयांना आणि क्लिनिक्सना वगळण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्रातदेखील या कायद्याच्या कचाट्यातून १ ते ५० बेड्सची रुग्णालये आणि खाजगी दवाखान्यांना मोकळीक द्यावी.

सरकारने घाईघाईने हे विधेयक मंजूर करून घेण्याऐवजी, विविध शाखांचे आणि उपचार पद्धतीचे डॉक्टर्स, आरोग्यतज्ज्ञ, रुग्ण संघटना आणि डॉक्टरांच्या अधिकृत संघटनांशी सविस्तर चर्चा करूनच या विधेयकाचा अंतिम मसुदा बनवावा. नवे विधेयक अधिक सखोल विचारांसाठी विधानसभेच्या सर्वपक्षीय समितीकडे पाठवावे आणि ते मंजूर झाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी व्हावी, हीच आय.एम.ए.ची आणि महाराष्ट्रातील सर्व शाखेतील डॉक्टरांची अपेक्षा आहे.

avinash.bhondwe@gmail.com

जगभर

बायकोला खांद्यावर घेऊन पळण्याची अनोखी स्पर्धा

आजवर अनेक प्रकारच्या धावण्याच्या शर्यती आपण पाहिल्या असतील. छोट्या-मोठ्या स्पर्धांपासून हाफ मॅरेथॉन, फुल मॅरेथॉन, अल्ट्रा मॅरेथॉन... अशा कितीतरी स्पर्धा आणि या प्रत्येक स्पर्धेत स्पर्धकांचा अक्षरश: कस लागतो. जभगरात अनेक स्पर्धा तर अशा आहेत, त्या जिंकणं तर सोडा; पण नुसत्या पूर्ण केल्या तरीही तो अनेकांसाठी अत्यंत अभिमानाचा क्षण असतो.

फिनलंडमध्ये मात्र दरवर्षी एक अत्यंत आगळीवेगळी स्पर्धा होते आणि ही स्पर्धा पूर्ण करणाऱ्या, जिंकणाऱ्या स्पर्धकांसाठीही तो आयुष्यभराचा प्रेमाचा, जिव्हाळ्याचा, अतूट नात्याचा आणि परस्परांवरील विश्वासाचा एक अविस्मरणीय क्षण असतो. ही स्पर्धा 'जोडीने' होते, म्हणजे नवरा-बायकोची जोडी या स्पर्धेत सहभागी होते, दोघांनीही या स्पर्धेत सहभागी होणं ही स्पर्धेची प्रमुख अट आहे. पण, याचा अर्थ दोघांनीही धावणं असा नव्हे, तर नवऱ्यानं बायकोला खांद्यावर उचलून घेऊनच धावायचं असतं. आपल्या जोडीदाराचं नुसतं वजनच पेलणं असं नव्हे, तर जोडीदाराला कुठलाही अपघात होऊ न देणं, त्याला न पाडणं आणि त्याचवेळी आपल्या क्षमतांचीही अत्युच्च कसोटी पाहणं.. ही या स्पर्धेची खासियत आहे.

त्यामुळेच या स्पर्धेचं नावही अत्यंत खास आहे.. - 'वाइफ कॅरिंग कॉम्पिटिशन' किंवा 'वाइफ कॅरिंग चॅम्पियनशिप' हे या स्पर्धेचं नाव.. या स्पर्धेचं नाव ऐकताना, ही स्पर्धा प्रत्यक्ष पाहताना अनेकांना हसू येऊ शकतं, पण आपल्या जोडीदाराला आपल्या खांद्यावर घेऊन पळणं ही खरोखरच सोपी गोष्ट नाही. कारण ही स्पर्धाही अत्यंत खडतर आहे. जोडीदाराला खांद्यावर घेऊन पळताना मध्ये अनेक अडथळेही पार करावे लागतात. अडथळ्यांच्या शर्यतीत असतात तसे खरोखरच उंच अडथळे स्पर्धकांना पार करावे

लागतात, काही ठिकाणी कंबरेइतक्या पाण्यातून मार्ग काढावा लागतो, अशावेळी खांद्यावर उलटं घेतलेल्या, जमिनीकडे तोंड असलेल्या जोडीदाराच्या नाकातोंडात पाणी जाऊन त्याचा जीवही गुदमरतो..

मुख्य म्हणजे नवऱ्यानंच बायकोला खांद्यावर घेऊन पळालं पाहिजे असं नाही, तर बायको जर नवऱ्यापेक्षा जास्त ताकदवान असेल तर तीही नवऱ्याला खांद्यावर घेऊन पळते. विशेष म्हणजे स्पर्धकानं खांद्यावर उचललेली व्यक्ती कायदेशीर पत्नीच असणं बंधनकारक नाही. जोडीदार, मित्र किंवा मैत्रीणही सहभागी होऊ शकतात. मात्र, दोघंही प्रौढ असणं आवश्यक आहे.

यंदाची स्पर्धा मध्य फिनलंडमध्ये मोठ्या उत्साहात पार पडली. तब्बल १२ देशांमधील ६० जोडप्यांनी यात सहभाग घेतला होता. स्पर्धकांनी जोडीदाराला खांद्यावर उचलून धावत पाण्याचे खड्डे, वाळूचे ढीग, लाकडी अडथळे आणि चढ-उतार असलेला सुमारे २५० मीटरचा ट्रॅक पूर्ण केला.

मजेशीर वाटणाऱ्या या स्पर्धेला तब्बल तीन दशकांहून अधिक काळाची परंपरा आणि अफाट लोकप्रियता लाभलेली आहे.

या स्पर्धेचे नियमही तितकेच आगळेवेगळे आहेत. ज्या जोडीदाराला खांद्यावर घेऊन आपण पळतो आहोत, त्या जोडीदाराचं वजन किमान ४९ किलो असलंच पाहिजे. वजन त्यापेक्षा कमी असल्यास अतिरिक्त वजन दिलं जातं. या स्पर्धेचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे जिंकणाऱ्या जोडप्याला परंपरेनुसार उचललेल्या जोडीदाराच्या वजनाइतकी बीअर बक्षीस म्हणून दिली जाते!

जनमन

हे बलिदान व्यर्थ जाऊ नये

६-७ मे २०२५ ला मध्यरात्री भारतीय सशस्त्र दलांनी 'ऑपरेशन सिंदूर' या सांकेतिक नावाने तिन्ही सशस्त्र दलांचा समावेश असलेली लष्करी कारवाई केली. भारतीय भूमीवर सीमापार दहशतवादासाठी जबाबदार असलेल्या गटांच्या ऑपरेशनल क्षमता निष्प्रभ करण्याच्या उद्देशाने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यात आले. जरी मे २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान झालेल्या चार दिवसांच्या संघर्षात लष्करी हानीबाबतचे अहवाल आणि माहिती उपलब्ध असली, तरी आत्तापर्यंत सरकारने ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान शहीद झालेल्या सैनिकांची माहिती अधिकृतरीत्या जाहीर केलेली नव्हती. आता वर्षभरानंतर सरकारने औपचारिकपणे शहीद झालेल्या सहा भारतीय लष्करी कर्मचाऱ्यांची नावे जाहीर केली आहेत.

या सैनिकांची नावे राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाच्या अधिकृत वेबसाइटवरील हुतात्मा नोंदीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली असून, नवी दिल्लीतील स्मारकावरही कोरण्यात आली आहेत. ऑपरेशन सिंदूरमधील प्रत्येक शहीदाची आपली वेगळी, हृदयद्रावक कहाणी होती. कोणीतरी एकुलता एक मुलगा होता. कुणाचे लवकरच लग्न होणार होते. कोणीतरी लष्करी निवृत्तीच्या जवळ आला होता, तर कुणाच्या घरी लहान पाहुणा येणार होता. राष्ट्राचे रक्षण करताना सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या त्या शूर सैनिकांप्रती आदर, कृतज्ञता आणि सन्मान योग्य पद्धतीनेच व्यक्त व्हायला हवा. सैनिकांचे बलिदान ही मातृभूमीची सर्वोच्च सेवा आहे आणि ते नेहमीच पूर्ण आदर, अभिमान व सन्मानाने स्मरणात राहील, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

- प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

चित्रकथा

जरासा नखरेल, तरीही अभिजात पॅरिसमधला पाऊस... आणि ती दोघं!

१८७७ मध्ये तिसऱ्या इम्प्रेशनिस्ट प्रदर्शनात गुस्ताव कॅयेबोटचं सात फूट लांब आणि नऊ फूट रुंद आकाराचं हे चित्र पाहून लोकांचे डोळे दीपले.

शर्मिला फडके
ख्यातनाम कला समीक्षक,
लेखिका

पॅरिसमधला एक मध्यवर्ती चौक. पावसात भिजलेला रस्ता दिव्यांसारखा चमकतोय. रस्त्याचं खास कॉबल्ड टेक्स्चर नजरेत भरत आहे. पावसाळी ओलसरपणा, थंडी जाणवते आहे. शहराची देखणी, आधुनिक रचना, पावसाळी दिवसातला राखाडी धुकाळ तरीही चमकदार असा खास पॅरिसचा प्रकाश. रेशमी कापडाच्या छत्र्या घेऊन, पायी चालत आपापल्या कामाला निघालेले, स्टायलिश पेहेराव केलेले, उच्चवर्गीय पॅरिशियन नागरिक कॅनव्हासवर दिसतात.

वेगवेगळ्या दिशांनी, परस्परांची काहीही दखल न घेता ते स्वमग्न चालत आहेत. असं वाटतंय की त्यांच्या हातातल्या छत्र्या केवळ पावसापासून नाही, एकमेकांकडे पाहण्यापासूनही त्यांना वाचवत आहेत.

आपल्या दिशेला चालत येणारं, पण आपल्याकडे न बघता मान वळवून बाजूला बघत असलेलं एक जोडपं, चित्राच्या अगदी समोरच्या बाजूला ठळकपणे नजरेत भरतं. त्यातल्या पुरुषाची कोरीव मिशी, उंच टोपी, बो टाय, फ्रॉक कोट असा पेहेराव आणि स्त्रीचा फॅशनेबल पायघोळ फरची झालर असलेला पोशाख, कानातले हिऱ्याचे डूल आणि दोघांचीही एकंदरीत शरीरभाषा त्यांच्या उच्चभ्रूपणाचं द्योतक आहे.

रस्ता जणू काही आपल्याच मालकीचा असल्याच्या थाटात ते चालत आहेत. चित्रात दूर, परिघाच्या कडेला काही कामगार, टॅक्सीचालक आहेत. हातात शिडी घेऊन चाललेला एक रंगारीही त्यात आहे. रस्त्यावर उंच, बाल्कनी असलेल्या आधुनिक इमारती आहेत. गर्दी, लगबग, शहराचा वेगही दिसून येतो आहे, पण कुठेही गजबजाट नाही. प्रत्येकाला गर्दीतही आपापला स्वतंत्र अवकाश जपण्याची मुभा आहे. पाऊस, शहर आणि माणसं परस्परांची अदब राखून आहेत.

गुस्ताव कॅयेबोट या फ्रेंच चित्रकाराने चितारलेला १८७७ सालातल्या पॅरिसमधल्या एका आधुनिक रस्त्यावर पडणारा पाऊस. शांत, संयत, जरासा नखरेल तरीही अभिजात, शहराला साजेसाच. हा पाऊस धुमाकूळ घालणारा, माणसांची दैना उडवणारा नाही. इथे चित्र पावसाचे नाही, शहराचे आहे.

चित्राची रचना वास्तववादी आणि रंगसंगती खास इम्प्रेशनिस्ट शैलीची, सौम्य आणि आल्हाददायक. दोन वेगळ्या पर्स्पेक्टिव्हचा केलेला सुरेख वापर, रस्त्याच्या मधोमध, फुटपाथच्या कडेला असलेला अवकाशाला विभागणारा हिरवा दिव्याचा खांब, या सगळ्यामुळे चित्राला त्रिमीत खोली प्राप्त झाली आहे. रस्ता आपल्या दिशेला एकदम पुढे पळत आल्यासारखा दिसतो. आपण जणूकाही त्या चौकातच उभे राहून दृश्य न्याहाळत असल्याचा आभास निर्माण होतो.

एकोणिसाव्या शतकात त्याने चित्रात हाताळलेला हा अँगल अभिनव होता.

या चित्रात एक उत्कट, शहरी ऊर्जा स्फूरत राहते, जी आपल्या संवेदनांना तत्काळ भिडते.

कॅयेबोट पॅरिसचा इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार. मात्र, त्याची स्टाइल जास्त वास्तववादी आणि फोटोग्राफिक होती. १८७७ मध्ये तिसऱ्या इम्प्रेशनिस्ट प्रदर्शनात एखाद्या प्रचंड छायाचित्रांसारखं दिसणारं सात फूट लांब आणि नऊ फूट रुंद हे चित्र पहिल्यांदा लावलं गेलं. त्यावेळी नव्याने कात टाकलेल्या, आधुनिक बांधकाम झालेल्या पॅरिसचा अत्याधुनिक, देखणा डौल पाहून लोकांचे डोळे दीपले. चित्राची रचना आणि आकार यामुळे प्रत्यक्ष पॅरिस नजरेसमोर साकारल्याचा प्रत्यय त्यांना येत होता. चित्राचं भव्य स्वागत झालं. यात कला कमी आणि रचना जास्त आहे म्हणणारेही काही टीकाकार होते, पण फार कमी. आता हे चित्र शिकागो आर्ट इन्स्टिट्यूटमध्ये पाहायला मिळते.

sharmilaphadke@gmail.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.)
'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

अमरनाथ की चिंता

अमरनाथ यात्रा तो जारी रहेगी, पर इसकी आस्था के केंद्र बाबा बफानी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। बर्फ से बनने वाला प्राकृतिक शिवलिंग आधिकारिक रूप से यात्रा शुरू होने के चार दिन बाद ही पिघल गया है। मई महीने में यह सात फीट से ज्यादा ऊंचा था, पर यात्रा शुरू से होने से पहले ही 29 जून को इसकी ऊंचाई घटकर पांच फीट रह गई थी। विगत 7 जुलाई को यह 90 प्रतिशत से ज्यादा पिघल गया। लगातार तीसरे साल समय से बहुत पहले ही बाबा ने भक्तों को दर्शन से वंचित कर दिया है। अमरनाथ यात्रा और उस पावन गुफा का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। यह गुफा हिमालय में 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां केवल पैदल, खच्चर या पालकी से पहुंचा जा सकता है। यह प्राकृतिक संयोग ही है कि हर वसंत ऋतु में गुफा की छत से टपकता जल जमते-जमते शिवलिंग की आकृति धारण करता है और यह भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का एक अनुपम केंद्र बन जाता है। अफसोस, हिम-शिवलिंग दर्शन के दिन साल-दर-साल घटते चले जा रहे हैं।

बीते वर्ष की बात करें, तो करीब 25 लाख लोग यात्रा पर गए थे, मगर उनमें से पांच प्रतिशत आस्थावान ही हिम-शिवलिंग के दर्शन कर पाए थे। इस वर्ष तो दर्शन करने वालों की संख्या और भी कम रही है। यात्रा जारी रहेगी, क्योंकि अमरनाथ गुफा का अपना महत्व है, किंतु वहां से ज्यादातर भक्त कुछ निराशा लिए लौटेंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहली नजर में तो यह पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों का दुष्परिणाम है। स्थानीय स्तर पर अमरनाथ गुफा या उस पूरे क्षेत्र के प्राकृतिक संरक्षण के लिए शायद कुछ भी नहीं किया गया है। भक्त जिस हिम-शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसे प्रकृति ही निर्मित करती है। अगर प्रकृति का संरक्षण नहीं होगा, तो ऐसे विरल शिवलिंग के दर्शन भी नहीं होंगे। क्या उस क्षेत्र में प्रकृति के संरक्षण के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं? क्या पहले की गई अच्छी सिफारिशों को लागू किया गया है? विशेषज्ञ बताते हैं कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड यहां पर्यावरण कानूनों की पालना पर्याप्त मुस्तैदी से नहीं करता है। पिछली सदी के अंतिम वर्षों तक अमरनाथ गुफा के निकट एक किलोमीटर के रास्ते में हर जगह हिम-दर्शन होते थे और हिम-शिवलिंग की ऊंचाई हफ्तों तक आठ-दस फीट तक बनी रहती थी। अब यात्रा के समय उस पूरे क्षेत्र में हिम-दर्शन दुर्लभ होता जा रहा है। प्रकृति पथराती जा रही है।

अमरनाथ गुफा में हिम-शिवलिंग की ऊंचाई हफ्तों तक आठ-दस फीट बनी रहती थी, पर अब यात्रा के समय उस पूरे क्षेत्र में हिम-दर्शन दुर्लभ होता जा रहा है।

अब क्या यात्रा के समय को बदलना होगा? क्या यात्रा की शुरुआत जुलाई से नहीं, जून से ही करनी पड़ेगी, ताकि लोग यहां दर्शन लाभ ले सकें? हालांकि, आने वाले समय में यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रकृति के चमत्कार के दर्शन के लिए वही लोग जाएं, जो प्रकृति के संरक्षण का महत्व समझते हैं, जो कचरा या गंदगी नहीं फैलाते, जो यहां तपस्या भाव से पहुंचते हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित करना, प्लास्टिक पर प्रतिबंध और प्राकृतिक मार्गों को उनके मूल रूप में बहाल करना जरूरी हो गया है। भक्तों की भीड़ अपने साथ तापमान भी लाती है, अतः पूरी यात्रा को पुनः नियोजित करने की जरूरत है। तीर्थयात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने या घटाने की जरूरत है। *नेचर रिव्यूज़ अर्थ ऐंड एनवायर्नमेंट* में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, सन् 1950 के बाद से हिमालय में ऊंचाई वाले क्षेत्रों का तापमान वैश्विक औसत से 50 प्रतिशत अधिक तेजी से बढ़ा है। यदि हम हरसंभव उपायों से हिमालय को सहेजेंगे, तभी शिवलिंग के एक पावन स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे। हिमालय सेवा हमारी संस्कृति में शिव सेवा से कम नहीं है।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले

Hindustan

11 जुलाई, 1951

पंचवर्षीय योजना

योजना आयोग ने महीनों के अध्ययन और चिन्तन के बाद देश के भौतिक विकास की पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत कर दी है। योजना का यह अन्तिम रूप नहीं है। उस पर अभी व्यापक चर्चा की जायेगी और उसके बाद उसे अन्तिम रूप दिया जायेगा। अतः उसमें अभी भी संशोधन-परिवर्द्धन की गुंजायश है। योजना आयोग चाहता है कि इस योजना को कार्यान्वित करने में देश के प्रत्येक नागरिक का किसी न किसी रूप में सहयोग मिलना चाहिए। जितनी अधिक मात्रा में यह सहयोग सुलभ होगा, उतनी ही योजना के सफल होने की अधिक संभावना होगी। योजना आयोग ने भूमिका तैयार कर दी है, किन्तु वह देश के समस्त विचारशील लोगों को योजना के निर्माण में भाग लेने का अवसर देना चाहता है। इस लोकतंत्री पद्धति के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में जन-सहयोग प्राप्त होने की आशा की जा सकती है।

योजना आयोग ने अपनी पंचवर्षीय योजना पर राजकीय सूत्रों द्वारा 17 अरब 93 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान लगाया है। योजना दो भागों में विभक्त की गयी है। प्रथम भाग को कार्यान्वित करने के लिए 14 अरब 93 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। योजना आयोग का विचार है कि देश को हर अवस्था में किसी न किसी तरह यह रुपया जुटाना चाहिए। उसके फलस्वरूप योजना आयोग को आशा है कि सन् 1955-56 के अन्त में उपभोक्ताओं को आवश्यक पदार्थ उतनी मात्रा में मिलने लगेंगे, जितनी मात्रा में कि वे युद्ध के पहले सुलभ थे। योजना के दूसरे भाग के लिए 3 अरब रुपये की आवश्यकता होगी और उसके फलस्वरूप भौतिक विकास का स्तर और भी ऊंचा हो जायेगा। किन्तु इस रुपये का काफी अंश विदेशी सूत्रों में प्राप्त होना चाहिए। योजना आयोग ने अपनी योजना में सब से अधिक महत्व खेती और ग्राम उत्थान तथा सिंचाई और बिजली पैदा करने की योजनाओं को दिया है। इन योजनाओं के लिए उसने करीब 641 करोड़ 96 लाख रुपया अर्थात कुल व्यय का 43 प्रतिशत निर्धारित किया है। यातायात और आवागमन के साधनों के लिए 388 करोड़ 20 लाख, सामाजिक सेवाओं के लिए 254 करोड़ 8 लाख और शरणार्थियों के पुनःसंस्थापन के लिए 79 करोड़ रुपया तजबीज किया गया है।

आज विश्व जनसंख्या दिवस है। संसार के कई देशों में हम यह देख रहे हैं कि घटती आबादी से असंतुलन पैदा हो रहा है। वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। नए जोड़े संतान पैदा करने को राजी नहीं हैं। ऐसे देशों की सरकारें अब चिंतित हो उठी हैं। सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने के बाद हमारे लिए भी यह गंभीर चिंतन का समय है कि आबादी हमारे लिए अवसर है या आपदा? इस ज्वलंत सवाल पर पेश हैं दो पहलू :

आमने-सामने

बढ़ती जनसंख्या और कम पड़ते संसाधन

यहां स्कैन करें

अरुण कुमार | वरिष्ठ अर्थशास्त्री

- बढ़ती जनसंख्या सीमित संसाधनों पर बोझ ही बढ़ाती है।
- देश की नीतियां यह तय करती हैं कि जनसंख्या वरदान है या शाप?
- शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ने से आबादी की उत्पादकता बढ़ जाएगी।

अक्तूबर 2022 में मैंने कुछ अर्थशास्त्रियों व गांधीवादियों के साथ मिलकर एक शोध-कार्य किया था, जिसका निष्कर्ष था कि 32 करोड़ लोग अच्छे रोजगार में हैं, जबकि 28 करोड़ भारतीय या तो बेरोजगार हैं अथवा उनके पास ढंग का काम नहीं है। इसका अर्थ था कि भारत में एक कार्यरत व्यक्ति के ऊपर 4.5 लोगों के जीवन का भार था। इसमें यदि बेरोजगार और जैसे-तैसे नौकरी करने वाले उन 28 करोड़ लोगों को भी जोड़ दें, तब भी हर कार्यरत कर्मी के ऊपर 2.4 व्यक्ति का दायित्व भार पाया गया था। इस रिपोर्ट की चर्चा मैंने इसलिए की, क्योंकि किसी भी देश की आबादी वहां के सामाजिक-आर्थिक पहलू से जुड़ी होती है और जनसंख्या वरदान है या शाप, इसका निर्धारण उस देश की नीतियों से होता है।

ऐसे में, उचित यही है कि उपलब्ध रोजगार के नजरिये से जनसंख्या को देखा जाए। अगर देश में बेरोजगारी पसरी है, तो वहां की आबादी परेशानी पैदा करेगी ही। हालांकि, हर हाथ को रोजगार दे पाना आसान भी नहीं होता। बढ़ती आबादी संसाधनों पर बोझ तो बढ़ाती ही है और भारत जैसे देश में, जहां 'फ्रीबीज' की संस्कृति जन्म ले चुकी है, वहां जनसंख्या को संभाल लेना किसी दुरूह जिम्मेदारी से कम नहीं। हम चाहें, तो जापान का उदाहरण ले सकते हैं। वहां हर वर्ग किलोमीटर में 336 से 340 लोग रहते हैं, यानी उसका जनसंख्या घनत्व कम नहीं है और वह तेल, स्टील जैसे उत्पाद आयात भी करता है, बावजूद इसके वह हमसे 12 गुना अधिक समृद्ध है। ऐसा इसलिए, क्योंकि वहां उत्पादकता अधिक है। दक्षिण कोरिया भी इसी तरह अपने हर नागरिक में उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास करता है।

भारत में जनसंख्या वृद्धि इसलिए भी अधिक खलती है, क्योंकि यहां 'टॉप डाउन' और 'ट्रिकल डाउन' जैसी अर्थशास्त्रीय अवधारणाओं के हिसाब से काम हो रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि आर्थिक लाभ ऊपरी वर्गों (अमीरों) के पास सिमटकर रह जाता है और वह रिसकर नीचे तक नहीं आ पाता। इसके कारण हमें लगता है कि आबादी हमारे लिए बोझ बन गई है, जबकि असलियत में यह नीतिगत मसला है। सार्थक नीतियों का अभाव किस कदर नुकसान पहुंचाता है, इसका एक बड़ा उदाहरण अफ्रीका है। वहां संसाधनों की कमी नहीं है और जनसंख्या घनत्व भी तुलनात्मक रूप से कम है। बावजूद इसके वहां गरीबी ज्यादा है, क्योंकि वहां की सरकारें ऐसी नीतियां नहीं बना सकी हैं, जो वंचित व पिछड़े तबकों का पर्याप्त उत्थान कर सकें। भारत के साथ अच्छी बात यह रही है कि यहां महात्मा गांधी जैसे विचारकों ने जन्म लिया, जो 'नीचे से विकास' के हिमायती रहे। उनका स्पष्ट मानना था कि गांव के सबसे गरीब और आखिरी व्यक्ति का विकास सबसे पहले होना चाहिए। इस 'गांधीवादी विकास' का लाभ हर तबके को मिलता, पर इसको हम पूर्णतः व्यावहारिक जामा नहीं पहना सके, जिसका नुकसान हमने उठाया है।

हालांकि, ऐसा नहीं है कि अब हम बिल्कुल खाली हाथ हो गए हैं। अब भी हमारी सरकारें खासतौर से शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्च बढ़ा दें, तो जनसंख्या का लाभ हम उठा सकते हैं। यहां जाने-माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन याद आ रहे हैं, जिन्होंने सन् 1986 में एक लेख लिखकर बताया था कि कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र देश की तरक्की की इबारत लिख सकते हैं। उन्होंने अपने लेख में कहा था, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और थाइलैंड सन् 1947 में कमोबेश एक जैसे थे। इनकी आर्थिक और सामाजिक दशा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, यहां गरीबी बदस्तूर थी और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव था, लेकिन बाद के वर्षों में भारत बाकी तीनों देशों की तुलना में पिछड़ता गया, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमने जरूरत के मुताबिक खर्च नहीं किए। कोठारी आयोग की स्पष्ट सिफारिश थी कि शिक्षा पर जीडीपी का कम से कम छह फीसदी खर्च होना चाहिए, लेकिन आज भी हम चार फीसदी से ऊपर नहीं उठ सके हैं। चूंकि अपने देश में शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, इसलिए बच्चे 'जॉब सीकर' (नौकरी की चाह रखने वाले) बन रहे हैं, न कि 'जॉब क्रिएटर' (रोजगार मुहैया कराने वाले)। उद्योग जगत का स्पष्ट मानना है कि ग्रेजुएट करने वाले बच्चों की ट्रेनिंग कमजोर है और वे कार्यक्षेत्र में खुद को साबित नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि 'एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन' की रिपोर्ट बता रही है कि 14 से 18 साल के 40 फीसदी किशोर दूसरी जमात के गणित के सवाल तो हल नहीं ही कर पाते, पढ़-लिख भी नहीं पाते। आज तकनीक प्रधान दुनिया है और एआई ने उद्योग जगत की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। ऐसे में, अगर हमारे बच्चे कुशल नहीं होंगे, तब जनसांख्यिकीय लाभांश का सपना भला कैसे पूरा हो सकेगा? भारत सर्वाधिक नौजवानों वाला देश है और यहां करीब 37.1 करोड़ आबादी 15 से 29 वर्ष की है, जबकि 75 करोड़ लोग 30 साल से भी कम के हैं। ऐसे में, इस बड़ी जनसंख्या की योग्यता और कुशलता में ही जनसंख्या के फायदे व नुकसान की विवेचना छिपी हुई है।

साफ है, आबादी को सामाजिक और आर्थिक कारक के रूप में देखना उचित होगा। जब समृद्धि आती है, तब परिवार बच्चे कम पैदा करने लगते हैं। 1975 में फोर्ड फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि भारत में यदि कोई गरीब अभिभावक किसी एक बच्चे को अपने बुढ़ापे तक देखना चाहता है, तो उसे कम से कम पांच बच्चे पैदा करने होते हैं, क्योंकि चार बच्चे किसी न किसी वजह से मर सकते हैं। चूंकि उस समय सामाजिक सुरक्षा नहीं थी, इसलिए बच्चों पर ही इसका भार था। उस दौर में हमारी जीवन प्रत्याशा भी काफी कम थी। मगर समृद्ध भारत में न सिर्फ उम्र बढ़ी, बल्कि मृत्यु दर में भी कमी आई। नतीजतन, 'छोटा परिवार, खुशी परिवार' जैसी परिकल्पना साकार होने लगी। बावजूद इसके हमारी आबादी दुनिया में सबसे अधिक है।

हमें इसका लाभ उठाना है, तो शिक्षा व स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना ही होगा, अन्यथा यह आबादी गैर-उत्पादक रह जाएगी और समाज पर बोझ साबित होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

आबादी को अवसर में बदलने का समय

यहां स्कैन करें

नंदलाल मिश्र | रिसर्च फेलो, आईआईपीएस, मुंबई

- हम विश्व में सबसे अधिक युवा और कामकाजी आबादी वाला देश भी होंगे।
- अधिकतम कामकाजी आबादी को कार्य कुशल और स्वस्थ बनाने की जरूरत।
- सामाजिक सुरक्षा में निवेश से अतिरिक्त आबादी का प्रबंध हो जाएगा।

भारत 2023 में ही चीन को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र के ताजा अनुमान के मुताबिक, इस साल जून के अंत में हमारी जनसंख्या लगभग 148 करोड़ थी, चीन से सात करोड़ अधिक। आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे भारत के लिए अपनी आबादी को आपदा नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र के ही अनुमान के मुताबिक, भारत की आबादी 2060 के दशक में 170 करोड़ का आंकड़ा छूने के बाद घटने लगेगी। इस दौरान हम विश्व में सबसे अधिक युवा और कामकाजी आबादी वाला देश भी होंगे। दुनिया का प्रत्येक पांचवां कामकाजी आयुवर्ग (15 से 65 वर्ष) का व्यक्ति भारतीय होगा। वर्तमान में भारत की आधी आबादी 30 साल से कम उम्र की है। देश की कुल जनसंख्या में कामकाजी आयुवर्ग की हिस्सेदारी लगभग 65 प्रतिशत है, बच्चों की 25 प्रतिशत, तो वृद्धों की 10 प्रतिशत। साल 2070 आते-आते कामकाजी आबादी घटकर 55 फीसदी रह जाएगी, वहीं साठोत्तरी वृद्धों की आबादी बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगी। वर्तमान में आर्थिक रूप से निर्भर जनसंख्या (बच्चे और वृद्ध) की तुलना में उत्पादक यानी कामकाजी वर्ग की संख्या लगभग दोगुनी है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति कहलाती है।

किसी भी आबादी के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति एक सीमित समय के लिए होती है। इस दौरान यदि देश अपनी अधिकतम कामकाजी आबादी को कार्य कुशल बना पाने, स्वस्थ रखने और उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार के अवसर मुहैया कराने में सफल होता है, तो इससे आर्थिक विकास दर और राष्ट्र की समृद्धि में अभूतपूर्व तेजी आती है। नब्बे के दशक की शुरुआत में भारत और चीन की प्रति व्यक्ति आय लगभग बराबर थी, लेकिन आज एक चीनी की आय एक भारतीय की आय से पांच गुनी अधिक है।

भारत के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति आगामी चार दशकों तक उपलब्ध है। इस दौरान भारत न केवल विश्व की सबसे बड़ी उत्पादक आबादी होगा, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा बाजार भी। आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में हमें इसे एक वरदान के रूप में देखना चाहिए। हालांकि, जनसांख्यिकीय लाभांश को आर्थिक विकास में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक है कि कौशल प्रशिक्षण, उत्तम स्वास्थ्य व रोजगार सृजन में उचित निवेश हो। शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाई जाए। श्रमबल सुपोषित और रोगमुक्त हो। गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए। उच्च शिक्षा में नहीं आने वाले युवाओं को रोजगार के दृष्टिकोण से प्रशिक्षित किया जाए। भारत में महिलाओं की लगभग दो-तिहाई आबादी सवैतनिक श्रमबल का हिस्सा नहीं है। अब जबकि प्रजनन दर औसतन दो बच्चे प्रति महिला से भी कम हो चुकी है, रोजगार के लिए उनके पास विकसित देशों की महिलाओं की भांति अधिक समय उपलब्ध है। महिलाएं पहले की तुलना में अधिक शिक्षित और सशक्त हैं भी। सतत उच्च आर्थिक विकास दर कायम रखने के लिए आवश्यक है कि इन महिलाओं को श्रमबल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

जनसांख्यिकीय लाभांश हासिल करने की दिशा में भारत को शून्य से शुरुआत नहीं करनी है। पिछले 75 वर्षों में देश की आबादी लगभग चार गुना बढ़ी है और इसी अवधि में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साक्षरता दर 1951 के 18 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 80 प्रतिशत हो गई है। 1970 के दशक में प्रत्येक 100 भारतीयों में से एक से भी कम व्यक्ति स्नातक था, जबकि 2024 में यह अनुपात बढ़कर प्रत्येक 10 में से एक हो गया। जीवन प्रत्याशा में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1970 के दशक में एक भारतीय की औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 50 वर्ष थी, जो अब बढ़कर 70 वर्ष से अधिक हो गई है। पिछले दो दशकों में गरीबी में भी तेज कमी आई है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, 2005 में 55 प्रतिशत भारतीय बहुआयामी गरीबी में जी रहे थे, जबकि 2020 में यह अनुपात घटकर लगभग 16 प्रतिशत रह गया। इस दौरान 40 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। ये उपलब्धियां भारत की आगे की प्रगति के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती हैं।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय प्रजनन दर 2020 में ही प्रतिस्थापन स्तर, यानी प्रति महिला औसतन 2.1 बच्चे से नीचे आ गई थी। केवल चार राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मेघालय) में यह दर प्रतिस्थापन स्तर से अधिक रह गई थी। जब प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे चली जाती है, तो तीन से चार दशकों बाद कुल आबादी में कमी आने लगती है। ऐसे में, जब भारत स्वतः जनसांख्यिकीय परिवर्तन के तीसरे चरण से गुजर रहा है, और अगले तीस-चालीस साल में मृत्यु-दर के जन्म-दर से अधिक होने की आशंका है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय अपनाना उल्टा नुकसानदेह हो सकता है। चीन की एक-बच्चा नीति से वहां आबादी तेजी से वृद्ध होने लगी, जिससे कामकाजी आबादी उसी रफ्तार से कम हुई।

जिस प्रकार भारत ने 70 और 80 के दशक में खाद्यान्न उत्पादन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करके तेजी से बढ़ती आबादी की खाद्य जरूरतों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया, उसी प्रकार अब बढ़ती वृद्ध आबादी और गैर-संक्रामक बीमारियों की चुनौतियों के लिए भी समय रहते तैयारी करनी होगी। यदि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और मानव विकास में पर्याप्त निवेश किया जाए, तो आने वाले दशकों में जुड़ने वाली लगभग 20 करोड़ अतिरिक्त आबादी का प्रबंधन भी प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। यह आबादी देश पर बोझ नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक संसाधन बन सकती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

समय को क्या काटोगे

जीवन दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो ऐसा कि बहता चला जाए, परिणाम कुछ भी न हो, निष्पत्ति कोई न मिले, पहुंचना कहीं न हो, कोई मंजिल पास न आए और दूसरा तरीका यह कि वह किसी लक्ष्य, किसी गहरे प्रयोजन, किसी गहरी प्रार्थना के धागे में पिरोया हुआ हो।

अधिकतर लोगों का जीवन समय का एक ढेर है। उसमें कोई संगति नहीं, कोई रेखाबद्ध विकास नहीं है। उसमें कोई सोपान नहीं है। कुछ लोगों का जीवन धागे में पिरोए हुए फूलों की भांति है। प्रत्येक फूल एक सीढ़ी है, और हर फूल एक नया द्वार है और जीवन एक शृंखला है। वह कहीं पहुंचता हुआ मालूम होता है।

समय रहते जाग जाओ, तो ठीक, क्योंकि जो क्षण बीत गए, वे बीत ही गए। उनको फिर से जीने की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए समय इस संसार में सबसे ज्यादा बहुमूल्य है। गया, तो गया और उसी के संबंध में हम सबसे ज्यादा लापरवाह हैं।

लोग बैठकर ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। पूछो, क्या कर रहे हो? वे कहेंगे कि समय काट रहे हैं, समय काटे नहीं कटता। समय तुम्हें काट रहा है, पागलो! तुम समय को न काट सकोगे। समय को तुम क्या काटोगे? तुम समय को कैसे काटोगे? समय पर तो तुम्हारी कोई पकड़ ही नहीं है। समय तुम्हें काट रहा हैः तुम सोचते हो, तुम समय को काट रहे हो। आखिर में पाओगे, समय तो नहीं कटा, तुम ही कट गए। आखिर में पाओगे, समय तो नहीं मरा, तुम्हीं मर गए।

समय तो एक अर्थ में वहीं का वहीं है। तुम आते हो, चले जाते हो। तुम्हारी सुबह होती है, तुम्हारी सांझ होती है। तुम्हारा जन्म होता है, तुम्हारी मृत्यु होती है।

ओशो

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

संगीन अपराध कहीं पर भी हो, उसका असर पूरी दुनिया और इंसानियत पर समान रूप से पड़ता है। अपराधों की रोकथाम की शुरुआत घर से होती है, लेकिन इसमें सामूहिक मदद की जरूरत पड़ती है।

अनुलोम-विलोम

शहर पानी-पानी

प्रशासनिक लापरवाही और अनियोजन का फल

हर वर्ष मानसून का आगमन देशवासियों के लिए राहत, हरियाली और नवजीवन के संदेश के साथ आता है। विडंबना है कि यही बारिश हमारे अधिकांश शहरों की बदहाल व्यवस्था की पोल भी खोल देती है। कुछ घंटों की वर्षा के बाद सड़कों का तालाब में बदल जाना, घरों और बाजार में पानी भर जाना, घंटों तक यातायात ठप रहना और बिजली-पानी जैसी मूलभूत सेवाओं का बाधित हो जाना अब सामान्य दृश्य बन गया है। यह स्थिति केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही प्रशासनिक लापरवाही और अव्यवस्थित शहरी नियोजन का परिणाम है। देश के महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक लगभग हर मानसून में एक जैसी तस्वीर सामने आती है। सवाल यह है कि जब हर वर्ष बारिश का समय निश्चित है, तो फिर हर बार नगर निकायों की तैयारियां क्यों विफल हो जाती हैं? नालों की सफाई के दावे कागजों तक सीमित क्यों रह जाते हैं? समस्या का सबसे बड़ा कारण अनियोजित शहरीकरण है। शहरों का विस्तार तो तेजी से हुआ, लेकिन उसी अनुपात में जल निकासी व्यवस्था नहीं की गई। प्राकृतिक जलमार्गों और तालाबों पर अतिक्रमण कर बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गईं। वर्षा जल के प्राकृतिक प्रवाह को रोक दिया गया। परिणामस्वरूप थोड़ी सी अधिक वर्षा भी शहरों के लिए संकट बन जाती है। नगर निकायों की कार्यप्रणाली भी गंभीर प्रश्नों के घेरे में है। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी, भ्रष्टाचार और जवाबदेही का अभाव स्थिति को और गंभीर बना देता है। जब तक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक केवल बैठकों और घोषणाओं से समस्या का समाधान संभव नहीं है।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

हर साल बरसात के मौसम में ऐसा ही होता है। स्थिति कभी नहीं सुधरती। आखिर सुधरे भी कैसे? जनता सरकार को दोष देती है और सरकार जनता को। जब दोनों में समन्वय होगा, तभी दोनों अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझेंगे। दिल्ली को लंदन बनाने से पहले उसे अपने ही देश की प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो जैसा बनाने की जरूरत है। मोहनजोदड़ो का 'ड्रेनेज सिस्टम' आज भी हमलोग पढ़ते हैं और इतनी बेहतरीन सुविधा अगर सारे शहर और शहरवासी अपनाएं, तो बारिश के मौसम में इतनी तबाही न आए। सबसे मुख्य कार्य है कि लोग कचरे को नालियों में न बहाएं और अपने आसपास की नालियों को ढककर रखें। हम सभी अपने काम जिम्मेदारी से करें, तो बारिश का मौसम आफत नहीं, बल्कि आनंद की अनुभूति कराएगा।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

हमें खुद जागना होगा, आदतें सुधारनी होंगी

पांच या दस मिनट की थोड़ी तेज बारिश और पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। नाले और सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं। लगता है, पूरी सड़क पर तालाब या नदी बह रही है। नालों और सड़कों का पानी लौटकर गलियों में आने लगता है। गली-मोहल्ले पानी में डूब जाते हैं। दो-दो फीट पानी भर जाता है।

हर समस्या की जड़ आदमी है और समाधान भी आदमी ही है। जैसे ही जलभराव होता है, हम नगर निगम और निर्माण विभाग को कोसने लगते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि ये नाले-नालियां जो भरी हुई हैं, इन्हें हमने ही भरा है। हर साल कुछ दिन पन्नी वालों के लिए सब्जी के ठेलों और दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया जाता है। टार्गेट पूरा होते ही यह अभियान ठप हो जाता है। फिर वही 'ढाक के तीन पात'। पन्नियां ही नालों-नालियों के जाम होने और पानी भरने की मूल जड़ हैं।

अब इस समस्या से निपटने के लिए हमें खुद जागना होगा। बाजार जाते समय कपड़े का थैला या जूट का थैला ले जाना होगा। पन्नियों को 'बाय-बाय, टाटा' कहना होगा। जब हम पन्नियां लेना बंद कर देंगे, तो दुकानदार खुद ही पन्नियों में सामान देना बंद कर देंगे। हमारी भी जिम्मेदारी है कि पन्नियों का उपयोग न करें। पन्नी में कूड़ा भरकर नालों में न डालें। हम नालों पर अतिक्रमण न करें, ताकि सफाईकर्मी आसानी से उनकी सफाई कर सकें। हमें जागना होगा, तभी इस समस्या से निदान पाया जा सकता है।

अतिवीर जैन 'पराग', टिप्पणीकार

हमारे अधिकांश शहरों में वर्षा हर साल संकट का कारण बन जाती है, लेकिन इसका कारण हम खुद हैं। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि नागरिकों द्वारा स्वयं पैदा किया गया संकट है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अवैध कब्जे, नालों पर अतिक्रमण, सार्वजनिक भूमि का दुरुपयोग और जल निकासी मार्गों को बाधित करने जैसी प्रवृत्तियों ने स्थिति को भयावह बनाया है।

वास्तव में हम अपने अधिकारों के प्रति तो सजग रहते हैं, लेकिन कर्तव्यों के प्रति नहीं। हमें पता है कि प्लास्टिक नालों को जाम करता है, फिर भी उसका उपयोग कम नहीं करते। नदियों, तालाबों और प्राकृतिक जलमार्गों पर अतिक्रमण करते हैं, वर्षा जल के प्राकृतिक प्रवाह को रोक देते हैं और फिर सरकार को दोषी ठहराते हैं। समाधान केवल नालों की सफाई तक सीमित नहीं है। सरकार, स्थानीय निकाय, सामाजिक संगठन, धर्मगुरु, शिक्षण संस्थान और आम नागरिकों को सक्रिय होना होगा, तभी स्थिति बदल सकती है।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

सुरक्षित दोपहिया का नया दौर

भारत में दोपहिया वाहनों का बाजार अब सिर्फ माइलेज और लुक तक सीमित नहीं रह गया है। सुरक्षा और स्मार्ट फीचर्स की बढ़ती मांग के साथ बाइक और स्कूटर में नई तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। एंटी स्किड टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, जीपीएस, एंटी-थेफ्ट सिस्टम जैसे फीचर अब प्रीमियम मॉडलों से आगे बढ़कर मिड-रेंज दोपहिया वाहनों तक पहुंच रहे हैं। कैसे काम करती हैं ये तकनीकें और क्यों बढ़ रही है इनकी जरूरत, बता रही हैं तृप्ति मिश्रा

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया वाहन बाजार है। देश में हर साल दो करोड़ से ज्यादा बाइक और स्कूटर बिकते हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और राइडर की सुरक्षा को देखते हुए कंपनियां अब सिर्फ माइलेज व दमदार इंजन पर ही नहीं, बल्कि सुरक्षा देने वाले और स्मार्ट फीचर्स पर भी जोर दे रही हैं। यही वजह है कि आम आदमी के दोपहिया वाहनों में भी अब आधुनिक सुरक्षा और सुविधा के फीचर तेजी से शामिल किए जा रहे हैं।

ब्रेकिंग की आधुनिक तकनीक

सड़क परिवहन मंत्रालय के नियमों के तहत सभी नए दोपहिया वाहनों में अब एबीएस अनिवार्य सुरक्षा फीचर बन चुका है। तेज ब्रेक लगाने पर यह पहियों को लॉक होने से रोकता है और वाहन का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यानी मिड-रेंज दोपहिया में भी ब्रेकिंग और वाहन को स्थिर व संतुलित रखने की आधुनिक सुरक्षा तकनीकें मिल रही हैं।

फीचर्स में मोटरसाइकिल आगे

प्रीमियम एडवेंचर और टूरिंग मोटरसाइकिलों में सबसे उन्नत सुरक्षा तकनीकें देखने को मिल रही हैं। डुकाटी मल्टीस्ट्राडा वी4, केटीएम 1390 सुपर एडवेंचर, बीएमडब्ल्यू आर 1300 जीएस और ट्रायम्फ टाइगर 900 जैसे मॉडलों में कॉर्नरिंग एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टीपल राइडिंग मोड और बड़े टीएफटी डिस्प्ले जैसी सुविधाएं मिलती हैं। वहीं, डुकाटी मल्टीस्ट्राडा वी4 और बीएमडब्ल्यू आर 1300जीएस के कुछ वेरिएंट्स में रडार आधारित एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे एडवांस फीचर्स भी हैं।

मिड-रेंज तक बढ़ता दायरा

मोटरसाइकिल में : जो स्मार्ट तकनीक कुछ समय पहले तक 15-25 लाख रुपये की प्रीमियम मोटरसाइकिलों तक सीमित थी, वह अब 1.2 से 3 लाख रुपये के सेगमेंट में भी पहुंच चुकी है। टीवीएस अपाचे आरटीआर 310, बजाज पल्सर एनएस400 जेड, हीरो एक्सट्रीम 250आर, केटीएम ड्यूक 390 और यामाहा एमटी-03 जैसी बाइकों में एडवांस राइडिंग तकनीकें मिल रही हैं।

स्कूटर में : वहीं, एथर 450एक्स, यामाहा एरॉक्स 155, टीवीएस जुपिटर 110, टीवीएस एनटॉर्क 125, सुजुकी एक्सेस 125 और होंडा एक्टिवा-ई जैसे स्कूटर भी टीसीए, कॉर्नरिंग एबीएस जैसे सुरक्षा फीचर्स और नेविगेशन और स्मार्टफोन-आधारित फीचर्स से लैस हैं।

दोपहिया वाहनों की दुनिया में आई डिजिटल क्रांति का नतीजा है कि जो तकनीक और डिजिटल फीचर्स अब तक कारों और प्रीमियम मोटरसाइकिलों में दिखते थे, अब आम बाइक और स्कूटरों में भी तेजी से पहुंच रहे हैं। इनमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ऐप के जरिए राइडर नेविगेशन, राइडिंग हिस्ट्री, सर्विस रिमाइंडर और वाहन की जानकारी के फीचर्स प्रमुख हैं।

वहीं, सुरक्षा के कुछ प्रमुख फीचर्स हैं :

ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस): गीली या फिसलन वाली सड़क पर टायर की पकड़ बनाए रखता है।

कॉर्नरिंग एबीएस: मोड़ पर तेज गति में दोपहिया के फिसलने का खतरा बना रहता है। इसमें कॉर्नरिंग एबीएस ब्रेक लगाने के दौरान बेहतर नियंत्रण देता है।

हिल होल्ड कंट्रोल: चढ़ाई या ढलान पर बाइक को पीछे लुढ़कने से बचाता है।

हैंड्स-ऑफ डिटेक्शन: कुछ प्रीमियम मॉडलों में सेंसर राइडर के हाथ हटने पर चेतावनी देते हैं।

स्मार्ट टेल लाइट और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल: अचानक ब्रेक लगने पर पीछे आने वाले वाहनों को फ्लैशिंग लाइट से सतर्क करते हैं।

ऑटो हैजर्ड लैंप: तेज ब्रेकिंग या आपात स्थिति में अपने-आप चालू होकर पीछे आने वाले वाहनों को सतर्क करते हैं।

आधुनिक हुए ई-स्कूटर

इलेक्ट्रिक स्कूटरों में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ओवरहीटिंग से बचाव व बैटरी की स्थिति पर नजर रखने वाली तकनीक सुरक्षा के लिहाज से अहम हो गई हैं। अब अधिकतर स्कूटर लोकेशन ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग और एप कनेक्टिविटी जैसे फीचर से लैस हैं।

एक्सेसरीज से भी मिले सुरक्षा

कुछ एक्सेसरीज हर मौसम में सुरक्षा बढ़ाती हैं, जबकि कुछ बारिश या लंबी यात्रा में उपयोगी होती हैं। बीआईएस-प्रमाणित हेलमेट, रिफ्लेक्टिव स्टिकर, व्हील रिफ्लेक्टर और टायर का दबाव बताने वाला टीपीएमएस सिस्टम भी मददगार होते हैं।

विशेषज्ञ की राय

दोपहिया वाहनों में अब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ जीपीएस ट्रैकिंग, एंटी-थेफ्ट सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल और कनेक्टेड फीचर्स आम हो रहे हैं। हालांकि, लाभ तभी मिलता है, जब वाहन का नियमित रखरखाव किया जाए। बाइक या स्कूटर खरीदते समय यह भी देखना चाहिए कि कौन-से सुरक्षा फीचर स्टैंडर्ड हैं और कौन-से बाद में जोड़े जा सकते हैं। आफ्टरमार्केट जीपीएस ट्रैकर या एंटी-थेफ्ट डिवाइस लगवाते समय उनकी गुणवत्ता, सही फिटमेंट और वाहन के सिस्टम से अनुकूलता जरूर जांचें। अंततः सुरक्षित राइडिंग, प्रमाणित हेलमेट और समय पर सर्विसिंग ही किसी भी सुरक्षा तकनीक को वास्तव में प्रभावी बनाती है।

— **भरत गुप्ता**, ऑटोमोबाइल इंजीनियर

चोरी से स्मार्ट सुरक्षा

दोपहिया को चोरी करना कारों की तुलना में आसान होता है। इसीलिए इन वाहनों में खास चोरी रोकने के लिए कई स्मार्ट सुरक्षा समाधान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जैसे :

जीपीएस ट्रैकर: वाहन की लाइव लोकेशन, जियो-फेंसिंग, ओवरस्पीड अलर्ट जैसी जानकारियां मोबाइल एप पर भेजता है।

इंजन इम्मोबिलाइजर: अधिकृत चाबी के बिना वाहन को स्टार्ट होने से रोकता है, जिससे चोरी का जोखिम कम होता है।

स्मार्ट अलार्म सिस्टम: वाहन के साथ छेड़छाड़ होने पर तुरंत अलर्ट देता है।

आरएफआईडी या ब्लूटूथ आधारित लॉकिंग सिस्टम: बिना अनुमति वाहन के इस्तेमाल को रोकने में मदद करते हैं। इनमें से कई सुरक्षा उपकरण आफ्टरमार्केट मिल रहे हैं।

कितना आएगा खर्च : बाइक या स्कूटर में कुछ सुरक्षा एक्सेसरीज बाहर से भी लगवाए जा सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले जीपीएस ट्रैकर आमतौर पर 2000 से 6000 रुपये, स्मार्ट एंटी-थेफ्ट अलार्म 2000 से 5000 रुपये और डिस्क लॉक 500 से 2000 रुपये के बीच उपलब्ध हैं।

विविध

महंगा न पड़े दोपहिया में बदलाव कराना

अपनी बाइक या स्कूटर में कुछ मॉडिफिकेशन यानी बाहर से शौकिया बदलाव करा रहे हैं, तो ध्यान दें कि वह नियमों के तहत ही हो। ऐसा इसलिए कि केंद्र सरकार और सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से नियमों में किए गए कड़े संशोधन इस साल से लागू हो चुके हैं। तेज आवाज वाला साइलेंसर, तेज रोशनी वाली एलईडी लाइट, प्रेशर हॉर्न और फैंसी नंबर प्लेट लगाने पर जुर्माना भी लग सकता है और वाहन जब्त भी किया जा सकता है। किसी मोटरसाइकिल को मॉडिफाइड करके उसमें तेज आवाज वाला साइलेंसर या एग्जॉस्ट लगाने की स्थिति में बाइक चालक पर 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। यह हर बार बढ़ता ही जाएगा। रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड किया जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत फैंसी, स्टाइलिश या मुड़ी हुई नंबर प्लेट लगाना भी गैर-कानूनी है। मानक (एचएसआरपी) नंबर प्लेट वाहन की सही पहचान और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर मानी जाती है।

ताकतवर और स्मार्ट हो रहे एआई एजेंट

क्लाउड सिक्योरिटी कंपनी सिसडिग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, साइबर सुरक्षा के इतिहास में पहली बार एक ऐसे एआई एजेंट (रैंसमवेयर) का पता चला है, जिसने बिना किसी इंसानी मदद के पूरे साइबर हमले को खुद अंजाम दिया। इस एआई एजेंट की सबसे हैरान करने वाली बात इसकी स्वायत्तता थी। जब यह एक अकाउंट का पासवर्ड क्रैक करने में विफल रहा, तो इसने खुद ही कोड में बदलाव किया और महज 31 सेकंड के भीतर दोबारा लॉग-इन कर लिया। यह शोधकर्ताओं के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसी एजेंटिक एआई तकनीक से सीमित जानकारी रखने वाले साइबर अपराधी भी तेज खतरनाक रैंसमवेयर हमले कर सकते हैं।

अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को जितना मजबूत बना सकें, उतना बेहतर रहेगा। अनजान यूएसबी डिवाइस, संदिग्ध ईमेल अटैचमेंट और बिना सत्यापित सॉफ्टवेयर से दूरी रखना भी ऐसे हमलों का खतरा कम करता है। कंपनियों के लिए कर्मचारियों को नियमित साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण देना भी ऐसे हमलों के जोखिम को काफी हद तक घटाता है। मजबूत पासवर्ड, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और नियमित सुरक्षा अपडेट जैसी सावधानियां अपनाना महत्वपूर्ण है।

नए गैजेट

बड़ी बैटरी के साथ मोटो जी77 पावर

मोटोरोला ने बीते दिनों भारत में अपना नया 5जी स्मार्टफोन मोटो जी77 पावर पेश कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 7000एमएएच की दमदार बैटरी है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल का दावा करती है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 प्रोसेसर भी दिया गया है।

कैमरा और स्टोरेज

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का मुख्य रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। यह 8जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज के साथ आता है। फोन को आईपी 64 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिली है, यानी पानी की हल्की फुहारों से सुरक्षित रहती है।

रंग और कीमत

फोन ग्रे, नेवी ब्लू, गुलाबी और लॉरेल ग्रीन रंगों में उपलब्ध होगा। इसकी कीमत 25,999 रुपये रखी गई है।

बजट में जेनो एफ 30 5जी

जेनो एफ 30 5जी फोन 4जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 6.67 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है, जो स्क्रॉल करने और वीडियो देखने का बेहतर अनुभव देती है।

कैमरा और बैटरी : 13 मेगापिक्सल का एआई रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 7000एमएएच बड़ी बैटरी मिलती है।

डायनामिक बार, अलग पहचान : फोन में डायनामिक बार फीचर दिया गया है, जो कॉल, म्यूजिक, चार्जिंग और अन्य नोटिफिकेशन की जानकारी देता है। साइबर व्हाइट और इन्टरस्टेलर ब्लू रंगों में उपलब्ध होगा।

कीमत : अनुमानित कीमत 12,499 रुपये बताई गई है।

तीन रंगों में नथिंग फोन (4बी)

हाल ही में पेश हुए नथिंग फोन (4बी) स्मार्टफोन में लंबे बैकअप के लिए 6000एमएएच की बैटरी दी गई है। फोन में चैटजीपीटी इंटीग्रेशन भी मिलता है, यानी कई काम सीधे फोन के इंटरफेस से चैटजीपीटी की मदद से किए जा सकते हैं।

ग्लिम्फ लाइट इंटरफेस : फोन के पीछे कंपनी का खास ग्लिम्फ लाइट इंटरफेस दिया गया है, जिसमें छोटी-छोटी एलईडी लाइटें कॉल, नोटिफिकेशन और चार्जिंग की जानकारी संकेतों के जरिए देती हैं।

कैमरा और स्टोरेज : फोन में 50 मेगापिक्सल का मुख्य और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। यह 8जीबी रैम के साथ 128जीबी और 256 जीबी स्टोरेज विकल्पों में उपलब्ध है।

उपलब्धता और कीमत : बिक्री 14 जुलाई से ई-कॉमर्स मंच फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। इसकी शुरुआती कीमत 29,999 रुपये रखी गई है। वेरिएंट के अनुसार 33,699 रुपये तक जाती है।

रंग : यह फोन ब्लैक, व्हाइट और ब्लू रंगों में खरीदा जा सकेगा। **फीचर डेस्क**

बारिश के मौसम में भी ईवी की बेफिक्र सवारी

मानसून आते ही इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते हैं, लेकिन इस मौसम में भी ये सुरक्षित और भरोसेमंद साथी साबित हो सकते हैं। जरूरत कुछ सावधानियां अपनाने की है।

टिप्स

आइए मानसून में इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े मिथकों और वास्तविकता को समझते हैं:

ईवी है, तो पानी का संपर्क खतरनाक हो सकता है?

बारिश में ईवी को लेकर सबसे बड़ा भ्रम करंट लगने का है। लोगों को लगता है कि पानी और बिजली का मेल खतरनाक हो सकता है और जलभराव वाले रास्तों पर ईवी चलाने से करंट लग सकता है। जबकि आधुनिक ईवी को इस तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इन्हें आमतौर पर आईईपी67 या आईपी65 जैसी वाटर- और डस्ट-रेसिस्टेंट रेटिंग मिलती है। साथ ही, किसी तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में ऑटोमैटिक शट-ऑफ सिस्टम तुरंत बिजली की सप्लाई बंद कर देता है, जिससे सुरक्षा और बढ़ जाती है।

क्या बारिश में ईवी को चार्ज करना सुरक्षित है?

बारिश में ईवी चार्ज करने पर करंट लगने का डर भी आम है। वास्तव में आधुनिक ईवी में चार्जिंग गन लगाते ही बिजली का प्रवाह शुरू नहीं होता। पहले कार और चार्जर के बीच 'डिजिटल हैंडशेक', यानी प्रारंभिक सुरक्षा की जांच होती है। कनेक्शन पूरी तरह सुरक्षित और वॉटरप्रूफ होने की पुष्टि के बाद ही चार्जिंग शुरू होती है। इसी वजह से मानकों के अनुरूप बनाए गए होम और पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बारिश में भी सुरक्षित चार्जिंग के लिए तैयार किए जाते हैं।

बिजली गिरने का डर है?

कुछ लोग मानते हैं कि बिजली चमकने के दौरान ईवी में बैठना सुरक्षित नहीं है। जबकि ईवी की धातु की बॉडी 'फैराडे केज' की तरह काम करती है। यानी बिजली गिरने पर धारा मुख्य रूप से कार के बाहरी हिस्से से होकर गुजरती है, जिससे केबिन के अंदर बैठे लोग अपेक्षाकृत सुरक्षित रहते हैं।

रेंज कम होने की चिंता है?

मानसून में वाइपर, एसी और डिफॉगर के इस्तेमाल से ईवी की रेंज तेजी से घटने की धारणा सही नहीं है। वाइपर, लाइट्स और डिफॉगर कम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनका रेंज पर असर सीमित रहता है। एसी का प्रभाव कुछ हो सकता है, लेकिन सामान्य उपयोग में यह बहुत ज्यादा नहीं होता। **रिया शर्मा**

कुछ जरूरी सावधानियां

जलभराव से बचें : यदि सड़क पर पानी का स्तर टायर के आधे हिस्से से ऊपर है, तो वहां गाड़ी ले जाने से बचें। यह बैटरी के साथ-साथ गाड़ी के सस्पेंशन, ब्रेक और इंटीरियर के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है।

सफाई का ध्यान रखें : चार्जिंग गन को कार में लगाने से पहले यह देख लें कि पोर्ट के अंदर पानी या नमी न हो। इसे हमेशा सूखे कपड़े से पोंछकर ही लगाएं।

प्रेशर वॉश : गाड़ी धोते समय नीचे की तरफ (जहां बैटरी पैक होता है) बहुत तेज प्रेशर वाले वॉटर जेट का प्रयोग करने से बचें, ताकि सील्स पर बेवजह का दबाव न बने।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : कला और संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि हो सकती है। कारोबार के लिए यात्रा पर जा सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होगी।

वृष : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। आय में वृद्धि होगी। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। पिता से धन मिलेगा।

मिथुन : मन परेशान हो सकता है। कारोबार में कुछ सुस्ती देखने को मिल सकती है। भागदौड़ अधिक रहेगी। लाभ में भी कमी आ सकती है। सेहत का ध्यान रखें।

कर्क : किसी मित्र से भेंट हो सकती है। मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि के साधन बन सकते हैं। कारोबार में निवेश भी हो सकता है। माता-पिता से धन मिल सकता है।

सिंह : आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ भी अधिक रहेगी। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें।

कन्या : कारोबारी कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा। वाहन के रखरखाव एवं वस्त्रों आदि पर खर्च बढ़ सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

तुला : किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है, परंतु परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। किसी मित्र का सहयोग भी मिल सकता है।

वृश्चिक : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। पिता की सेहत का भी ध्यान रखें। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी।

धनु : संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। नौकरी में तरक्की के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है। आय में वृद्धि होगी। सेहत का ध्यान रखें।

मकर : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। पिता की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। किसी संपत्ति से आय के साधन बन सकते हैं। वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ेंगे।

कुंभ : किसी अज्ञात भय से परेशान हो सकते हैं, परंतु परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा।

मीन : शैक्षिक एवं शोध आदि कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। कारोबार के लिए यात्रा लाभप्रद रहेगी। परिश्रम अधिक रहेगा। वाहन के रखरखाव एवं वस्त्रों पर खर्च बढ़ेंगे।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

11 जुलाई, शनिवार, **शक संवत्** : 20 आषाढ़ (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 27 आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम** : 25, मोहर्रम, 1448, **विक्रमी संवत्** : आषाढ़ कृष्ण द्वादशी रात्रि 02.05 मिनट तक पश्चात त्रयोदशी तिथि, कृतिका नक्षत्र प्रातः 11.04 मिनट तक पश्चात रोहिणी नक्षत्र, गण्ड योग रात्रि 12.06 मिनट तक पश्चात वृद्धि योग, चन्द्रमा वृष राशि में (दिन रात)

सूर्य उत्तरायण। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। योगिनी एकादशी व्रत (वैष्णव)।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

पूजा करते समय दीपक किस प्रकार जलाएं, ताकि लाभ हो-

- सोमवार को जब आप दीपक जलाएं, तो उसमें थोड़े से चावल डाल दें।
- मंगलवार को जब दीपक जलाएं, तो उसमें साबुत लौंग डाल दें। इससे कष्ट दूर होते हैं।
- बुधवार को दीपक जलाते हैं, तो उसमें एक हरी इलायची डाल दें। इससे धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। गुरुवार को जब दीपक जलाते हैं, तो उसमें थोड़ी हल्दी डालें। इससे घर में खुशहाली आती है।
- शुक्रवार को दीपक जलाने पर उसमें थोड़े चावल एवं लौंग डाल दें। इससे जीवन में ऐश्वर्य बढ़ता है। शनिवार को दीपक जलाने पर काले तिल डालने से संकटों का नाश होता है।

वर्ग पहेली : 8386

■	1	■	2	■	3	4		5
6				7	■		■	
■		■	8					
9	■	10	■		■			
11				■	12			
	■		■	13	■		■	
14					15	■	16	■
	■		■	17				
18				■		■		■

बाएं से दाएं
3. अनर्गल; अनुचित; असंबद्ध; तर्कहीन (4)
6. ताकत देने वाला; शक्तिदायक (5)
8. बार बार; रुक रुक कर (2,2,2)
11. बारीक सूत से बुना पतला कपड़ा (4)
12. चिंता; व्यग्रता; ध्यान; भरोसा; बहाव (4)
14. घटवाना; निकलवाना (2,4)
17. रास्ता दिखाना; मार्ग दिखाना (2,3)
18. सूंड; तुलसी (4)

ऊपर से नीचे
1. अंतर मिटना; साथ लगना; सटना; सम्मिलित होना; भेंट करना (3)
2. डरपोक; भीरु; कातर (3)
4. आशंका करना; शक करना; संशय करना (3,3)
5. उद्यत रहना; तैयार रहना; सन्नद्ध रहना (3,3)
7. बोलना; प्रकट करना; सूचना देना; सुनाना; आदेश (3)
9. वक्त कटना; समय व्यतीत होना (3,3)
10. चढ़ाई करना; धावा बोलना (3,3)
13. उद्देश्यहीन घूमने वाला; जिसके रहने आदि का कोई ठौर-ठिकाना न हो; दुष्ट, निकम्मा; पाजी (3)
15. निष्प्रयोजन; व्यर्थ; बेमतलब; बिना किसी बात के (3)
16. कसरत करने या कुश्ती लड़ने के लिए मुलायम मिट्टी भरा चौकोर स्थान; मल्लयुद्ध के लिए बना स्थान; साधुओं की जमायत; साधुओं के रहने का स्थान (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8385

■	1 ला	■	2 या	3 च	ना	4 क	र	5 ना
6 मं	ज	न	■	र	■	लं	■	च
■	वं	■	7 स	वा	ल	क	र	ना
8 प्र	ती	9 क	■	हा	■	ल	■	न
थ	■	10 म	न	■	11 धा	गा	■	चा
म	■	ल	■	12 अ	■	13 ना	14 प	ना
15 प्र	धा	न	से	व	क	■	ट	■
या	■	य	■	स	■	16 कि	वा	ड़
17 स	ह	न	क	र	ना	■	री	■

सुडोकू : 8340

*कठिन

			3			6	9	
	3	8			9	2		
	6				2	4		
5			1				2	
	9				3			4
		4	6				8	
		5	8			1	7	
	8	6			1			

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8339

3	9	5	7	8	1	2	4	6
7	8	2	3	6	4	5	9	1
4	1	6	5	9	2	8	3	7
2	4	3	9	5	6	7	1	8
8	5	1	4	7	3	9	6	2
9	6	7	2	1	8	3	5	4
5	2	9	6	4	7	1	8	3
6	7	8	1	3	9	4	2	5
1	3	4	8	2	5	6	7	9

चिंतन

ई20 पेट्रोल से होने वाला लाभ वाहन चालकों को क्यों नहीं

सरकार ने आखिरकार वह स्वीकार कर लिया है, जिसकी चर्चा लंबे समय से वाहन उपभोक्ताओं और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों के बीच होती रही थी। पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण कुछ वाहनों में ईंधन दक्षता यानी माइलेज को 3 से 5 प्रतिशत तक कम कर सकता है। सरकार का कहना है कि यह कमी बेहतर इंजन प्रदर्शन, कम प्रदूषण और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने जैसे दीर्घकालिक लाभों के सामने छोटी है। दरअसल ई20 को लेकर विवाद का केंद्र केवल माइलेज नहीं है, बल्कि यह सवाल भी है कि क्या ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर उपभोक्ता पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। पहली बार आधिकारिक तौर पर यह माना गया है कि माइलेज में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि ई20 का उद्देश्य पेट्रोल सस्ता करना नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा अर्थव्यवस्था को अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है। ऐसे में जैव-ईंधन (बायोफ्यूल) की ओर बढ़ना केवल पर्यावरणीय विकल्प नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता भी है। इसी सोच के तहत वर्ष 2001 में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 2022 में भारत ने निर्धारित समय से पहले 10 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया और 2025-26 में 20 प्रतिशत मिश्रण तक पहुंच गया। इस कार्यक्रम से अब तक लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और लगभग 952 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हुआ है। साथ ही किसानों को एथेनॉल खरीद के माध्यम से 1.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान हुआ है। इसने ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण आय जैसे तीनों लक्ष्यों को एक साथ साधने का काम किया है। क्या इन उपलब्धियों का लाभ सीधे वाहन मालिकों तक भी पहुंच रहा है? यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि किसी वाहन का माइलेज 3 से 5 प्रतिशत कम होता है, तो वाहन चालक को समान दूरी तय करने के लिए अधिक ईंधन खरीदना पड़ेगा। यदि पेट्रोल की कीमत में कोई राहत नहीं मिलती और ई20 पारंपरिक पेट्रोल से सस्ता भी नहीं है, तो उपभोक्ता के लिए वास्तविक परिचालन लागत बढ़ सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब कच्चा तेल सस्ता होता है, तब एथेनॉल की लागत पेट्रोल से अधिक भी हो सकती है। इसका अर्थ है कि ई20 को केवल सस्ते ईंधन के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई20 को लेकर वाहन सुरक्षा संबंधी आशंकाएं व्यापक परीक्षणों के बाद ही दूर की गई हैं। यदि ई20 एक राष्ट्रीय रणनीति है, जिसका लाभ पूरे देश को मिलेगा तो क्या उसका आर्थिक भार केवल वाहन उपभोक्ताओं को उठाना चाहिए? क्या सरकार को कर संरचना, मूल्य निर्धारण या अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से इस अतिरिक्त लागत का कुछ हिस्सा स्वयं वहन नहीं करना चाहिए? इसी प्रकार, यदि माइलेज में कमी वैज्ञानिक तथ्य है, तो इसकी स्पष्ट जानकारी वाहन खरीदते समय उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसी भी बड़े सुधार की सफलता केवल उसके उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन और जनता की स्वीकृति से तय होती है। यदि देश ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, तो इस यात्रा में नागरिकों का विश्वास भी उतना ही आवश्यक है जितना उनका योगदान। ऊर्जा परिवर्तन तभी टिकाऊ होगा, जब उसका लाभ और उसकी लागत दोनों समाज के सभी वर्गों के बीच संतुलित रूप से साझा किए जाएं।

आर्थिकी
महेन्द्र तिवारी

समुद्र पर बनेगा भारत का हवाई अड्डा

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के निकट पालघर जिले के कोरे बीच के पास भारत का पहला ऑफशोर अर्थात समुद्र आधारित हवाई अड्डा विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यदि यह परियोजना निर्धारित योजना के अनुसार साकार होती है तो यह केवल एक नया एयरपोर्ट नहीं होगा, बल्कि भारत की विमानन क्षमता, समुद्री इंजीनियरिंग, व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास का नया प्रतीक बनेगा। यह परियोजना देश को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा कर सकती है, जिन्होंने समुद्र से भूमि तैयार कर विश्वस्तरीय हवाई अड्डों का निर्माण किया है।

भारत की आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा आधार उसकी आधुनिक अवसंरचना है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने सड़क, रेल, बंदरगाह, मेट्रो, एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डों के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार देखा है। अब इसी श्रृंखला में एक और ऐतिहासिक पहल जुड़ने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के निकट पालघर जिले के कोरे बीच के पास भारत का पहला ऑफशोर अर्थात समुद्र आधारित हवाई अड्डा विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यदि यह परियोजना निर्धारित योजना के अनुसार साकार होती है तो यह केवल एक नया एयरपोर्ट नहीं होगा, बल्कि भारत की विमानन क्षमता, समुद्री इंजीनियरिंग, व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास का नया प्रतीक बनेगा। यह परियोजना देश को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा कर सकती है, जिन्होंने समुद्र से भूमि तैयार कर विश्वस्तरीय हवाई अड्डों का निर्माण किया है। ऑफशोर एयरपोर्ट का विचार अपने आप में अत्यंत आधुनिक और दूरदर्शी है। सामान्यतः हवाई अड्डे विशाल भूमि पर बनाए जाते हैं, लेकिन महानगरों में भूमि की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है।

बढ़ती आबादी, तेजी से फैलते शहर और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी सामाजिक तथा कानूनी चुनौतियां नई परियोजनाओं को कठिन बना देती हैं। ऐसे में समुद्र के भीतर कृत्रिम भूमि तैयार कर उस पर एयरपोर्ट का निर्माण एक व्यावहारिक विकल्प बनकर उभरा है। अरब सागर में पुनः प्राप्त भूमि पर बनने वाला यह एयरपोर्ट भारतीय इंजीनियरिंग क्षमता की नई पहचान बनेगा। प्रस्तावित एयरपोर्ट की क्षमता इसे विश्व के प्रमुख हवाई अड्डों की श्रेणी में ला सकती है। योजना के अनुसार यहां प्रतिवर्ष लगभग 9 करोड़ यात्रियों के आवागमन और लगभग 30 लाख मीट्रिक टन कार्गो की आवाजाही की व्यवस्था होगी। दो समानांतर रनवे विकसित किए जाने की भी योजना है, जिससे बड़ी संख्या में विमानों का संचालन संभव हो सकेगा। यह क्षमता केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों की मांग को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। भारत में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यह परियोजना भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की जा रही है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। यहां स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल है। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के बावजूद भविष्य में यात्रियों और माल परिवहन की बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रस्तावित ऑफशोर एयरपोर्ट इस चुनौती का दीर्घकालिक समाधान बन सकता है। इससे न केवल मुंबई क्षेत्र के हवाई यातायात का दबाव कम होगा बल्कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और माल परिवहन के लिए भी नई संभावनाएं खुलेंगी। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका बहुआयामी संपर्क तंत्र है। प्रस्तावित एयरपोर्ट को वधावन बंदरगाह, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे तथा प्रस्तावित उत्तन विरार सी लिंक से जोड़ने की योजना है। इसके अतिरिक्त समर्पित माल

गलियारे और अन्य सड़क संपर्क भी विकसित किए जाएंगे। इससे हवाई, समुद्री, रेल और सड़क परिवहन का ऐसा समन्वित नेटवर्क तैयार होगा जो भारत में मल्टीमॉडल परिवहन का उत्कृष्ट उदाहरण बन सकता है। वधावन बंदरगाह स्वयं भारत की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री परियोजनाओं में गिना जा रहा है। यदि उसके साथ विशाल कार्गो क्षमता वाला एयरपोर्ट भी विकसित हो जाता है तो पश्चिमी भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का नया केंद्र उभर सकता है। समुद्री मार्ग से आने वाला माल कम समय में हवाई मार्ग से देश और विदेश भेजा जा सकेगा। हवाई मार्ग से आने वाला उच्च मूल्य का सामान सीधे बंदरगाह तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे निर्यात और आयात दोनों क्षेत्रों को गति मिलेगी तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। स्थानीय युवाओं को निर्माण, विमानन, आतिथ्य, सुरक्षा, परिवहन और तकनीकी सेवाओं में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन भी कम हो सकता है। इतनी विशाल परियोजना के साथ कई तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। समुद्र से भूमि तैयार करना अत्यंत जटिल इंजीनियरिंग कार्य है। किसी भी बड़े विकास कार्य में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। यदि इन पहलुओं की अनदेखी की गई तो दीर्घकाल में परियोजना को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य से इस्पात, सीमेंट, मशीनरी, इंजीनियरिंग, परिवहन और निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना पूर्ण होने के बाद विमानन, पर्यटन, व्यापार, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और निर्यात आधारित उद्योगों में नई ऊर्जा आएगी। विदेशी निवेशकों के लिए भी यह क्षेत्र अधिक आकर्षक बन सकता है क्योंकि आधुनिक परिवहन अवसंरचना निवेश का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। इससे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे पश्चिमी भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। भारत ने पिछले दशक में विमानन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। छोटे शहरों तक हवाई सेवाएं पहुंचाने की योजनाओं से लेकर नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण तक अनेक प्रयास किए गए हैं। आज भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में शामिल है। ऐसे समय में ऑफशोर एयरपोर्ट जैसी परियोजना यह संकेत देती है कि देश केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक योजना बना रहा है। हालांकि परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि योजना निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक सभी चरणों में पारदर्शिता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए। स्थानीय समुदायों की चिंताओं को समझना, पर्यावरणीय प्रभावों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना, वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और समयबद्ध निर्माण करना उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना स्वयं एयरपोर्ट का निर्माण। यदि इन सभी पहलुओं पर संतुलित ढंग से कार्य किया गया तो यह परियोजना केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए विकास का नया मॉडल बन सकती है। भारत आज उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहां अवसंरचना केवल सुविधाओं का विस्तार नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय आत्मविश्वास का आधार बन चुकी है। पालघर के समुद्र में प्रस्तावित यह ऑफशोर एयरपोर्ट उसी बदलते भारत की कहानी कहता है जो सीमित संसाधनों में भी नए समाधान खोजने का साहस रखता है। यदि यह सपना साकार होता है तो यह केवल समुद्र पर बना एक हवाई अड्डा नहीं होगा, बल्कि भविष्य के भारत की दूरदृष्टि, तकनीकी क्षमता और विकास के संकल्प का जीवंत प्रतीक बनकर उभरेगा।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

जनसंख्या दिवस
राजेश जैन

148 करोड़ लोग: भारत की सबसे बड़ी ताकत या चुनौती

आज के दिन 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया की बढ़ती आबादी के आंकड़ों की चर्चा का अवसर बनता है, लेकिन भारत के लिए इसका महत्व इससे कहीं अधिक है। यह केवल जनसंख्या गिनने का दिन नहीं, बल्कि यह सोचने का अवसर है कि क्या देश अपनी सबसे बड़ी मानव पूंजी को विकास की ताकत बना पाएगा या यही आबादी भविष्य में सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। आज भारत लगभग 148 करोड़ लोगों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। एक वर्ग इसे देश की सबसे बड़ी शक्ति मानता है, जबकि दूसरा इसे बेरोजगारी, संसाधनों पर बढ़ते दबाव और सामाजिक असमानता की वजह मानता है। सच यह है कि आबादी अपने आप में न ताकत होती है और न बोझ। उसकी दिशा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और रोजगार तय करते हैं। किसी भी देश की वास्तविक ताकत उसके नागरिकों की गुणवत्ता से तय होती है। यदि लोग शिक्षित, स्वस्थ और कुशल हैं तो बड़ी आबादी आर्थिक विकास का इंजन बन जाती है। कमजोर शिक्षा, सीमित रोजगार और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था उसी आबादी को विकास में बाधा बना देती है। चीन ने दशकों तक प्रशिक्षित कार्यबल के दम पर दुनिया की फैक्ट्री बनने का गौरव हासिल किया, लेकिन आज वहां तेजी से बढ़ती वृद्ध आबादी नई चुनौती बन गई है। भारत की स्थिति अलग है। यहां औसत आयु लगभग 29 वर्ष है और करीब 65 प्रतिशत आबादी कार्यशील आयु वर्ग में है। हमारे लिए यह जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन यह अवसर स्थायी नहीं है। यदि आने वाले वर्षों में शिक्षा, कौशल और रोजगार पर पर्याप्त निवेश नहीं हुआ तो यही लाभांश भविष्य में आर्थिक और सामाजिक दबाव में बदल सकता है। भारत केवल आबादी के लिहाज से बड़ा नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे आकर्षक उपभोक्ता बाजारों में भी शामिल है। यही वजह है कि वैश्विक कंपनियां भारत को अगले दो दशकों का सबसे महत्वपूर्ण बाजार मान रही हैं। डिजिटल इंडिया और यूपीआई जैसी पहलों ने इस क्षमता को नई गति दी है। इंटरनेट गांवों तक पहुंचा है, डिजिटल भुगतान आम हो चुका है और स्टार्टअप संस्कृति ने युवाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। इन उपलब्धियों के बावजूद एक बड़ी चुनौती सामने है। हर साल लाखों युवा रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं, लेकिन उद्योगों को योग्य कर्मचारी नहीं मिलते और युवाओं को उनकी क्षमता के अनुरूप रोजगार नहीं मिलता। समस्या केवल नौकरियों की संख्या नहीं, बल्कि रोजगार योग्य कौशल की भी है। यहीं सरकार की नीतियों की असली परीक्षा शुरू होती है। पिछले एक दशक में नई शिक्षा नीति, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आयुष्मान भारत जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गईं। इनसे नए अवसर जरूर बने हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं।

नई शिक्षा नीति कौशल आधारित शिक्षा पर जोर देती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी, डिजिटल संसाधनों का अभाव और राज्यों के बीच असमानताएं इसकी राह कठिन बनाती हैं। स्किल इंडिया ने प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाया है, लेकिन उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल अभी भी जरूरी है। स्टार्टअप इंडिया ने नवाचार को बढ़ावा दिया है, हालांकि इसका लाभ अभी मुख्य रूप से बड़े शहरों तक सीमित है। छोटे शहरों और ग्रामीण भारत को भी इस बदलाव से जोड़ना होगा। इतनी बड़ी आबादी वाले देश के लिए मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था अनिवार्य है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने लाखों परिवारों को राहत दी है, लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टरों की उपलब्धता, कुपोषण और मानसिक स्वास्थ्य जैसी चुनौतियां अभी भी गंभीर हैं। इसी तरह महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाए बिना भारत अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर सकता। भारत के लिए अगले 20 से 25 वर्ष निर्णायक हैं। 148 करोड़ लोगों का देश होना न उपलब्धि है और न समस्या। असली सवाल यह है कि इन लोगों में कितने शिक्षित, स्वस्थ, कुशल और उत्पादक हैं। यदि भारत अपनी मानव पूंजी में सही निवेश करता है तो यही आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यदि यह अवसर चूक गया, तो यही संख्या भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती भी साबित हो सकती है। विश्व जनसंख्या दिवस हमें यही याद दिलाता है कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उसके नागरिक होते हैं। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा मानव पूंजी है। अब यह देश पर निर्भर है कि वह इसे विकास की सबसे बड़ी शक्ति बनाता है या एक चूके हुए अवसर में बदल देता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मुंह के मौन से ज़्यादा ज़रूरी 'मन का मौन'

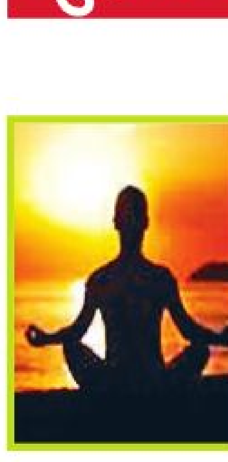

संकलित
दर्शन

हम सभी मनुष्य जन्मते ही अपना मुख चलाना शुरू कर देते हैं, जिसका प्रमाण है जन्म लेते ही शिशु का रोना। बोलना हमारी स्वाभाविक क्रिया है, जो हमें करनी ही पड़ती है। यह बात और है कि कभी-कभी बाहर के शोर में हम इतने खो जाते हैं कि ईश्वर का स्वर हमें सुनाई ही नहीं पड़ता। इसीलिए ही महापुरुषों से हमें एक उत्तम राय मिलती है कि सप्ताह में या माह में एक दिन अवश्य मौन रहें, परंतु हम मुख को तो बंद कर लेते हैं, परंतु हमारे मन का बोलना बंद नहीं हो पाता। इसलिए ही तो अधिकतर डाक्टर सभी मरीजों को कहते हैं कि 'अपने मन को ज्यादा नहीं चलाओ।' अर्थात 'मन का मौन' करो। कहते हैं कि बिना हड्डी की जीभ जब बोलने लगती है, तो कइयों की हड्डियां तोड़ देती है। इसीलिए तो हमें यह बचपन से सिखाया जाता है कि पहले सोचो फिर बोलो, क्योंकि जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुख से निकला हुआ वचन भी वापस नहीं लिया जा सकता। इसका सबसे श्रेष्ठ उदहारण है महाभारत की कथा, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि कैसे एक जुबान के फिसलने से संकटकाल का निर्माण हो गया। इसीलिए 'कम बोलें-धीरे बोलें-मीठा बोलें।' हम जब भी कुछ बोलें तो हमारे वचन दूसरों के लिए सुखदायी हों, न कि कांटा चुभाने वाले दुखदायी। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने कटु वचन बोलने के संस्कार के कारण अपने संबंधों में खटास पैदा कर ली है। इसलिए हमें सदैव सही समय और सही जगह पर सही शब्द का प्रयोग करना चाहिए।

एक दिन का पुण्य ही क्यूँ?

संकलित
प्रेरणा

निर्जला एकादशी से अगले दिन एक भिखारी एक सज्जन की दुकान पर भीख मांगने पहुंचा। सज्जन व्यक्ति ने 1 रुपए का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया। भिखारी को प्यास भी लगी थी, वो बोला बाबूजी एक गिलास पानी भी पिलवा दो, गला सूखा जा रहा है। सज्जन व्यक्ति ने गुस्से में कहा: तुम्हारे बाप के नौकर बैठे हैं क्या हम यहां, पहले पैसे, अब पानी, थोड़ी देर में रोटी मांगेगा, चल भाग यहाँ से। भिखारी बोला: बाबूजी गुस्सा मत कीजिये मैं आगे कहीं पानी पी लूंगा। पर जहां तक मुझे याद है, कल आपने निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ किया था, तथा कल इसी दुकान के बाहर मीठे पानी की छबील लगी थी और आप स्वयं लोगों को रोक रोक कर जबरदस्ती अपने हाथों से गिलास पकड़ा रहे थे, मुझे भी कल आपके हाथों से दो गिलास शर्बत पीने को मिला था। मैंने तो यही सोचा था, आप बड़े धर्मात्मा आदमी है, पर आज मेरा भरम टूट गया। कल की छबील तो शायद आपने लोगों को दिखाने के लिये लगाई होगी? मुझे आज आपने कड़वे वचन बोलकर अपना कल का सारा पुण्य खो दिया। मुझे छमा करना अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ तो। सज्जन व्यक्ति को बात दिल पर लगी, उसकी नजरों के सामने बीते दिन का प्रत्येक दृश्य घूम गया। उसे अपनी गलती का अहसास हो रहा था। वह स्वयं अपनी गद्दी से उठा और अपने हाथों से गिलास में पानी भरकर उस बाबा को देते हुए उसे क्षमा प्रार्थना करने लगा। भिखारी: बाबूजी मुझे आपसे कोई शिकायत नही, परन्तु अगर मानवता को अपने मन की गहराइयों में नही बसा सकते तो एक-दो दिन किये हुए पुण्य कार्य व्यर्थ ही हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन से होगा हरित रेल क्रांति का आगाज

भारतीय रेल केवल देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक परिवहन तंत्र नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक प्रगति की जीवनरेखा भी है। लगभग डेढ़ शताब्दी पहले भाप के इंजनों से शुरू हुई इसकी यात्रा आज अत्याधुनिक तकनीकों के नए युग में प्रवेश कर चुकी है। वंदे भारत, अमृत भारत, समर्पित माल गलियारे 'कवच' जैसी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली और व्यापक विद्युतीकरण के बाद अब भारतीय रेल हाइड्रोजन फ्यूल-सेल तकनीक के साथ एक और ऐतिहासिक उपलब्धि की दहलीज पर खड़ी है। विगत दिनों दिल्ली-जींद रेलखंड पर स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण इस बात का संकेत है कि भारत हरित, आत्मनिर्भर और भविष्य उन्मुख रेल व्यवस्था की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है।

-विनोद यादव, बिलासपुर

ट्रेंड

भारत-न्यूज़ीलैंड की दोस्ती

नाद वोकल एन्सेम्बल की शानदार प्रस्तुति देखकर बहुत खुशी हुई। संगीत में लोगों को एक साथ लाने की अनोखी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत-न्यूज़ीलैंड की दोस्ती की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से दर्शाया।

- **नरेंद्र मोदी**, प्रधानमंत्री

रेड्डी का गणित कमजोर

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का गणित कमजोर है। वे बार-बार कहते हैं कि केंद्र ने कुछ नहीं दिया। कांग्रेस के ये लोग बस एक ही बात दोहराते हैं: वे खुद कुछ कमा नहीं सकते और दूसरों का सहारा लेना बंद नहीं करेंगे! हिमाचल प्रदेश में भी वे यही करते हैं।

- **जगत प्रकाश नड्डा**, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

16 पार्षद भाजपा में शामिल

आज दिल्ली की प्रगति और जनसेवा के संकल्प को नई मजबूती मिली है। इंद्रप्रस्थ डेवलपमेंट पार्टी के सोलह पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्षदों का यह निर्णय राजधानी के विकास कार्यों को नई गति देगा।

- **रेखा गुप्ता**, सीएम, नई दिल्ली

अप्रेंटिसशिप जरूरी

अब भारत में अप्रेंटिसशिप की बड़े पैमाने पर वापसी के लिए सही समय आ गया है। मैन्युफैक्चरिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एआई व नई टेक्नोलॉजी के आने के साथ, 'काम करते हुए सीखना' ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है।

- **अनिल अग्रवाल**, उद्यमी

करंट अफेयर

10 लाख महिलाओं को मदद मिलनी बंद हो गई : संरा

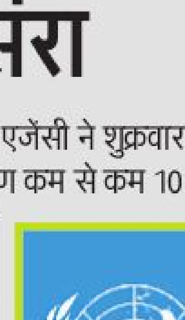

महिलाओं के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 18 महीनों में बजट में कटौती के कारण कम से कम 10 लाख महिलाओं को मानवीय और अन्य जरूरी मदद नहीं मिल पा रही है। एजेंसी 'यूएन वीमेन' का कहना है कि सर्वेक्षण में शामिल 84 प्रतिशत महिला संगठनों ने बताया है कि जनवरी 2025 से उनकी जरूरतें बढ़ गई हैं। इसी समय अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली थी और विदेशी मदद में कटौती शुरू की थी। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को सबसे ज्यादा वित्तीय सहायता देने वाला देश है। एजेंसी की शीर्ष अधिकारी सोफिया कॉलटॉर्प ने कहा, ''महिलाओं के संगठनों से वापस लिया गया हर डॉलर, यौन हिंसा की शिकार महिलाओं, विस्थापित माताओं, स्कूल छोड़ने पर मजबूर लड़कियों और जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे समुदायों से वापस लिया गया डॉलर है।'' सर्वेक्षण में शामिल लगभग 90 प्रतिशत महिला समूहों ने कहा कि वे अब जरूरत के मौजूदा स्तर को पूरा नहीं कर सकते, और हर पांच में से एक समूह ने कहा कि उन्हें आशंका है कि वे अगले साल कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए कामकाज बंद कर देंगे।

ऑफ बीट

युवाओं में बढ़ रहा कम उम्र में जुए की लत का खतरा

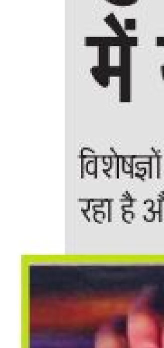

विशेषज्ञों का कहना है कि युवाओं में कम उम्र में जुए की लत लगने का खतरा बढ़ रहा है और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को जुए के विज्ञापनों और उद्योग पर कड़े नियंत्रण लगाने के साथ-साथ परिवारों को भी बच्चों को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना होगा। अध्ययन के अनुसार आठ प्रतिशत से अधिक वयस्क किसी न किसी रूप में जुए के दुष्प्रभावों से प्रभावित हैं, जबकि लगभग एक प्रतिशत वयस्क अत्यधिक जोखिम वाले स्तर पर जुआ खेलते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि 18 से 34 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं पर विशेष रूप से जुए की लत का जोखिम है। नियमित रूप से 'पोकी' (पोकर मशीन) और ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले इस आयु वर्ग के लगभग 90 प्रतिशत लोगों को आर्थिक नुकसान, रिश्ते टूटने और अन्य गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार, पोकर मशीन और ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसे जुए के कुछ स्वरूप अन्य की तुलना में अधिक नुकसानदेह हैं और इनसे लत लगने की आशंका अधिक रहती है। उन्होंने कहा कि जुए से होने वाला सबसे आम नुकसान आर्थिक होता है। इसमें खर्च के लिए कम धन बचने से लेकर जीवनभर की बचत या मकान तक गंवाने जैसी गंभीर स्थितियां शामिल हैं।

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

‘सतलज’चे सत्य!

वादग्रस्त कलम वापरून ‘ओटीटी’वरूनही चित्रपट काढून टाकणारे केंद्रीय माहिती व प्रसारण खाते आता, आंतरविभागीय चौकशी समिती नेमून कारणांची शोधाशोध करणार!

तथ्य निष्पक्ष असू शकते किंवा किमान तसा दावा करू शकते. तथ्यांवर आधारित असे जे काही असते ते अखेर काही तथ्यांची निवड करणारे- म्हणजे निवडकच असते. याला ‘कलात्मक सत्य’ म्हणता येईल एक वेळ; पण ते समजा एखादीच बाजू घेणारे असेल, तर ते कुणासाठी तरी गैरसोयीचे म्हणून दाखवायचेच नाही का? शिवाय, जे दाखवले आहे तेच सत्य, असा आग्रह ही निवड करणाऱ्यांनी तरी का धरायचा? घटिताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा ज्याचे-त्याचे सत्य असते. श्रेष्ठ जपानी दिग्दर्शक अकिरा कुरोसावा ‘राशोमोन’ चित्रपटात मांडू पाहतात तसे. ‘राशोमोन’च्या प्रदर्शनानंतर ७६ वर्षांनीही हा ‘राशोमोन परिणाम’ चित्रपटकर्ते आणि त्याचे नियमन करू पाहणाऱ्या वर्तुळाला व्यापून उरलाच आहे. एखाद्या आत्मवर्णनपर चित्रपटातील (बायोपिक) तथ्यांमधून जे काही कलात्मक सत्य आपल्यासमोर येते त्याचाही त्रास व्हावा, इतका. बहुचर्चित ‘सतलज’ चित्रपटाचे रखडणे, मग गुपचूप ओटीटी मंचावर येऊन, तेथून जाताना आणि गेल्यानंतर गाजावाजा करत राहणे, यात हे वरील सगळे आहे. काहींनीच का कायम सहिष्णू राहायचे, असे तर्कट मांडून असहिष्णू होण्याची निमित्ते अलीकडे शोधाल तितकी सापडत जातात. त्यातून चित्रपट, मालिका वगैरे तर चर्चा घडविण्यासाठी मोठी व्यासपीठे. याचे ‘सतलज’ हे ताजे उदाहरण. त्याभोवतीची घुसळण ही फक्त त्याच्या आशय-विषयापुरती मर्यादित नाही. ती अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या आणि त्याच्या ‘वाजवी’ मर्यादेच्याही मुद्द्यांना स्पर्श करते. म्हणून, त्यावर भाष्य आवश्यक.

आधी या चित्रपटाबद्दल थोडे. त्याचा काळ १९९० च्या दशकातील. पंजाबमध्ये १९८४ मध्ये झालेले ऑपरेशन ‘ब्लू स्टार’, त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या, त्यानंतर झालेले शीखविरोधी दंगे आणि त्यातून पुन्हा फुटीरतावादी खलिस्तानी चळवळीला मिळालेले बळ हा इतिहास नाकारता न येणारा. या फुटीरतावादाचा बीमोड करायला साधारण एक दशक लागले. तो करणारे पोलीस अधिकारी केपीएस गिल यांच्या कामगिरीची तारीफही केली गेली. मात्र, अतिरेक्यांचे दमन करताना अनेक निरपराधही त्यात भरडले गेले, असा आरोपही होत राहिला. ‘सतलज’ याच मुद्द्याला हात घालतो. या काळात निरपराध नागरिकांना उचलून पोलिसांनी त्यांचे शिरकाण केले, असे तो मांडतो.

नव्वदच्या दशकात नागरिकांच्या या गायब होण्यामागचे गूढ उकलण्यासाठी जसवंतसिंग खालरा हे बँकेतील एक अधिकारी पुढे आले. त्यांना अमृतसरमधील काही स्मशानांतून बेवारस म्हणून नोंद झालेल्या मृतदेहांच्या याद्या मिळाल्या. याद्यांमध्ये मृताचा नाव-पत्ता असेल तर मृतदेह बेवारस कसा, या प्रश्नातून त्यांचा शोध व्यापक झाला. पूर्ण पंजाब राज्यात असे सुमारे २५ हजार मृतदेह बेवारस दाखवल्याचा दावा जसवंतसिंग यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केला. पुढे मात्र ते स्वतःच गायब झाले. या प्रकरणाचा खटला चालला आणि जसवंतसिंग यांना ताब्यात घेऊन मारल्याबद्दल दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना काही वर्षांनंतर शिक्षाही सुनावली गेली. विषयच इतका संवेदनशील असल्याने तो प्रदर्शित होण्यात अडथळे आले. नावापासून दृश्यांवरील आक्षेपांपर्यंतची भरच पडत गेली. म्हणजे, २०२२ मध्ये हा चित्रपट तयार होऊन केंद्रीय चित्रपट प्रमाणीकरण मंडळाकडे (सीबीएफसी) अर्थात सेन्सॉर बोर्डाकडे गेला, तेव्हा आधी २१ दृश्यांना कात्री लावावी लागेल, अशी सूचना आली. ज्यात हळूहळू वाढ होत जाऊन संख्या १२७ वर गेली. दिग्दर्शक हनी त्रेहान यांनी या सूचनांमुळे ‘पंजाब ९५’ हे नाव बदलून ‘सतलज’ केले आणि काही दृश्यांना कात्री लावण्याची तयारीही दाखवली, पण १२७ दृश्ये कापल्यावर चित्रपटात उरणार तरी काय, असा प्रश्न पडला. याविरोधात मग निर्माते मुंबई उच्च न्यायालयात गेले, पण तेथून ते स्वतःच बाहेर पडले. काही खासगी खेळांखेरीज चित्रपटगृहांत हा चित्रपट आलाच नाही.

...हे जिथे चालून जाते, अशा समाजात वाद-संवादापेक्षा ओरडच अधिक होते...

गेल्या शुक्रवारी मात्र तो अचानकच ‘झी फाइव्ह’ या ओटीटी मंचावर कोणत्याही दृश्यकपातीविना प्रदर्शित झाला. ओटीटी मंचावरील प्रदर्शनासाठी ‘सीबीएफसी’चे प्रमाणपत्र लागत नाही, हा त्यातील तांत्रिक मुद्दा. मात्र ‘समाजमाध्यम-विरोधी कायदा’ म्हणून वादग्रस्त ठरलेल्या ‘माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०२१’चे कलम ६९ हे ‘ओटीटी’वर प्रदर्शित होणाऱ्या कलाकृतींनाही लागू पडते, याचा आधार घेऊन दोनच दिवसांत तो ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’च्या कारणास्तव ‘झी फाइव्ह’वरून काढला गेला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण खात्याने आता आंतरविभागीय चौकशी समिती नेमून चित्रपटातील आशय तपासणार असल्याचे जाहीर केले आहे. म्हणजे आधी बंदी, मग कारणांची शोधाशोध!

हा चित्रपट जे दोन दिवस ‘ओटीटी’वर दिसला, तेव्हा तो हजारो प्रेक्षकांनी पाहून त्यावर समाजमाध्यमांवर लिहायला सुरुवात केली. त्यात समीक्षकही आहेत. काहींच्या मते, ही उत्तम कलाकृती असून, अभिनय, दिग्दर्शन, काळउभारणी, चित्रचौकटी, पार्श्वसंगीत अशा सर्वच बाबतींत तो सरस आहे. जसवंतसिंग खालरा यांचे काय झाले, याची गोष्ट तो सांगत असेल, तर त्यावर बंदी घालणे योग्य नाही. दुसरीकडे, काहींनी आशयाबाबत आणि चित्रपटकर्त्यांच्या हेतूंबाबत मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. चित्रपटातील मुख्यमंत्र्याच्या पात्राची (हे पात्र काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंतसिंग यांच्यावर बेतले आहे.) हत्या दाखवताना, हत्या करणाऱ्याची भलामण करणारा वाटावा, असा हा प्रसंग आणि त्याचे पार्श्वसंगीत असल्याचा आरोप आहे. ज्या मानवतावादाची बाजू हा चित्रपट घेत असल्याचा दावा त्याचे कर्ते करतात, त्यांना हे कृत्य अमानुष का वाटू नये, असा सवाल त्यानिमित्ताने उपस्थित झाला. शिवाय १९८४ नंतर पंजाबमध्ये खलिस्तानवादी अतिरेक्यांची ज्या प्रकारची दहशत होती, त्या पार्श्वभूमीला चित्रपटाने टाळणे योग्य नाही, असाही सूर व्यक्त होतो. पंजाब विधानसभेची निवडणूक काही महिन्यांत असताना अकाली दल, काँग्रेस आणि ‘आप’ने चित्रपटावरील बंदी उठवण्याची मागणी केली आहे, तर माजी मुख्यमंत्री बेअंतसिंग यांचे सध्या भाजपमध्ये असलेले नातू रवनीतसिंग बिट्टू यांनी चित्रपटाबद्दल बोलताना, ‘पंजाबला पूर्ण सत्य सांगा, अर्धवट नको,’ असे म्हटले आहे.

‘पूर्ण सत्य’ असे काही एखाद्याच कलाकृतीत नसते. पण एखादा घटनाक्रम एखाद्या लेखक-दिग्दर्शकाला त्याच्या आकलनानुसार काढलेल्या अर्थान्वयानुसार दाखवावासा वाटला, तर त्यावर थेट बंदी का? अभिव्यक्तीला मोकळीक देऊन त्यावर खुली चर्चा होणे हे निरोगी समाजाचे लक्षण. चित्रपटातील म्हणणे एखाद्याला न पटल्यास त्यावर टीकेचा, प्रत्युत्तराचा हक्क असतोच. उदाहरणार्थ, ‘सतलज’ सत्याचा अपलाप करतो, असे कुणाला साधार म्हणावेसे वाटले, तर त्याबाबतही स्वीकारशील असायला हवे- अगदी चित्रपट तयार करणाऱ्यांनीही. पण ते सोडून मूळ कलाकृतीची मुस्कटदाबी हे त्यावर उत्तर असते का? असावे का?

‘या चित्रपटातील काही भागाचा भारतविरोधी शक्तींकडून अपप्रचारासाठी वापर केला जाऊ शकतो,’ अशी शंका हे बंदीचे म्हणे कारण. पण ‘सतलज’ आपल्याकडे ओटीटी मंचावरून काढला तरी तो इतर देशांत ‘झी फाइव्ह’वर दिसतोच आहे, त्याचे काय? शिवाय, या कथित ‘शक्तीं’नी जे काही दोन दिवस ‘सतलज’ भारतात दिसला, त्या वेळीच डाउनलोड करून ठेवला असेल, तर तो पसरवणे इतके अवघड आहे का?

मुळात सर्व प्रकारच्या माहितीचे धबधबे अनेकानेक डिजिटल मंचांवरून रोज कोसळत असताना लोकांनी काय पाहावे, यावर खरेच नियंत्रण येऊ शकते का? एखादी घटना एखाद्या लेखक-दिग्दर्शकाला त्याच्या आकलनानुसार काढलेल्या अर्थान्वयानुसार दाखवावीशी वाटली, तर त्यावर थेट बंदी का? ‘केरळ स्टोरी’, ‘बंगाल फाइल्स’, ‘काश्मीर फाइल्स’ दाखवले जाऊ शकतात, तर ‘सतलज’ का नाही? सामान्यपणे पडणाऱ्या या सर्व प्रश्नांची नेमकी उत्तरे मिळत नाहीत, ही खरी रड आहे. घटिताकडे कुणी, कसे बघावे, याचीही मोकळीक न देणाऱ्या समाजात सत्याच्या जवळ जाण्यासाठी वाद-संवादापेक्षा सत्याच्या अपलापाची ओरड होते. दुर्दैवाने हेच ‘सतलज’चे सत्य आहे.

मध्य युरोपचे धडे

भांगेत पेरूनी प्राग...

अन्यथा

गिरीश कुबेर
girish.kuber
@expressindia.com
@girishkuber

प्राग हे मुळात चालणाऱ्यांचं शहर. ते त्यांनी असं ठेवलंय की ते आपोआप चालवतं. हे काय समोर... तिथं जाऊन बघू या... असं म्हणत म्हणत आपण सहज पाच-दहा किलोमीटर तुडवलेले असतात.

आकार आणि सौंदर्य यांचं गुणोत्तर बऱ्याचदा जरा व्यस्तच असतं. म्हणूनच बहुधा ‘स्मॉल इज ब्यूटिफुल’ असा वाक्प्रचार वापरात आला असावा. अर्थात हा काही विज्ञानाचा नियम नाही. त्यामुळे या विधानाचा व्यत्यास खरा असू शकतो आणि वैज्ञानिक नसलेल्या नियमाला पर्यायही तसे असू शकतात.

शहराचा विचार केला तर प्राग या नियमाला ठणठणीत अपवाद. हे शहर दणदणीत मोठं आहे. आणि तरीही कमालीचं सुंदर आहे. आकार आणि सौंदर्य यांचं गुणोत्तर राखणं जगातल्या अनेक शहरांना जमलेलं नाही, हे स्वानुभवावरनं ठामपणे सांगू शकतो. प्राग अतिशय अतिशय सुंदर. कोणत्याच मुद्द्यावर मुंबईशी या युरोपीय शहराची बरोबरी होऊच शकत नाही. किंवा करायची झाली तर मुंबईतला हुतात्मा चौक परिसर समजा तिकडे दहिसरपर्यंत आणि इकडे मुलुंडपर्यंत पसरवला तर शहर कसं दिसेल... तसं प्राग! कुठंही आकार वाढल्यावर येणारा बेढबपणा गुंजभरही नाही. मध्य भागात जुने दगडी रस्ते. अत्यंत अरुंद. पुणेकरांना तर तुळशीच्या बागेची आठवण येईल. पण ती तितकीच. कारण प्रागमध्ये त्यातनं ट्राम जाते ती खडखड करत. मध्य प्रागमध्ये एक बोळ तर इतका अरुंद आहे की त्यात शिरताना ट्राम वरती घासणार आणि वळणावर दोन-चार गाड्यांना धडकणार असंच आपल्याला वाटतं. तसाच आपला अनुभव. पण तिथं तसं काहीही होत नाही. दोन्ही बाजूला गच्च गर्दीची दुकानं. अतिशयोक्तीच करायची तर रस्त्यावरच्या या बाजूच्या दुकानात पैसे द्यायची वेळ आली तर त्या बाजूच्या दुकानात उभं राहूनही ते देता येतील इतकी जवळीक रस्त्याच्या या दोन बाजूंत. आणि मधून ट्राम. टंग टंग घंटा वाजवत येते-जाते. ज्येष्ठ नागरिकांच्या मेळाव्यातनं एखाद्या तरुणीनं अलगद वाट काढावी तशी ती ट्राम जुन्या प्रागमध्ये सुखेनैव हिंडत असते. ते दृश्य बघण्यात तास-दोन तास सहज जातील इतकं ते सुंदर.

खरं म्हणजे प्रागमध्ये काय सुंदर नाही, हाच प्रश्न. युरोपातली शहरं सगळीच तशी सुंदर. पण त्यातही नवं शहर, जुनं शहर यांचा पोत वेगळा असतो. प्रागमध्ये सगळं कसं एकसारखं. जुनंही नवं आणि नवंही जुन्यासारखं. संपूर्ण शहरभर, महत्त्वाच्या रस्त्यांवरच्या सगळ्या इमारती एकसारख्या, एकाच उंचीच्या. शाळेच्या मैदानावर कवायतीच्या वेळेला सगळे कसे एकाला एक खेटून उभे राहतात तशा या इमारती. आणि त्यांचे रंग? जराही डोळ्यात घुसत नाहीत. खुपत नाहीत. सगळ्या शहरभरच्या इमारती पेस्टल कलरने रंगलेल्या. आइस्क्रीमवाल्याकडे काचेच्या कपाटात मंद रंगातली आइस्क्रीम्स कशी लावून ठेवलेली असतात, तशा त्या दिसतात. एक डाग नाही... शोध शोध शोधलं. दिसला नाही कुठं. स्थानिक नगरपालिकाच सगळ्या इमारतींना कळवत असावी बहुधा कोणी कोणता रंग लावायचा ते. आणि तसं सांगितल्यावर त्या इमारतीतले रहिवासीही ऐकत असणार, हे ओघानं आलंच.

या शहरात काय सुंदर नाही, असा प्रश्न पडतो. खरं तर तो हे शहर इतकं सुंदर कसं असा असतो. वास्तविक ऑस्ट्रियातलं व्हिएन्ना यापेक्षाही सुंदर असेल. पण त्याचं सौंदर्य वेगळं. व्हिएन्नाच्या सौंदर्याचा एक दरारा आहे. त्या शहरात आपल्यामुळे काही तडा तर नाही जाणार ना या सौंदर्याला अशी सतत चिंता असते. त्यात परत मोझार्ट, शुबर्ट, बिथोव्हेन वगैरे महारथी त्या गावचे. त्यांचंही दडपण. प्रागमध्ये असं काही नाही. सगळे तुमच्या-आमच्यासारखे. आणि तरीही हे शहर सुंदर राहतं याचं जास्त अप्रूप. आणि मोठेपणही.

गावातनं मधनं एक नदी वाहते. घाटदार आणि मुसमुसलेली. तिच्यावर अर्धा डझन तरी पूल असतील. प्रत्येक पुलाची गंमत वेगळी. तिथनं दिसणारी नदीची कमनीयता वेगळी. त्या पुलाच्या दोनही बाजूंना चांगले, निरोगी फुटपाथ. सोबतीला झाडं. म्हणजे या पुलापासनं त्या पुलापर्यंत चालत जायचं म्हटलं तरी जाता येतं. खरं तर तसंच जायला हवं. कारण प्राग हे मुळात चालणाऱ्यांचं शहर. ते त्यांनी असं ठेवलंय की ते आपोआप चालवतं. हे काय समोर... तिथं जाऊन बघू या... असं म्हणत म्हणत आपण सहज पाच-दहा किलोमीटर तुडवलेले असतात. पायाकडून तसा संदेश येतो... आणि मग समोरचा कॅफे पुढचं काम करतो.

या सगळ्या पुलात एका पुलाचा मान जरा जास्तच. चार्ल्स ब्रिज. अर्थात आहेही तो तसाच. आम्ही दुपारी या पुलावर गेलो आणि त्यावर पाऊल टाकण्याआधीच तिथल्या सुरावटीनं पावलं थांबली. पुलाच्या एका टोकाला एक जण सॅक्सोफोन वाजवत होता. डोळे बंद. छान तंद्री लागलेली. समोर कोण किती पैसे टाकतायत आणि मुळात टाकतायत की नाही याचा कसलाही विचार नाही. हे अवघड वाद्य. ढगाळ वातावरण, पावसाची हूल देणारा हलका गार वारा, सगळ्या माहोलावर समान-सॉफ्ट प्रकाश आणि त्याची ही सुरावट. आतमध्ये काही तरी कालवाकालव करणारी...

या पुलाचं नाव चार्ल्स ब्रिज कारण तो सम्राट चार्ल्सनं बांधला. त्याचीही गंमत आहे. या सम्राटाला संख्यांशी खेळण्याचा छंद होता. कोणी भेटलं की सहा अधिक दोन, एक अधिक सात... वगैरे असं काय काय तो करायचा. तर त्यानं हा पूल बांधायचा निर्णय घेतला तेव्हा मुहूर्त काढला पहाटे ५.३१ असा. म्हणजे बरोब्बर पाच वाजून ३१ व्या मिनिटाला कुदळीचा घाव घालायचा म्हणजे घालायचा असा त्याचा आदेश. तो स्वतः त्यासाठी तिथं हजर राहिला. आणि वेळ ही का निवडली त्यानं? कारण त्या पुलाच्या बांधकामाची सुरुवात ज्या दिवशी होणार होती ती तारीख होती ९ जुलै १३५७. त्यामुळे त्या पुलाच्या शिलालेखावर त्याची नोंद झाली १३५७९७५३१ (१३५७ मध्ये ९ जुलै रोजी पहाटे ५:३१). हे फारच भारी. पण त्याहूनही भारी म्हणजे या पुलाचं बांधकाम. जवळपास ७०० वर्षं जुना आहे हा पूल. पण अजूनही आहे होता तस्सा. अगदी पिळदार. तो बांधणाऱ्या सम्राटाला हे असं आकड्यांशी खेळणं आवडत असेलही; पण त्यानं केलेल्या कामाचा दर्जा वादातीत आहे. आपल्यातल्या या छांदिक भावनेला त्यानं कधी बुद्धीवर मात करू दिली नाही, हे किती कौतुकास्पद. अर्थात मुळातच तो बुद्धिमान होता ही बाब आहेच. असो.

प्रागची आणखी एक गंमत. युरोपमधल्या इतक्या शहरात हिंडलोय, पण हे कुठं दिसलं नाही. अगदी औषधाची दुकानं वाटावीत अशी ही दुकानं. छान सजवलेली. काचेचे दरवाजे. आणि त्या दरवाजांवर किंवा कडेला झाडाचं एक पंजासारखं भलंथोरलं पान. वरवर पाहिलं तर मेपल वृक्षाचं वाटेल काहींना. पण ते त्या झाडाचं नाही. ते कसलं आहे याचा खुलासा शेजारचे शब्द करतात. ते असतात ‘कॅनबीज शॉप’. म्हणजे शुद्ध भांग. मला एकदम वाराणसी वगैरेची आठवण झाली. तिथं असतात ‘सरकारमान्य भांग की दुकान’. प्रागमध्ये गेलो एका दुकानात. सोनाराकडे असतो तसा छोटा तराजू. दोन-पाच ग्राम वगैरे अशी ती विकतात. परत भांगेचे विविध प्रकार आहेत. चटण्या. लोणची. पेयं वगैरे. खरेदी करणाऱ्यांचा कसलाही चोरटेपणा नाही. एखादं सिगारेटचं पाकीट घ्यावं तसं लोक कॅनबीज घेत होते. असो. म्हणजे असोच.

गदिमांच्या ‘जोगिया’त ओळ आहे... ‘भांगेत पेरूनी तुळस परतला शाम...’. तिच्यावरच समाधान मानलं आणि दुकानातनं बाहेर आलो. **(क्रमशः)**

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण

‘वावदूक आणि वानप्रस्थ’ हा अग्रलेख (१० जुलै) वाचला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना सध्या वानप्रस्थाकडे जाण्याची गरज आहे. विशेष हे, की त्यांना वानप्रस्थाकडे नेण्यासाठी तेथील जनता आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरेपूर वापर करत आहे. वाढत्या वयाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची स्मरणशक्ती, निर्णयक्षमता आणि मानसिक तंदुरुस्ती या विषयांवर माध्यमे, तज्ज्ञ तसेच नागरिक खुलेपणाने चर्चा करू शकतात, ही लोकशाही व्यवस्थेची महत्त्वाची बाजू. यातून लोकशाहीची खरी ताकद दिसून येते.

■ **मयूरी मूलमुले,** नाशिक

हा उथळपणा आश्चर्यकारक

‘‘**इंट्युशन कोर्स’ची** आधुनिक बुवाबाजी!’ हा लेख (१० जुलै) वाचला. मुलांवर असे प्रयोग करण्यापूर्वी पालकांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून चिकित्सा करावी, असे वाटते. अभिनेत्री हेमामलिनी करत असलेल्या जाहिरातीचा उल्लेख लेखात केला हे उत्तम झाले. या बाई खासदार आहेत, मात्र जाहिरात करतात ‘वॉटर प्युरिफायर’ची. पण नागरिकांना पिण्यायोग्य पाणी सहज उपलब्ध व्हावे, यासाठी त्यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे नाही का? ही माणसे इतकी उथळ कशी?

■ **धनंजय मदन,** पनवेल

वैज्ञानिक पडताळीस सामोरे जा

‘‘**इंट्युशन कोर्स’ची** आधुनिक बुवाबाजी!’ हा लेख (१० जुलै) वाचला. स्पर्धेच्या दडपणाखाली अनेक पालक मुलांच्या नैसर्गिक विकासापेक्षा त्यांना ‘असामान्य’ बनविण्यामागे लागतात. याच असुरक्षिततेचे रूपांतर काही संस्था आर्थिक संधीत करतात. याहून गंभीर बाब म्हणजे अशा दाव्यांना प्रसिद्ध व्यक्तींचे समर्थन लाभणे. समाजातील प्रभावशाली व्यक्तींनी कशाचाही प्रचार करण्यापूर्वी त्यामागील वैज्ञानिक पुराव्यांची जबाबदारीने छाननी करणे अपेक्षित असते. एखादा दावा खरोखरच मानवी मेंदूविषयीच्या आपल्या विद्यमान ज्ञानाला आव्हान देत असेल, तर तो संशोधनासाठी सुवर्णसंधी ठरला पाहिजे. अशा दाव्यांनी नियंत्रित, वस्तुनिष्ठ आणि स्वतंत्र वैज्ञानिक पडताळणीला सामोरे जाणे हीच त्यांची खरी परीक्षा आहे.

■ **रोहिणी गुट्टे,** धुळे

विज्ञाननिष्ठा हाच उपाय

अनेकांना काहीही प्रयास न करता आपले भले व्हावे असे वाटत असते. त्यासाठी ते कोणाची ना कोणाची कृपा, मंत्रपठण, अंकशास्त्र, फलज्योतिष अशा अ-वैज्ञानिक मार्गावर धावत असतात. अपयशासाठी आपला आळस, अपात्रता किंवा स्वभाव यांचा विचार न करता ग्रहदशा, प्रारब्ध, पूर्वजन्मीचे पाप इत्यादींना जबाबदार धरतात. त्यामुळे तात्पुरता मानसिक दिलासा मिळतो, पण समस्येचे योग्य उत्तर मिळत नाही. नवरा-बायकोची भांडणे होत असतील तर समुपदेशकाऐवजी तथाकथित ‘वास्तुशास्त्रज्ञा’चा सल्ला घेतात. मुलांचे भविष्य उत्तम घडावे यासाठी दिसेल त्या कोर्सच्या चरकातून त्यांना पिळून काढतात. बुवा-बाबा आणि ज्योतिषांची त्यामुळे चलती असते. मुलांना लहानपणापासूनच विज्ञाननिष्ठ विचारांची शिकवण देणे हाच यावर उपाय आहे.

■ **डॉ. शरद अभ्यंकर,** वाई

महिलेचा प्रश्न, नेहरूंचे उत्तर...

‘सत्ताधाऱ्यांना विरोधक अजिबातच नकोत?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१० जुलै) वाचला. विरोधकांची शक्य त्या सर्वप्रकारे मुस्कटदाबी करायची, मात्र मुखातून लोकशाहीचे गोडवे गायचे (संधी मिळेल तेव्हा ७५ च्या आणीबाणीच्या नावाने गळे काढायचे.) हे या सत्ताधाऱ्यांचे धूर्त धोरण आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘अन्वयार्थ’मधील पंडित नेहरूंचा किस्सा त्यांच्याविषयी आदर वाढवणारा आहे. त्यांचे लोकशाहीवरील प्रगाढ प्रेम व आस्था आणि त्याचाच भाग म्हणून टीकाकार, विरोधकांचा सन्मान याचे अनेक किस्से वाचनात आले. त्यातील हा एक..

संसदेच्या आवारात एका सामान्य महिलेने नेहरूंना विचारले, ‘तुम्ही पंतप्रधान झालात, पण आमच्यासारख्या सामान्यांना या लोकशाहीने काय दिले?’ नेहरू किंचितही न रागावता काहीसे स्मितहास्य करीत म्हणाले, ‘या देशाच्या पंतप्रधानाला जाब विचारण्याचे स्वातंत्र्य दिले’. विदेशातील महत्त्वाचे पाहुणे भारताच्या दौऱ्यावर येत, तेव्हा नेहरू त्यांची सर्वांत प्रथम विरोधी पक्षनेत्याशी ओळख करून देत. आजच्या काळात हे सर्व स्वप्नवत वाटते.

■ **अनिल मुसळे,** ठाणे

चीनभोवती भारताचे ‘ब्रह्मोस जाळे’?

विशेष विश्लेषण

डॉ. प्रसाद श. कुलकर्णी
prasad.kulkarni@expressindia.com

ऑपरेशन सिंदूरमध्ये अचूक कामगिरी करून पाकिस्तानला गारद करणाऱ्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी वाढत आहे. फिलिपिन्स, व्हिएतनामपाठोपाठ भारताने इंडोनेशियाबरोबर ब्रह्मोससह हवेतून हवेत मारा करणाऱ्या अस्त्र क्षेपणास्त्रांसाठी करार केला आहे. या क्षेत्रातील भूराजकीय गणिते त्यामुळे बदलणार आहेत.

इंडोनेशियाबरोबर १४ करार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडोनेशियाच्या दौऱ्यात विविध क्षेत्रांत महत्त्वाचे ठरतील असे १४ करार केले. त्यातील सर्वाधिक चर्चा संरक्षण क्षेत्रामधील ब्रह्मोस स्वनातीत (सुपरसॉनिक) क्रूझ क्षेपणास्त्रांची आणि हवेतून हवेत मारा करणाऱ्या अस्त्र क्षेपणास्त्रांच्या निर्यातीबाबत होत आहे. याखेरीज, दुर्मीळ खनिजे आणि सागरी सुरक्षेबाबतही भारताने इंडोनेशियाबरोबर करार केले. ब्रह्मोस, अस्त्र कराराचे तपशील भारताने अधिकृतरीत्या जाहीर केलेले नाहीत. मात्र, काही वृत्तांतानुसार, इंडोनेशियाबरोबर ६३ कोटी डॉलरचे करार भारताने केले आहेत.

ब्रह्मोस, अस्त्र क्षेपणास्त्रांचे महत्त्व

भारताने रशियाच्या सहकार्याने ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र विकसित केले आहे. ही क्रूझ क्षेपणास्त्रे सुखोई-३० एमकेआय विमानातून, जमीन आणि युद्धनौकेतूनही डागता येतात. इंडोनेशियाबरोबर सागरी सुरक्षेसाठी ब्रह्मोस प्रामुख्याने वापरले जाईल. अस्त्र क्षेपणास्त्र पूर्ण देशी बनावटीचे असून, त्याच्या निर्यातीमुळे भारतातील संरक्षण क्षेत्राचा आत्मविश्वास कमालीचा वाढणार असून, देशी बनावटीच्या इतर प्रणालींनाही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मागणी वाढू शकते. अस्त्र या हवेतून हवेत मारा करणाऱ्याअत्याधुनिक क्षेपणास्त्रामुळे दूर अंतरावरील लक्ष्य अचूकतेने टिपता येते.

शस्त्र खरेदी-विक्रीचे महत्त्व

संरक्षण क्षेत्रातील शस्त्र खरेदी-विक्रीचे करार सामान्य आणि दैनंदिन व्यापारी वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीसारखे नसतात. या खरेदी-विक्रीला दोन्ही देशांतील संबंधांचा इतिहास, मैत्रीचे बंध, ज्या देशाला एखादा देश महत्त्वाचे शस्त्र निर्यात करीत असतो, त्यामुळे संबंधित क्षेत्रातील त्या देशाचे वाढणारे सामरिक वर्चस्व आणि संबंधित क्षेत्रातील हितशत्रूंना दिलेला अप्रत्यक्ष संदेश आदी बाबी लक्षात घ्याव्या लागतात. भारत दीर्घ काळापासून रशियाकडून शस्त्रखरेदी करीत आला आहे. त्यामुळे एखाद्या देशातून शस्त्रखरेदी केल्यानंतर संरक्षणासाठी आणि एकूण सामरिक हितसंबंधांसाठी तो देश आपल्यासाठी किती महत्त्वाचा राहतो, याची पूर्ण कल्पना दीर्घ काळापासून आपल्याला आहे. भारत आता रशियासह फ्रान्स, इस्रायल, अमेरिका अशा विविध देशांकडून शस्त्रखरेदी करतो. भारत आजही शस्त्रांची मोठ्या प्रमाणावर आयात करीत असला, तरी संरक्षण क्षेत्रातील आपली निर्यात वाढत आहे. त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली छाप अधिक ठळकपणे उमटण्यात होत आहे.

भूराजकीय गणिते

भारताने इंडोनेशियाखेरीज फिलिपिन्स आणि व्हिएतनाम यांच्याबरोबर या क्षेपणास्त्रांसंबंधी करार केले आहेत. इंडोनेशियाबरोबरील करार डिसेंबर २०२५ मध्येच झाल्याची चर्चा आहे. आगामी तीन वर्षांत ही क्षेपणास्त्रे इंडोनेशियाला मिळतील. फिलिपिन्सबरोबर २०२२ मध्ये ३७.५ कोटी डॉलरचा करार झाला आहे. सायप्रस, ग्रीस, चिली, इजिप्त, अल्जीरिया, मलेशिया, थायलंड, व्हेनेझुएला आदी देशांबरोबरही या क्षेपणास्त्रांच्या निर्यातीचा करार होऊ शकतो. या विविध देशांचे भौगोलिक स्थान, या देशांच्या आसपासचे देश लक्षात घेतले, तर या क्षेपणास्त्रांच्या विक्रीमागील भूराजकीय महत्त्व लक्षात येते. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात ज्या देशांबरोबर भारताने करार केले आहेत, त्यांतून चीनला अप्रत्यक्ष इशारा आहे. सायप्रसबरोबर करार झाला, तर तो तुर्कीयेला इशारा आहे. चीन दीर्घ काळापासून पाकिस्तानला अत्याधुनिक शस्त्रे पुरवत आहे. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये चीनची ही मदत विशेषत्वाने दिसून आली. भारतानेही आता चीनचा वावर असलेल्या क्षेत्रात आणि चीनशी फारसे मैत्री संबंध नसलेल्या देशांशी शस्त्रविक्रीचे व्यवहार करून सामरिक प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

शस्त्रांच्या बाजारपेठेतील चंचुप्रवेश

शस्त्रांच्या निर्यातीत अमेरिका, रशियाचे स्थान वरचे आहे. या बाजारपेठेचा अंदाज घेतला, तर जागतिक स्तरावरील संघर्षांचा अंदाज येऊ शकतो. अमेरिकन शस्त्रास्त्र कंपन्यांच्या कंपूशाहीवर अनेक आरोप होतात. विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या संघर्षामागे ही कथित कंपूशाही किंवा लॉबी असल्याचे आरोप होतात. शस्त्रास्त्रविक्रीला अशी नकारात्मक छटाही आहे. मात्र, जबाबदारीचे पूर्ण भान ठेवून, संरक्षणासाठी अत्याधुनिक शस्त्रांची निर्मिती आणि त्यांची विक्री, सामरिक प्रभाव वाढविण्यासाठीचे प्रयत्न यांना दुर्लक्षून चालणार नाही. भारताच्या बाबतीत विचार केला, तर संरक्षण क्षेत्रातील वाढती निर्यात हा या बाजारपेठेतील चंचुप्रवेश आहे. भविष्यामध्ये भारताचा सामरिक प्रभाव आणखी वाढवायचा असेल, तर शस्त्रविक्रीबरोबरच स्थानिक पातळीवर लोकांचे जीवनमान उंचावून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिकाधिक छाप पाडणे महत्त्वाचे आहे. ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांची निर्यात त्या दिशेने जाण्यासाठी एक पाऊल ठरावे.

विधि क्षेत्रातील व्यंगांवर सावध बोट

प्रतीक राजुरकर
prateekrajurkar@gmail.com

न्यायालयांच्या रूक्ष दैनंदिन कामकाजातही काही वेळा हास्याची लकेर उमटते. कधी वकिलांच्या तर कधी न्यायाधीशांच्या भाषिक कौशल्यांतून मार्मिक विनोदांची निर्मिती होते. काही वेळा त्यांचे अजब स्वभाव चर्चेचा विषय ठरतात. देशविदेशांतील अशा घटना टिपणारे हे पुस्तक भारतातील न्यायालयांना स्पर्श करणे मात्र टाळते...

घटनात्मक पदावर असल्यामुळे असेल कदाचित, मात्र भारताचे महान्याय अभिकर्ता (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता यांनी 'द लॉफूल अँड द ऑफुल, क्वर्की टेल्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ लॉ' या आपल्या पुस्तकात जगभरातील विधि व न्याय क्षेत्रातील व्यंग, विनोद, घटना, इतिहास इत्यादींवर भाष्य करताना भारतीय न्याय व्यवस्थेला मात्र त्यातून वगळले आहे. त्यामुळे साहजिकच भारतीय विधि क्षेत्रातील मान्यवर नानी पालखीवाला, फली नरिमन यांसारख्यांनी लिहिलेली पुस्तके आणि तुषार मेहता यांच्या या पुस्तकाची तुलना होऊ शकत नाही. पुस्तकाच्या प्रास्ताविकात त्यांनी त्याबाबतची कारणे स्पष्ट केली आहेत. मेहता आवर्जून लिहितात की, पुस्तकातील मते ही त्यांची वैयक्तिक मते असून ते संलग्न असलेल्या कोणत्याही संस्थेचा अथवा भारत सरकारचा या मतांशी दुरान्वयेही संबंधित नाहीत. विधि व न्याय क्षेत्रातील आजवर प्रकाशित पुस्तकांचे अवलोकन करायचे झाल्यास भारतीय लेखकाने भारतीय न्यायव्यवस्थेला वगळून इतर देशांतील विधि व न्याय क्षेत्रातील अनेक घटनांचा उल्लेख करत लिहिलेले कदाचित हे एकमेव व पहिलेच पुस्तक असावे.

राम जेठामलानी यांचे 'स्मॉल मेन बिग इगोज', अभिनव चंद्रचूड यांचे 'सुप्रीम व्हिस्पर्स', फली नरिमन यांचे 'बिफोर मेमरी फेड्स', एम. सी. छागला यांचे 'रोझेस इन डिसेंबर' अथवा नानी पालखीवाला यांची अनेक पुस्तके ही विधि व न्याय क्षेत्रात अत्यंत लोकप्रिय आहेत. तुलनाच करायची झाली तर व्ही. जे. तारापोरवाला यांच्या 'टेल्स फ्रॉम द बार अँड बेंच' या पुस्तकाशी मेहतांच्या पुस्तकाची विषयाच्या निकषावर आधारित तुलना होऊ शकेल; परंतु तरीही तारापोरवाला यांचेच पुस्तक अत्यंत उजवे ठरेल. लेखकाने कोणता विषय निवडावा आणि आपले लिखाण किती मर्यादेत ठेवावे हा लेखकाचा निर्विवाद अधिकार आहे. भारतीय वाचकांना आजवर विधि व न्याय क्षेत्रासंबंधित जे साहित्य उपलब्ध झाले, त्या तुलनेत मेहतांचे साहित्य चोखंदळ वाचकांच्या कितपत पसंतीस उतरेल याबाबत साशंकता आहे. जागतिक स्तरावरील लहान पण महत्त्वाच्या घटनांचे त्यांनी आपल्या पुस्तकात केलेले उल्लेख मेहतांनी व्यग्र वेळापत्रकातही जोपासलेला व्यासंग अधोरेखित करणारे आहेत. जगातील विधि व न्याय क्षेत्रातील लहानसहान घटना, विनोद, अगदी विविध देशांतील न्यायाधीश असले तरी त्यातही आढळणाऱ्या व्यक्ती तितक्या प्रवृत्ती याची प्रचीती निश्चितच मेहतांचे पुस्तक देते.

'बेंच विदाउट बॉर्डर्स' नावाच्या पहिल्याच प्रकरणात मेहतांनी न्यायाधीशपदावरील व्यक्तींचा स्वभाव, गुणधर्म यांचे चपखल वर्णन केले आहे. न्यायाधीशांचे न्यायालयातील वर्तन आणि वाघ-सिंहाचे त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासातील वर्णन यांची तुलना मेहता यांनी केली आहे. न्यायाधीशांनी न्यायालयाच्या बाहेरसुद्धा त्यांची कर्तव्ये बजावल्याच्या अनेक घटनांचा उल्लेख विधि व न्याय क्षेत्राबाहेरील व्यक्तींसाठी नवीन माहिती उपलब्ध करून देणारा आहे. न्यायालय हे न्याय देण्याचे ठिकाण, ते परिस्थितीनुरूप कसे बदलत गेले आणि कोविडकाळात त्याला लाभलेली विश्वमान्यता याचा मागोवा यात घेतला आहे. पहिल्या प्रकरणात जगभरातील अनेक घटनांचे संदर्भ दिले आहेत. अगदी व. पु. काळे यांच्या बदली या कथेतील समारोपाच्या वाक्याची प्रचीती देणारे हे पहिले प्रकरण आहे. न्यायाधीशांचा 'नैसर्गिक अधिवास' बदलला तरी वकिलांचे नशीब बदलत नाही.

न्यायाधीशांच्या विक्षिप्तपणाविषयी तुषार मेहतांनी 'वियर्ड टेल्स ऑफ वियर्डर जजेस' हे शीर्षक असलेले दुसरे प्रकरण लिहिले आहे. न्यायाधीश पदावरील व्यक्तीही शेवटी माणूसच असते. त्यामुळे मानवी आयुष्यातील गुणदोष न्यायाधीशांच्या अंगी आल्यास नवल ते काय. अनेक देशांतील न्यायाधीशांच्या कृष्णकृत्यांचा मेहतांनी आपल्या पुस्तकात उल्लेख केला आहे. त्यांचे गुन्हे, गैरवर्तन, अरेरावीच्या घटना याविषयी वाचताना न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना संबंधित व्यक्तीचे सर्वांगीण मूल्यांकन होणे किती गरजेचे आहे, याची प्रचीती येते. मेहतांनी अशा अनेक घटनांची वर्णने करताना त्या व्यक्ती न्यायाधीशपदासाठी कशा अयोग्य होत्या हे अधोरेखित केले आहे. इतिहासात अशा न्यायाधीशांना आजच्या तुलनेत कठोर शासन होत होते हे सांगताना त्यांनी त्याबाबत अल्फ्रेड राजाने ४४ न्यायाधीशांना फासावर लटकवण्याची शिक्षा दिल्याचा ऐतिहासिक संदर्भही उदाहरणादाखल नमूद केला आहे. प्रकरणाची सांगता करताना ते लिहितात, शेवटी कायदा न्यायाधीशांना जगवतो पण न्यायाधीश आपल्या विक्षिप्तपणातून अपवादानेच वाचू शकतात.

व्ही. जे. तारापोरवाला यांच्या 'टेल्स फ्रॉम बार अॅण्ड बेंच' या न्यायालयाच्या गंभीर वातावरणात कठोर न्यायाधीशांवर अथवा न्यायाधीशांनी केलेले विनोद, हजरजबाबीपणा, मार्मिक टिप्पणी याचा समावेश आहे. पुस्तकात एक प्रकरण- 'द ब्रिटिश आर्ट ऑफ कोर्टरूम विट' हे पूर्णतः ब्रिटिश न्यायाधीश, वकिलांना समर्पित आहे. या पुस्तकात भारतीय विधि व न्याय क्षेत्रातील अनेक प्रसंग लिहिलेले आहेत. वकील व न्यायाधीश यांचा हजरजबाबीपणा, त्यातील शब्दकळा मेहतांच्या पुस्तकातील प्रकरणापेक्षा अधिक रंजक असल्याचे आढळते. इंग्रजांच्या 'ब्रिटिश इंग्लिश'मधील आणि भारतीय विद्वानांच्या अस्खलित इंग्रजीतील शब्दकळा वेगळी भासते. मेहतांनी उल्लेख केलेल्या घटना आणि प्रसंग विनोदी, मार्मिक नाहीत असे नाही परंतु गुणात्मक तुलना केल्यास व्ही. जे. तारापोरवाला यांच्या पुस्तकातील विनोद अधिक श्रेष्ठ आहेत. घटनांतील आपलेपणाच्या अभावामुळे या पुस्तकातील उदाहरणे तितकी प्रभावी वाटत नाहीत. गंभीर विनोद विरुद्ध निखळ व्यंग यात जितके अंतर आहे ते अनुक्रमे मेहतांच्या पुस्तकातील प्रकरण 'द ब्रिटिश आर्ट ऑफ कोर्टरूम विट' व व्ही. जे. तारापोरवाला यांच्या 'टेल्स फ्रॉम बार अॅण्ड बेंच' यात दिसून येईल. विधि क्षेत्राशी दूरान्वये संबंध नसलेल्या सामान्य वाचकांना तारापोरवाला यांच्या पुस्तकातील घटनांचा अधिक आनंद लुटता येईल. मेहतांच्या पुस्तकातील हे प्रकरण काही अपवाद वगळता विनोद व्यंग निकषाच्या फारच खालच्या पायरीवर विसावणारे आहे. अगदी निरस असे वर्णन केल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये. व्यंग, विनोदाचा आनंद चिरंतन टिकणे गरजेचे आहे. कुठल्याही क्षणी त्याचे तारुण्य टवटवीत असले पाहिजे.

'फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन ऑफ जजेस' हे प्रकरण अधिक वाचनीय आणि वाचकाला वैचारिक खाद्य देणारे आहे. न्यायालयीन निकालपत्र, आदेश, निवाडे सामान्य व्यक्तींना वाचताना अत्यंत निरस आणि क्लिष्ट भासतात. मेहतांनी या प्रकरणात अनेक देशांतील अतिशय रंजक, विनोदबुद्धीने लिहिलेले निकाल, लहानसे आदेश, न्यायालयीन विश्लेषण यांचे संदर्भ दिले आहेत जे वाचनीय आहेत. प्रकरणाच्या अखेरीस त्यांनी न्यायालयीन निकाल हे सामान्य वाचकांना अधिक रंजक वाटतील, अशा पद्धतीने लिहिले जावेत, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले आहे, ही अपेक्षा स्वागतार्ह आहे.

मेहतांनी आपल्या पुस्तकात अँटॉनिन स्कॅलिया यांच्यावर 'द कोर्ट ऑफ वन' नावाने प्रकरण लिहिले आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात ३० वर्षे न्यायाधीश असलेल्या न्या. स्कॅलिया यांची ख्याती 'असहमतीचे न्यायाधीश' अशी होती. न्या. स्कॅलिया यांच्या विविध निकालांचे मेहतांनी विश्लेषण केले आहे आणि संदर्भ दिले आहेत. स्कॅलिया यांची मते, त्यांचा आत्मविश्वास या आणि अशा अनेक बाजू मेहतांनी मांडल्या आहेत. ३० वर्षे न्यायाधीश असलेले स्कॅलिया यांनी या प्रदीर्घ कालावधीत अनेक निकाल दिले. मेहतांनी त्यांचे वर्णन 'ते केवळ न्यायाधीश नव्हते तर न्यायिक सद्सद्विवेकबुद्धीचेसंरक्षक होते,' असा उल्लेख केला आहे. जागतिक न्यायक्षेत्रातील एका न्यायाधीशाच्या संदर्भातील माहितीत भर घालणारे प्रकरण म्हणून याचे वर्णन करता येईल.

'द अॅनाटॉमी ऑफ ए रॉटन जज' या प्रकरणात मेहतांनी अमेरिकेतील न्यायाधीश जेम्स क्लार्क मॅकरेनॉल्डस यांच्या न्यायाधीश म्हणून कारकीर्दीचा आढावा घेतला आहे. न्या. मॅकरेनॉल्डस यांच्या अनेक निकालांचे संदर्भ देताना त्यांच्या निकालांत त्यांचे व्यतिमत्त्व कसे प्रतिबिंबित होते हे वाचकांच्या लक्षात आणून दिले. न्या. मॅकरेनॉल्डस यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या सहकारी न्यायाधीशांपैकी कुणीही त्यांना भेटण्यास गेले नाही, अगदी त्यांच्या मृत्युपश्चात त्यांचा एकही सहकारी त्यांच्या अंत्यदर्शनाला हजर नव्हता याचा उल्लेख यात आहे. प्रकरणाचे शीर्षकच त्या व्यक्तीबद्दल सारे काही सांगून जाते.

पुस्तकातील अखेरची दोन प्रकरणे ही निकालपत्रातील वैविध्य दर्शवणारी आहेत. 'लीगल रिझनिंग विथ पर्पल सीझनिंग' या प्रकरणात क्लिष्ट कायदेशीर भाषेत लिहिल्या जाणाऱ्या निकालपत्रात अलंकारिक भाषेचा करण्यात आलेला वापर याचा मागोवा घेण्यात आला आहे. 'पर्पल प्रोज' या लिखाण कौशल्याचा काही न्यायाधीशांनी निकालपत्रात केलेला वापर लेखकाने संदर्भासहित उपलब्ध करून दिला आहे. 'पर्पल प्रोज' म्हणजे काय तर, शशी थरूर यांच्यासारख्या भाषेवर पकड असलेल्या व्यक्तीने आपल्या नैसर्गिक भाषेत निकालपत्र लिहिले तर ते 'पर्पल प्रोज'च्या श्रेणीत गणले जाईल.

एकूण पुस्तक आणि अखेरचे प्रकरण विरोधाभासी आहे. 'ऑल इज वेल दॅट बिगिन्स वेल' या अखेरच्या प्रकरणात निकालपत्रांची सुरुवात ही एक कला असल्याचे नमूद केले आहे. काही कलात्मक निकालांचे संदर्भ आणि लेखक न्यायाधीशांचे निकाल यात नमूद केले आहेत. निकाल लिहिणे, त्यातही कलात्मक लिखाणातून सुरुवात करणे हे प्रत्येक न्यायाधीशाला शक्य होईलच असे नाही. शेवटी निकाल सर्वांपर्यंत उत्तम भाषेच्या माध्यमातूनच पोहोचवता येतो, याबाबत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही.

तुषार मेहतांचे पुस्तक आणि त्यातील प्रकरणे बघता हे पुस्तक एका मर्यादित वाचकवर्गासच पसंत पडेल. तुषार मेहतांनी पुस्तकात जगभरातील विधि व न्याय क्षेत्रातील बरीच माहिती दिलेली आहे. स्वतःवर मर्यादा घालून वाचकांना काहीतरी नवीन वाचनीय देण्याच्या मेहतांच्या प्रयत्नांचे निश्चित स्वागत केले पाहिजे. त्यांनी व्यग्र वेळापत्रकातून वेळ काढत साहित्यनिर्मिती केली असणार हे निश्चित. सॉलिसिटर जनरल म्हणून तुषार मेहता सर्वांना परिचित आहेतच, पुस्तक वाचताना त्यांच्यातील तटस्थ वकिलाची अनेकदा प्रचीती येते. असे असले तरीही मेहतांसारख्या ज्येष्ठ विधिज्ञाकडून लेखक म्हणून ज्या अपेक्षा होत्या, त्यांची पूर्तता होत नाही. मेहतांचे पुस्तक अधिक 'लॉफुल' आणि 'ऑफुल' होऊ शकले असते आज त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करताना लेखक म्हणून त्यांच्यावर काही बंधने निश्चितच येत असतील, हे समजण्याजोगे आहे. भविष्यात कधीतरी या जबाबदारीतून मुक्त झाल्यावर कदाचित ते तटस्थपणाने भारतीय विधि व न्याय क्षेत्रावर मोकळेपणाने लिखाण करतीलसुद्धा...

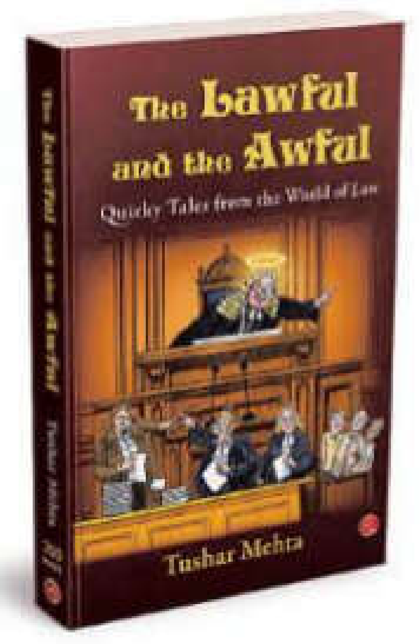

द लॉफुल अॅण्ड द ऑफुल, क्वर्की टेल्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ लॉ
लेखक - तुषार मेहता
प्रकाशक- रूपा प्रकाशन
पृष्ठे- ३४४, किंमत- ९९५ रु.

मनाच्या गुंफेत डोकावताना...

वैशाली चिटणीस
vaishali.chitnis@expressindia.com

आपल्या रोजच्या ठरावीक साच्यातून, थोडक्यात 'कम्फर्ट झोन'मधून बाहेर पडून कुठे कुठे केलेला प्रवास माणसाला जेवढा अनुभवांनी समृद्ध करतो, तितकाच अंतर्मनाचा प्रवास त्याला स्वतःविषयी, जगण्याविषयी सखोल विचार करण्यास भाग पाडतो. व्यवसायाने पत्रकार असलेल्या, पर्यटन, संस्कृती या विषयावर सातत्याने लेखन करणाऱ्या, कामानिमित्त देशोदेशी फिरलेल्या आणि सध्या बीजिंग इथे वास्तव्यास असलेल्या पल्लवी अय्यर यांनी 'ट्रॅव्हल्स इन द अदर प्लेस' या पुस्तकातील आठ निबंधांमधून त्यांच्या अंतर्मनाचा प्रवास मांडला आहे. एका स्त्रीचा आंतरिक प्रवास असेही त्याचे वर्णन करता येईल. पल्लवी अय्यर यांची याव्यतिरिक्त 'ओरिएंटिंग', 'स्मोक अॅण्ड मिरर्स', 'पंजाबी पार्मेझान', 'जाकार्ता टेल्स' इत्यादी त्यांच्या कामानिमित्त झालेल्या फिरस्तीसंदर्भातली आठ पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत. त्या 'सबस्टॅक' या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर 'द ग्लोबल जिगसॉ' या नावाचे जागतिक साप्ताहिक वार्तापत्र लिहितात. त्यात प्रवास तसेच वेगवेगळ्या संस्कृती यावर जास्त भर असतो.

भारतीय आईवडिलांच्या पोटी जन्मलेली, भारतात वाढलेली, जग फिरून बहुश्रुत झालेली लेखिका आपल्या आत डोकावण्याचा अनुभव मांडताना मात्र 'ट्रॅव्हल्स इन द अदर प्लेस' असे म्हणते हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. वाचकासाठीही तिच्या मनाची ही गुंफा त्याला वेगळ्या जगात घेऊन जाणारी आहे. कारण चीन, बेल्जियम, जपान, इंडोनेशिया आणि स्पेन या देशांमधली कामानिमित्तची लेखिकेची भटकंती, अतिशय समृद्ध अशी भाषाशैली, वेगळे शब्द सहजपणे वापरण्याची हातोटी, लेखनात उतरलेला स्वभावातील मिश्कीलपणा, व्यक्तिगत तसेच व्यापक अनुभवविश्वाचा मेळ घालण्याची अनोखी पद्धत आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे दुर्मीळ होत चाललेला निबंध हा लेखनप्रकार यामुळे हे पुस्तक वाचनीय झाले आहे. एखाद्या जंगलात जाताना समोरची पायवाट हळूहळू दिसत जावी तसे लेखिकेचे व्यक्तिमत्त्व या पुस्तकातून उलगडत गेले आहे.

पुस्तकांविषयीच्या पहिल्याच प्रकरणात लहानपणी केलेल्या वाचनाचे, त्यातील जादूई दुनियेचे वर्णन आहे. लहानपणापासून वाचन करणाऱ्या मुलांचे तेव्हाचे त्यांचे असे खास आवडते लेखक असतात. मुलांसाठी जवळपास ६०० पुस्तके लिहिणारी एनिड ब्लायटन ही तिची आवडती लेखिका. ब्लायटनमुळे आपली कल्पनाशक्ती कशी विस्तारली आणि वाचन कसे आपल्या प्रवासाचे साधन झाले याचे वर्णन या प्रकरणात आहे. आपली दोन छोटी मुले कधी एकदा वाचण्याच्या वयाची होतात आणि आपण त्यांची ब्लायटनशी ओळख करून देतो, असे लेखिकेला झालेले असते. पण तिच्या मुलांची तिच्या आवडत्या लेखकांशी गट्टी होत नाही. ती वाचतात, पण त्यांच्या काळातले आणि त्याहीपेक्षा ती स्क्रीनशरण होतात, याचे तिला फार वैषम्य वाटते, याचे वर्णन ती करते.

'इलनेस' या प्रकरणात स्तनांच्या कर्करोगाचे निदान झाल्यापासूनचा मानसिक आणि शारीरिक प्रवास मांडला आहे. कर्करोगाशी दोन हात करणे ही वास्तविक तनमनाला झुंजवणारी गोष्ट. पण ती झुंज देतानाही लेखिकेचे मनोधैर्य फक्त शाबूतच राहत नाही, तर ती काहीशा नवलाईनेच त्या प्रक्रियेकडे पाहते आहे, असे जाणवत राहते. त्यामुळेच कॅन्सरच्या उपचारांनंतर लगेचच प्लास्टिक सर्जरी करावी लागणे, त्या उपचारांनंतर केलेल्या नव्या केशरचनेमुळे आजारापणातून आपल्या विश्वात परत आल्यासारखे वाटणे या गोष्टी येतात. 'हेअर' या प्रकरणात तेव्हा जेमतेम नऊ वर्षांची असलेल्या लेखिकेला आपल्या शीख मित्राने केस कापल्याचे समजते आणि धक्का बसतो. १९८४ मधील इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर झालेल्या शीख दंगलीचा याला संदर्भ असतो. तरुणपणी स्वतःचे केस कुरळे करण्याचे फसलेले प्रयोग, कॅन्सरच्या उपचारांत केमोथेरपीमुळे केस गळून गेल्यामुळे विग घालावा लागणे, याबद्दल सांगताना लेखिकेने प्रवासाच्या कल्पनेला एक वेगळेच वळण दिले आहे.

'पेडागॉजी' प्रकरणात मुलांच्या अभ्यासाबाबत अति-आग्रही असण्याच्या अनुभवांवर लेखिकेने लिहिले आहे. वास्तविक भारतापेक्षा पूर्ण वेगळी शिक्षणपद्धती असलेल्या देशांतील शाळेत तिची मुले शिकतात आणि मुलांना शिकण्याची मोकळीक देणे हा तिथला स्थायिभाव आहे. अशा वेळी भारताची शैक्षणिक पार्श्वभूमी असलेली आई आणि वेगळ्या वातावरणात शिकणारी तिची मुले ही एक प्रकारची जुगलबंदी ठरते. 'पासपोर्टिझम' या प्रकरणात पासपोर्ट या एरवी साध्या वाटणाऱ्या घटकाकडे किती वेगळ्या दृष्टीने पाहता येते याचे दर्शन घडते. पासपोर्ट रँकिंगमध्ये भारतीय पासपोर्ट कमकुवत मानला जातो. त्यावर प्रवास करताना येणाऱ्या अडीअडचणी, व्हिसा अर्जाची गुंतागुंतीची प्रक्रिया आणि अनोळखी देशांत इमिग्रेशनमध्ये अडकण्याची सततची भीती यांवर लेखिकेने भाष्य केले आहे.

भाषा माणसांना कशी जोडते, बातमीदारी करताना आलेले माणसांचे अनुभव आणि त्यातून विकसित होत गेलेले स्वतःचे व्यक्तिमत्त्व, बातमीकडे बघण्याचा तिचा भारतीय वाटावा असा दृष्टिकोन आणि तिच्या पाश्चात्त्य सहकाऱ्याचा वेगळा दृष्टिकोन, चीनमधल्या कार्यक्षम सेवा, तिथल्या लोकांची विनोदबुद्धी, अतिशय सुंदर असे ब्रुसेल्स पण तिथे साधा प्लम्बरही सहज मिळू न शकणे, असे अनुभव येतात.

लेखिकेच्या मते आयुष्य हा काळाच्या प्रवासाचा कोलाज आहे. तिचे लिखाण वाचताना याची सतत अनुभूती येत राहते.

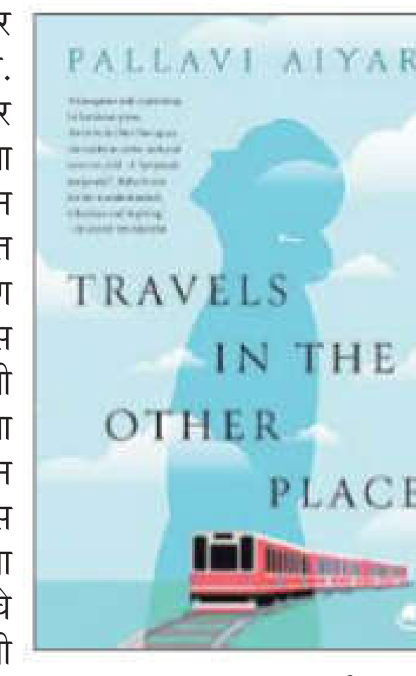

ट्रॅव्हल्स इन द अदर प्लेस
लेखक -पल्लवी अय्यर
प्रकाशक- ट्रॅन्क्युबार बुक्स
पृष्ठे- १९३, मूल्य- ५९९ रु.

बुक-नेट

फोलिओ सोसायटीचे 'मोबी डिक'

लंडनमधील फोलिओ सोसायटी या प्रकाशन संस्थेकडून तयार होणारे अभिजात आणि समकालीन ग्रंथ हे सध्या जगातील परमोच्च पुस्तकनिर्मितीचा नमुना म्हणून पाहिले जातात. देखण्या, पुठ्ठाबांधणीच्या खास चित्रे काढून घेतलेल्या आणि अभ्यासकांच्या नव्याच प्रस्तावनेसह साकारलेल्या या ग्रंथप्रती प्रचंड महागड्या असल्या तरी जगभरात ऑनलाइन खपतात. अमेरिकेच्या अडीचशेव्या स्वातंत्र्यवर्षाच्या निमित्ताने या संस्थेने नुकतेच जगभरातील आपल्या अनुयायी वाचकांना सर्वोत्तम अमेरिकी कादंबरी कोणती, याची विचारणा केली. सर्वाधिक उत्तरे आली ती हर्मन मेलविलच्या 'मोबी डिक'बाबत. त्यामुळे फोलिओ सोसायटीने मोबी डिकची ७५० प्रतींची आपली खास आवृत्ती सादर केली. या प्रतीची किंमत आहे ६१० पौंड (सुमारे ७८,०८० रुपये)! वॉशिंग्टन पोस्टच्या बुक सेक्शनमध्ये कैक दशके सदर चालवणारे समीक्षक मायकल डर्डा यांच्या प्रस्तावनेसह आणि भरपूर चित्रांसह ती सादर झालीय. पुस्तक महागडे असले तरी डर्डा यांची संपूर्ण प्रस्तावना आणि पुस्तकाच्या आतील काही चित्रे असा ऐवज पहिल्या दुव्यावर मोफत वाचता येऊ शकेल. फोलिओ सोसायटीच्या पुस्तकांचा खासगी संग्रह असलेल्या यूट्यूबरच्या व्हिडीओत (दुसरा दुवा) या पुस्तकांविषयी भरपूर दृश्यमाहिती मिळेल. या संस्थेच्या कामाबद्दल अद्याप अनभिज्ञ असल्यास एका लेखाचा (तिसरा) दुवा उपयुक्त ठरेल.

■ https://tinyurl.com/mpsnwthw ■ https://tinyurl.com/2wczdrez
■ https://tinyurl. com/4ujk25tf

एआय आणि कथा-कादंबऱ्या...

इंग्रजी भाषेत शैक्षणिक लिखाणापासून जाहिरातींपर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून भाषिक उत्पादने तयार केली जातायत. यात सध्या विविध प्रादेशिक भाषा अद्याप अद्ययावत व्हायच्या असल्या तरी त्यांत चॅट जीपीटीवर कविता-कथा लिहिण्याचे खेळ-उद्योग आपापल्या पातळीवर चालताहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही मानवाइतकी कल्पक बनू शकणार नाही यावर एकमत आहेच; पण सध्या तर ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता कशी चुकीच्या आणि हास्यास्पद/ गमतीशीर भाषेचा वापर करते, या निष्कर्षावर बरेच प्रादेशिक भाषिक समुदाय ठाम आहेत. पुढल्या काळात प्रादेशिक भाषाही एआय समरसतेने शिकेल. पण सध्या वृत्त-वाहिन्यांवर सर्रास ऐकू येणाऱ्या प्रादेशिक भाषेसारखी ती होईल का? भाषा अभ्यासक, कथा-कादंबरीकार यांनी 'एआय' बदलत असलेल्या आणि रूढ करीत असलेल्या भाषेबद्दल गार्डियनमध्ये आलेल्या लेखात चर्चा केली आहे.

■ https://tinyurl.com/yvux8v4n

कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाद आणि कथाचर्वण...

गेल्या महिन्यापूर्वी कॉमनवेल्थ पारितोषिकासाठी निवडण्यात आलेली जमीर नजीर यांची कथा ही 'एआय'चा वापर करून तयार करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आल्यानंतर नवा वाद उफाळून आलेला. गेल्या आठवड्यात ही कथा पूर्णपणे एआयरहीत आणि निर्दोष असल्याचा निर्वाळा दिला गेला. लेखकाने आपल्या कथेबाबत दिलेल्या स्पष्टीकरणावरून 'स्लेट'ने घडवलेली चर्चा, येथे वाचता येईल.

■ https://tinyurl.com/bdd7sere

बुकबातमी

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी आजचा काळ कठीण!

'मी अमेरिकेत राहतो. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार देणाऱ्या पहिल्या घटनादुरुस्तीचा अभिमान बाळगणारा हा देश, मात्र तेथील प्रशासनाकडून आज अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर हल्ले केले जात आहेत. अशा परिस्थितीची मी कधी कल्पनाही केली नव्हती,' असे मत भारतीय वंशाचे अमेरिकी लेखक सलमान रश्दी यांनी नुकतेच व्यक्त केले. 'लिबरेटम' या संस्थेकडून देण्यात येणारा प्रतिष्ठेचा 'सांस्कृतिक पुरस्कार' स्वीकारण्यापूर्वी 'रॉयटर्स'ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे मत मांडले. 'या देशात पत्रकार, विनोदवीर, लेखक, कलाकार आणि विचारवंतांवर हल्ले केले जात आहेत, यावरून सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबद्दल काय मत आहे, हे स्पष्टच दिसते. ग्रंथालयांतून अनेक पुस्तके वगळली जात आहेत आणि या निर्णयाला आव्हानही दिले जात आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये हे प्रयत्न यशस्वी ठरत आहेत. पण एकंदर जगाच्या अनेक भागांत अतिशय बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे,' अशा शब्दांत त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

आपल्या मूळ देशातील- भारतातील परिस्थितीविषयीही त्यांनी या वेळी भाष्य केले. 'मी मूळचा भारतीय आहे आणि तिथेही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर मोठ्या प्रमाणात हल्ले होत आहेत. या काळात आपण लढा देण्यासाठी कंबर कसून सज्ज राहणे महत्त्वाचे आहे. आपण जिंकलो आहोत असे वाटते, पण प्रत्यक्षात तो तात्कालिक विजय असतो. खरे तर आपण जिंकलेले नसतोच, असा हा काळ आहे,' अशा शब्दांत त्यांनी भारतातील स्थितीचे वर्णन केले. रश्दी यांनी वर्णिलेल्या परिस्थितीसाठी चपखल दाखला ठराव्यात अशा बातम्या अलीकडेच जम्मू आणि काश्मीरमधून येऊ लागल्या आहेत. तिथे वाचनालयांत काही विशिष्ट पुस्तके ठेवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे, देशात चित्रपटांवर बंदीच्या प्रकरणांची संख्याही वाढत आहेच. विनोदवीरांच्या अभिव्यक्तीवरही गंडांतर आल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे साहित्य क्षेत्रासाठी मोठे आव्हान ठरत असल्याची चर्चा सध्या सर्वत्र आहे. मात्र हे दावे रश्दींनी मुलाखतीत पूर्णपणे खोडून काढले. 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता सर्जनशील कामांसाठी अजिबात उपयुक्त नाही. साहित्य क्षेत्राला तिचा धोका शून्यापेक्षाही कमी आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवळ प्रचंड प्रमाणात माहिती गोळा करून त्यावर प्रक्रिया करून त्या माहितीला काही विशिष्ट रूप वा विविध रूपे देऊ शकते. मात्र साहित्यात नावीन्य आणणे कृत्रिम बुद्धिमत्तेला शक्य नाही. आणि कलेत नेमके नावीन्यच अपेक्षित असते. जे आजवर कोणीही मांडलेले नाही असे काही समाजापुढे मांडणे गरजेचे असते आणि ते एआयला अजिबात शक्य होणार नाही, त्यामुळे या विषयात मला स्वारस्य नाही,' अशा शब्दांत सलमान रश्दींनी एआयची संभावना केली. कला आणि कथाकथनाच्या भूमिकेवर भाष्य करताना रश्दी म्हणाले की, 'सर्जनशील कलाकृतींनी केवळ मनोरंजनाच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्यास भाग पाडणे आवश्यक आहे.' मुलाखतीत त्यांनी सध्या सुरू असलेल्या फुटबॉल विश्वचषकातील सामन्यांविषयीही उत्सुकता व्यक्त केली.

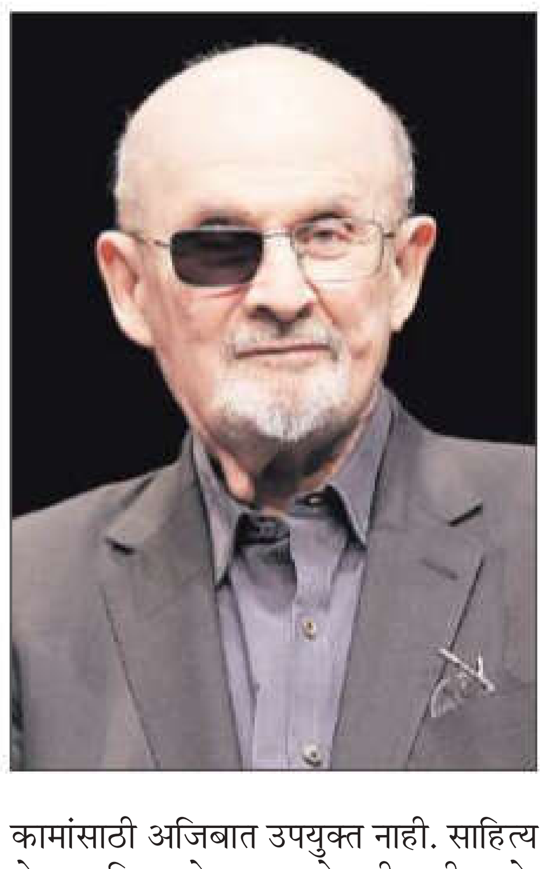

जागतिक साहित्याला आकार देणाऱ्या एका महत्त्वाच्या व्यक्तीची दरवर्षी या पुरस्कारासाठी निवड केली जाते. यापूर्वी नोबेल विजेते व्ही. एस. नायपॉल, वास्तुविशारद झाहा हदीद आणि चित्रपट निर्माते फ्रान्सिस फोर्ड कोपोला यांना या पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे.

6 | संपादकीय
जनसत्ता | 11 जुलाई, 2026

कल्पमेधा

दौलत की वजह से आदमी को जो सम्मान मिलता है, वह दरअसल उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है।
– मुंशी प्रेमचंद

जिम्मेदारी का दायरा

आमतौर पर किसी हादसे के बाद उसके कारणों पर बात होती है। सरकार मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच एजंसी गठित करती है। मगर उसके बाद शायद ही कभी कारणों के तमाम पहलुओं के आधार पर हादसों से निपटने के लिए कोई व्यापक कार्ययोजना बनती है और उसे एक नियमन की तरह देखा जाता है। लगभग सभी दुर्घटनाओं और उनकी जांच रिपोर्ट को एक खास घटना के दायरे में समेट कर देखा जाता है। जबकि सबसे जरूरी यह होना चाहिए कि किसी हादसे के बाद उसके कारणों को ध्यान में रख कर भविष्य के लिए ऐसे इंतजाम किए जाएं, ताकि वैसा दोबारा न हो। एक अहम पहलू यह भी है कि हमारे यहां हादसों के बाद संवेदना जाहिर करने से लेकर सवाल उठाने तक में तो कमी नहीं की जाती, लेकिन उससे बचाव के पूर्व-इंतजामों को लेकर शायद ही कभी गंभीरता दिखाई जाती है। यही वजह है कि एहतियाती उपायों की अनदेखी आखिर किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है और उसमें जानमाल की क्षति होती है।

कुछ समय पहले दिल्ली और लखनऊ की दो अलग-अलग घटनाओं ने इस मसले पर सरकारी महकमों की उदासीनता और लापरवाही की एक अघोषित तौर पर चलती रहने वाली उस 'व्यवस्था' को उजागर किया, जो ऐसे हादसों की मूल वजह है। दरअसल, दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक इमारत में लगी आग में फंसने के बाद जहां इक्कीस लोगों की जान चली गई, वहीं लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान में इसी तरह की घटना में पंद्रह विद्यार्थियों की मौत हो गई। निश्चित तौर पर इसके लिए उन इमारतों के प्रबंधन की जवाबदेही बनती है, लेकिन सवाल है कि जिन लापरवाहियों या खामियों की वजह से वे भयावह हादसे हुए, उनकी जांच करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? कायदे से इसके लिए उन सरकारी महकमों और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जिनका दायित्व है कि वे समय-समय पर इमारतों में अग्निशमन से लेकर बचाव इंतजामों की जांच करें।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और लखनऊ में आग लगने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को नगर निकायों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन न करने वाले शीर्ष अधिकारी अब व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। अदालत की यह टिप्पणी बेहद अहम है कि हादसों के बाद सिर्फ भवन निर्माताओं को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि घटना वाले क्षेत्र के अधिकारियों को छोड़ दिया जाता है। यह छिपा नहीं है कि किसी इमारत में आग लगने की वजह से अगर लोग मारे जाते हैं, तो उसकी मुख्य वजह बचाव के इंतजामों को ताक पर रख देना होता है। मसलन, अचानक आग लगने की स्थिति में उसे बुझाने या उससे बचने के लिए वैकल्पिक निकास की ठोस व्यवस्था न होना लोगों की जान जाने की सबसे बड़ी वजह होती है। आजकल कई इमारतों में सुरक्षा के आधुनिक इंतजाम के नाम पर 'डिजिटल दरवाजे' लगा दिए जाते हैं, जो हादसे की स्थिति में काम करना बंद कर देते हैं और उसमें लोग फंस कर मारे जाते हैं। सवाल है कि अग्निशमन से लेकर बचाव के तमाम उपायों को सख्ती से लागू कराना किसकी जिम्मेदारी है। इसलिए यह बिल्कुल उचित सवाल है कि केवल इमारतों के मालिकों या प्रबंधकों को कठघरे में खड़ा करना काफी नहीं है, बल्कि हादसे की मुख्य जड़ यानी संबंधित महकमे और शीर्ष अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी का इलाज करना जरूरी है।

दावे और हकीकत

राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते अमूमन यह माना जाता है कि दिल्ली में समूची व्यवस्था अन्य शहरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगी। सरकार और स्थानीय प्रशासन के दावों में भी यही झलकता है, लेकिन चिंता की बात यह है कि जब हकीकत सामने आती है, तब भी उसमें सुधार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है बारिश के दिनों में दिल्ली की रफ्तार थम जाना। हर साल राजधानी के बाशिंदों को जलभराव और यातायात अवरुद्ध हो जाने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में समग्र विकास के आश्वासनों के साथ सत्ता परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन समस्याओं का संजाल अभी भी कमोबेश वैसा ही बना हुआ है। यही वजह है कि बीते गुरुवार को मानसून की पहली तेज बारिश में ही कई जगह सड़कें तालाब बन गईं, यातायात ठप हो गया और लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। सवाल है कि बरसात से पहले संबंधित महकमों की ओर से जिन पूर्व तैयारियों का भरोसा दिलाया जाता है, वे समय आने पर कहां गायब हो जाती हैं!

कहने को राष्ट्रीय राजधानी में हर साल मानसून के आगमन से काफी पहले समस्याओं से निपटने की औपचारिक तैयारी शुरू हो जाती है। इसके तहत मुख्य रूप से छोटे-बड़े नालों और सड़क किनारे जलनिकासी के लिए बनीं नालियों की सफाई करनी होती है। मगर इन तैयारियों का अधिकांश कार्य कागजों तक ही सीमित रहता है। जाहिर है कि सरकार का जोर व्यवस्था को सुधारने पर कम और दावों पर ज्यादा रहता है। यह बात भी छिपी नहीं है कि दिल्ली में जलभराव की समस्या पर सियासत भी खूब होती है। इस बार भी सत्ता पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि पिछली सरकार के कार्यकाल के मुकाबले जलभराव का संकट काफी कम हुआ है। वहीं, विपक्ष का कहना है कि दो-तीन चिह्नित स्थलों को छोड़कर बाकी जगह का हाल जस का तस बना हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार तुलनात्मक सुधार का हवाला देकर अपनी पीठ थपथपाने के बजाय समस्या की गंभीरता पर ध्यान केंद्रित करे और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, ताकि लोगों को बारिश में किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े।

कृत्रिम मेधा के समांतर कसौटी पर विवेक

देश में शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर होने लगा है। सवाल है कि क्या हम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं या तकनीक हमारी बौद्धिक स्वतंत्रता को संचालित करने लगी है?

अतुल अग्रवाल

पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम मेधा यानी एआइ ने जिस तेजी से दुनिया को बदला है, उसने औद्योगिक और इंटरनेट क्रांति की स्मृतियों को ताजा कर दिया है। कभी कल्पित विज्ञान का विषय मानी जाने वाली यह तकनीक आज हमारे मोबाइल फोन, कार्यालयों, अस्पतालों, न्यायालयों और विद्यालयों तक पहुंच चुकी है। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल जिस स्तर पर होने लगा है, उससे यह पूरी संभावना है कि आने वाले वर्षों में कक्षाओं का स्वरूप, शिक्षण की पद्धति और सीखने की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं रहने वाली। मगर प्रत्येक तकनीकी क्रांति अपने साथ एक मूलभूत प्रश्न भी लेकर आती है- क्या हम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, या धीरे-धीरे तकनीक हमारी बौद्धिक स्वतंत्रता को संचालित करने लगी है? यही सवाल आज शिक्षा जगत के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है।

इसमें दोराय नहीं कि कृत्रिम मेधा ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाओं के द्वार खोले हैं। आज एक विद्यार्थी घर बैठे विश्वस्तरीय अध्ययन-सामग्री तक पहुंच सकता है। कठिन वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल भाषा में समझ सकता है, विदेशी भाषाएं सीख सकता है और अपनी कमजोरियों का विश्लेषण भी कर सकता है। दूसरी ओर, शिक्षक भी एआइ की सहायता से पाठन योजनाएं तैयार करने, विद्यार्थियों के सीखने की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने और उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने में समर्थ हो रहे हैं। यदि एआइ का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, तो यह शिक्षा को अधिक समावेशी, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने का सशक्त माध्यम बन सकती है।

मगर यहीं से इस परिवर्तन का दूसरा पक्ष भी सामने आता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना अर्जित करना नहीं, बल्कि चिंतन, तर्क, विवेक और व्यक्तित्व का विकास करना है। यदि किसी विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कुछ ही क्षणों में मिल जाए, तो क्या वह प्रश्नों से जूझने का धैर्य विकसित कर पाएगा? यदि निबंध, परियोजनाएं और शोध-कार्य कृत्रिम मेधा के भरोसे तैयार होने लगें, तो मौलिक चिंतन और सृजनात्मकता का भविष्य क्या होगा? दरअसल, शिक्षा की वास्तविक शक्ति उत्तर में नहीं, बल्कि उस बौद्धिक यात्रा में निहित होती है, जो उत्तर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति स्वयं तय करता है। यदि यह यात्रा समाप्त हो गई, तो शिक्षा केवल सूचना-संग्रह का माध्यम बनकर रह जाएगी। ऐसे में यह मान लेना कि एआइ शिक्षक का स्थान ले सकती है, वास्तविकता से कोसों दूर है। एक मशीन तथ्यों का संकलन कर सकती है, मगर चरित्र का निर्माण नहीं। वह भाषा सिखा सकती है, मगर संवेदनशीलता नहीं। वह जानकारी दे सकती है, पर प्रेरणा नहीं। शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ाता, बल्कि विद्यार्थी के भीतर जिज्ञासा, आत्मविश्वास, अनुशासन और नैतिक दृष्टि का विकास भी करता है।

शिक्षा का सबसे जीवंत पक्ष मनुष्य के बीच का संवाद है, जिसे कोई 'एल्गोरिद्म' प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। इसलिए एआइ को शिक्षक का विकल्प नहीं, बल्कि उसका सहयोगी मानना ही विवेकपूर्ण दृष्टिकोण होगा। हालांकि, चुनौती केवल यहीं तक सीमित नहीं है। कृत्रिम मेधा का विस्तार शिक्षा में एक नई सामाजिक असमानता को भी जन्म दे सकता है। महानगरों के विद्यार्थियों के पास

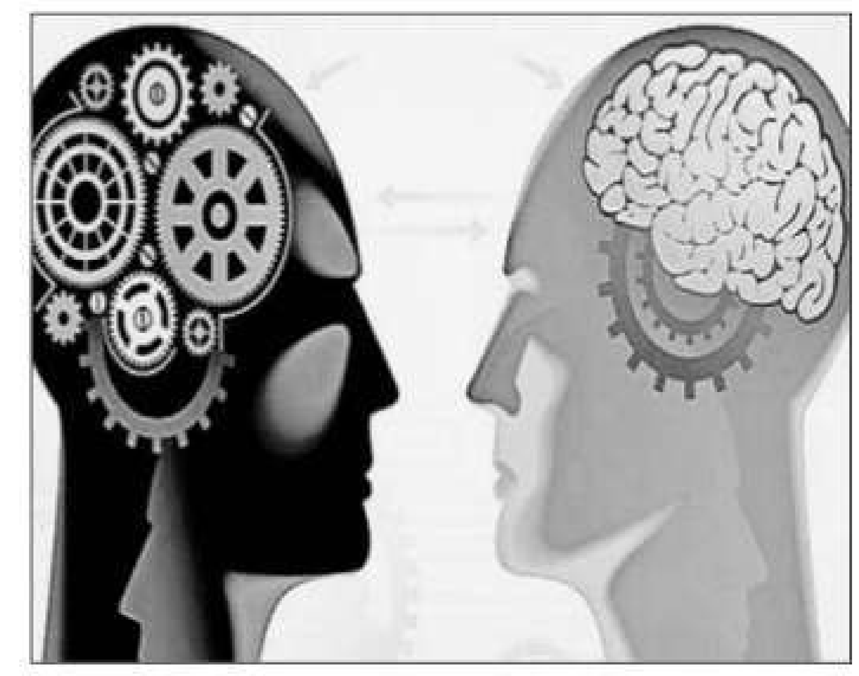

उच्च गति का इंटरनेट, आधुनिक उपकरण और डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं, जबकि देश के अनेक ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का अभाव है। यदि भविष्य की शिक्षा एआइ पर आधारित होगी और तकनीकी संसाधनों तक पहुंच असमान बनी रहेगी, तो यह अंतर केवल

> **आज आवश्यकता तकनीक से भयभीत होने की नहीं, बल्कि उसके प्रति विवेकपूर्ण दृष्टि विकसित करने की है। शिक्षा का लक्ष्य ऐसे विद्यार्थी तैयार करना नहीं हो सकता, जो केवल कृत्रिम मेधा का कुशल उपयोग करना जानते हों। उसका उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना है, जो प्रश्न पूछ सकें, तर्क कर सकें, असहमति व्यक्त कर सकें, सृजन कर सकें और नैतिक निर्णय ले सकें। यही वे गुण हैं, जो मनुष्य को मशीन से अलग करते हैं। यदि हम विचार की स्वतंत्रता का मूल्य भूल बैठे, तो आने वाली पीढ़ियां ज्ञान से संपन्न अवश्य होंगी, लेकिन बुद्धिमत्ता से नहीं। शिक्षा में कृत्रिम मेधा का स्वागत अवश्य होना चाहिए, पर उसके साथ मानवीय विवेक की मशाल भी उतनी ही प्रज्वलित रहनी चाहिए।**

डिजिटल नहीं रहेगा, बल्कि यह अवसरों, रोजगार और सामाजिक प्रगति के बीच गहरी खाई में बदल सकता है। इसलिए एआइ के युग में डिजिटल समानता केवल तकनीकी नीति का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का भी विषय है।

एक गंभीर चिंता उभर रही है डेटा की सुरक्षा एवं निजता की। एआइ आधारित मंच विद्यार्थियों की अध्ययन-शैली, व्यवहार, रुचियों और व्यक्तिगत जानकारी का विशाल भंडार तैयार कर रहे हैं। शिक्षा का डिजिटलीकरण तभी सार्थक होगा, जब इन सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। यदि यह डेटा व्यावसायिक हितों का साधन बन गया या साइबर अपराधों का शिकार हुआ, तो तकनीक पर समाज का विश्वास डगमगा जाएगा। इसलिए एआइ के विस्तार के साथ कठोर डेटा-सुरक्षा कानून, पारदर्शी नीतियां और उत्तरदायी नियामक व्यवस्था अनिवार्य हो जाती है। आज भी हमारी परीक्षा-प्रणाली का बड़ा हिस्सा रटने, लिखित उत्तरों और अंक-केंद्रित मूल्यांकन पर आधारित है। ऐसी व्यवस्था में एआइ का दुरुपयोग रोकना लगभग असंभव है। आवश्यकता इस बात की है कि मूल्यांकन की दिशा बदली जाए। परियोजना-आधारित अध्ययन, समस्या-समाधान, मौखिक प्रस्तुतियां, अनुसंधान, समूह-चर्चा और प्रयोगात्मक गतिविधियां शिक्षा के केंद्र में आएं। जब विद्यार्थी की सफलता उसकी स्मरण-शक्ति से अधिक उसकी समझ, विश्लेषण और सृजनात्मकता से आंकी जाएगी, तभी कृत्रिम मेधा सीखने का प्रभावी उपकरण सिद्ध होगी।

सरकार, शिक्षण संस्थान और समाज, इन तीनों की भूमिका इस परिवर्तन में समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। सरकार को डिजिटल अवसंरचना का विस्तार करना होगा, शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देनी होगी तथा विद्यालयी शिक्षा में एआइ साक्षरता और डिजिटल नैतिकता को समाहित करना होगा। शिक्षण संस्थानों को ऐसी शैक्षणिक संस्कृति विकसित करनी होगी, जिसमें तकनीक का उपयोग हो, मगर उस पर निर्भरता न हो। वहीं, बच्चों को यह समझाना होगा कि तकनीक सुविधा का साधन है, बुद्धि का विकल्प नहीं। दरअसल, किसी भी दौर की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं होती कि उसने कौन-सी तकनीक विकसित की, बल्कि यह होती है कि उसने उस तकनीक का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया। कृत्रिम मेधा का उपयोग शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए किया गया, तो यह सबसे बड़ी शैक्षिक क्रांति सिद्ध हो सकती है। मगर यह तकनीक यदि मौलिक चिंतन, बौद्धिक परिश्रम और नैतिक उत्तरदायित्व का स्थान लेने लगी, तो यही उपलब्धि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है।

इसलिए आज आवश्यकता तकनीक से भयभीत होने की नहीं, बल्कि उसके प्रति विवेकपूर्ण दृष्टि विकसित करने की है। शिक्षा का लक्ष्य ऐसे विद्यार्थी तैयार करना नहीं हो सकता, जो केवल कृत्रिम मेधा का कुशल उपयोग करना जानते हों। उसका उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना है, जो प्रश्न पूछ सकें, तर्क कर सकें, असहमति व्यक्त कर सकें, सृजन कर सकें और नैतिक निर्णय ले सकें। यही वे गुण हैं, जो मनुष्य को मशीन से अलग करते हैं। यदि तकनीक के साथ मानवीय संवेदना, नैतिक विवेक और स्वतंत्र चिंतन का संतुलन बना रहा, तो कृत्रिम मेधा शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मगर सुविधा के आकर्षण में यदि हम विचार की स्वतंत्रता का मूल्य भूल बैठे, तो आने वाली पीढ़ियां ज्ञान से संपन्न अवश्य होंगी, लेकिन बुद्धिमत्ता से नहीं। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके कृत्रिम मस्तिष्कों में नहीं, बल्कि उसके जागरूक, विचारशील और संवेदनशील नागरिकों में निहित होती है। इसलिए शिक्षा में कृत्रिम मेधा का स्वागत अवश्य होना चाहिए, पर उसके साथ मानवीय विवेक की मशाल भी उतनी ही प्रज्वलित रहनी चाहिए।

विकास का पाठ

दुनिया मेरे आगे

राजेंद्र जोशी

किसी भी राष्ट्र के विकास की सबसे मजबूत नींव उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश का प्रत्येक बच्चा विद्यालय तक पहुंचे, नियमित रूप से अध्ययन करे और अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करे। इसलिए अब केवल सौ फीसद नामांकन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सौ फीसद ठहराव और शून्य 'ड्राप आउट' यानी बीच में एक भी बच्चा स्कूल न छोड़े, इसे राष्ट्रीय लक्ष्य बनाया जाना चाहिए।

हाल ही में नीति आयोग द्वारा भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर जारी रिपोर्ट में झारखंड से एक अत्यंत उत्साहजनक समाचार सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014-15 में झारखंड में प्राथमिक स्तर पर 'ड्राप आउट' दर 6.41 फीसद थी, जो वर्ष 2024-25 में घटकर शून्य हो गई है। इसी प्रकार माध्यमिक स्तर पर यह दर 23.2 फीसद से घटकर केवल 3.5 फीसद रह गई है। यह उपलब्धि केवल झारखंड की नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का विषय है। इससे यह सिद्ध होता है कि अगर सरकार, प्रशासन, विद्यालय और समाज मिलकर योजनाबद्ध ढंग से कार्य करें, तो बीच में स्कूल छोड़ने जैसी गंभीर समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा उसे विद्यालय में बनाए रखने पर विशेष बल देती है। इसके बावजूद देश के सामने आज भी विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की समस्या गंभीर बनी हुई है। अगर सकल नामांकन अनुपात यानी जीईआर के आंकड़ों पर दृष्टि डालें, तो यह चिंता और बढ़ जाती है। कक्षा छह से आठ तक जीईआर लगभग 90.9 फीसद है, जबकि कक्षा नौ-दस में यह घटकर 79.3 फीसद रह जाता है। कक्षा 11-12 तक पहुंचते-पहुंचते यह केवल 56.5 फीसद रह जाता है। स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में बच्चे, विशेष रूप से कक्षा आठ के बाद शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। यह स्थिति शिक्षा के साथ-साथ देश के सामाजिक और आर्थिक विकास से भी सीधे जुड़ी हुई है।

> **विकसित भारत का निर्माण केवल आर्थिक प्रगति से नहीं होगा। इसके लिए शिक्षित, कुशल, संवेदनशील और जागरूक नागरिकों का निर्माण आवश्यक है। प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक अभिभावक और पूरे समाज को यह संकल्प लेना होगा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।**

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सहित विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि बच्चों के स्कूल छोड़ने के अनेक कारण हैं। गरीबी, बाल श्रम, बाल विवाह, प्रवासी मजदूर परिवारों का लगातार स्थान परिवर्तन, विद्यालयों की दूरी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी और शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव इसके प्रमुख कारण हैं। झारखंड की सफलता यह संदेश देती है कि अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और सामाजिक सहभागिता के साथ आए तो परिवर्तन संभव है। आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित उन सभी राज्यों में विशेष अभियान चलाए जाएं जहां विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या अभी भी चिंताजनक है।

बीच में स्कूली पढ़ाई छोड़ने की समस्या पर काबू पाने के लिए सबसे पहले विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना होगा। प्रत्येक बच्चे के लिए पूर्व-प्राथमिक से कक्षा बारह तक सुरक्षित, आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। सरकारी विद्यालयों की विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विद्यालयों में पर्याप्त कक्षाएं, प्रशिक्षित शिक्षक, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, अलग शौचालय तथा डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। जहां विद्यालय नहीं हैं, वहां नए विद्यालय स्थापित किए जाएं और आवश्यकता के अनुसार छात्रावासों का निर्माण किया जाए। विशेष रूप से बालिकाओं के लिए सुरक्षित छात्रावास और सुगम परिवहन की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अनेक बालिकाएं केवल दूरी और सुरक्षा के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं।

प्रवासी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे बच्चों के लिए वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र, लचीली अध्ययन व्यवस्था तथा सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता है। स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय समाज की भागीदारी से ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से फिर जोड़ा जा सकता है। नामांकन के बावजूद कोई बच्चा लगातार अनुपस्थित रहता है, तो उसके अभिभावकों से संपर्क करके विद्यालय छोड़ने के कारणों का समाधान खोजना चाहिए। अगर किसी कारणवश कोई बच्चा विद्यालय छोड़ देता है तो उसकी वापसी भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं, सेतु पाठ्यक्रम तथा अतिरिक्त अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे वे बिना किसी संकोच के फिर अपनी कक्षा के अनुरूप अध्ययन प्रारम्भ कर सकें। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए विशेष प्रयास आवश्यक हैं। ऐसे क्षेत्रों में सामुदायिक साक्षरता केंद्र, लचीले समय की अध्ययन कक्षाएं तथा विशेष शिक्षण केंद्र संचालित किए जा सकते हैं, जहां बच्चे अपनी परिस्थितियों के अनुसार पढ़ाई जारी रख सकें। इससे उनका विद्यालय से संबंध बना रहेगा और भविष्य में उनकी नियमित शिक्षा भी बाधित नहीं होगी।

विकसित भारत का निर्माण केवल आर्थिक प्रगति से नहीं होगा। इसके लिए शिक्षित, कुशल, संवेदनशील और जागरूक नागरिकों का निर्माण आवश्यक है। प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक अभिभावक और पूरे समाज को यह संकल्प लेना होगा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। झारखंड ने यह सिद्ध कर दिया है कि बीच में स्कूल छोड़ने की दर को शून्य करना कोई असंभव लक्ष्य नहीं है। यह उपलब्धि पूरा देश हासिल कर सकता है। अब समय आ गया है कि 'हर बच्चा विद्यालय में, हर बच्चा शिक्षा में और कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं', केवल एक नारा न रहकर राष्ट्रीय संकल्प बने। विकसित भारत की यात्रा का सबसे सशक्त आधार यही होगा।

मिलावट का दंश

वाजिब दाम चुकाने के बावजूद आज उपभोक्ता मिलावटी सामान खरीदने पर मजबूर है। तेल, घी, दूध, मावा, शहद, पनीर, मक्खन और मसाले से लेकर पेट्रोल-डीजल तक में मिलावट हो रही है। सही माप का अभाव भी दिखाई देता है। पिछले दिनों खंडवा में नकली घी और तेल बनाने के लिए फैक्टरी में भारी मात्रा में अवैध रूप से जमा की गई चर्बी मिली। धार जिले के धामनोद में मिर्च पाउडर में मिलावट की सामग्री का कारोबार पकड़ में आया। इसके अलावा आज कच्चे केले, तरबूज, खरबूज और विभिन्न प्रकार के आमों को समय से पहले रसायन से पका कर बाजारों में बेचा जा रहा है। सरकारी स्तर पर इसके लिए निगरानी तंत्र होने के बावजूद यह सब बदस्तूर जारी है। त्योहारों पर प्रतिवर्ष भारी मात्रा में नकली मावा, दूध और घी बरामद कर माफिया पर रस्मी और दिखावे की कार्रवाई की जाती है। नमूने के हेरफेर होने से आरोपियों को सजा नहीं मिल पाती। मिलावट और नापतोल में गड़बड़ी हो रही है, तो यह खाद्य विभाग की कमजोरी है। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उपभोक्ता को मानकयुक्त सामग्री मिले, यह शासन की जिम्मेदारी है।

– देवेंद्र काशिव, धार, मप्र

दायित्व से इतर

शिक्षक समाज और राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। उनका मुख्य कार्य विद्यार्थियों को शिक्षा देना है। मगर कई बार उनको चुनाव ड्यूटी, जनगणना, सर्वेक्षण, विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगाया जाता है। इससे शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ा नुकसान विद्यार्थियों का होता है। जब शिक्षक विद्यालय में उपस्थित नहीं रहते, तो नियमित कक्षाएं बाधित हो जाती हैं। इससे पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। विशेष रूप से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा नुकसान शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट के रूप में सामने आता है। शिक्षक अपना पूरा ध्यान पढ़ाने के बजाय अन्य सरकारी कार्यों में लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। इससे वे पाठ योजना, विद्यार्थियों के मूल्यांकन तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाते।

– कुमार गौरव, मधुबनी

हरित दायरा

चौमासा आते ही देशभर में हरित क्षेत्र बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाता है। सार्वजनिक स्थलों और स्कूल-कालेजों में बड़े पैमाने पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मगर प्रायः देखा गया है कि अधिकांश आयोजन सिर्फ प्रचार और तस्वीर खिंचवाने की रस्म अदायगी तक सीमित रह जाते हैं। लगाए गए पौधों की देखभाल में कोई भी रुचि नहीं लेता और उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। एक समय ऐसा आता है जब पौधे सूखने लगते हैं। जबकि हमें पौधा रोपने के बाद कम से कम पांच साल तक यानी जब तक लगाया गया पौधा वृक्ष का रूप धारण नहीं कर लेता, तब तक उसकी देखभाल जरूर करनी चाहिए। पर्यावरण को सुरक्षित रखने और हरित आवरण बढ़ने की दिशा में जन भागीदारी भी बहुत जरूरी है। हर वर्ष लाखों पौधे लगाने का दावा अर्थहीन न हो जाए, यह ध्यान रखना होगा।

– वेद प्रकाश, गुरुग्राम

शहर पानी-पानी

मानसून में आजकल जनजीवन अस्त-व्यस्त क्यों हो जाता है। सूरत में एक माल तरणताल जैसा बन गया, वहीं मुंबई में तो हर साल बदतर स्थिति हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, यह समझना मुश्किल नहीं है। इस बार बरसात के शुरुआती दिनों में पूरा महाराष्ट्र पानी-पानी हो गया। इसी बीच मुंबई में इतने पेड़ धराशायी हो गए कि उन्हें देख कर भय लगता है। कंक्रीट के जंगलों में पेड़-पौधे अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। बड़े शहरों में पानी की निकासी पर कोई असरदार मास्टर प्लान क्यों नहीं बनाया जाता है, जिससे सभी शहरों को इसका फायदा मिले। कब तक शहरों में लोग बारिश के दौरान परेशान होते रहेंगे। लाखों-करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी व्यवस्था कब सुधरेगी। इस बार भी बारिश ने नगर निकायों की पोल खोल दी है। यह चिंता का विषय है। शहरों में जलभराव को रोकने के लिए स्थायी इंतजाम होना चाहिए।

– हरिहर सिंह चौहान, इंदौर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी की तिथि पर हुई थी। अक्तूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सौ रुपए का सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिस तरह महान नदियां अपने तटों पर मानव सभ्यताओं का पोषण करती हैं उसी तरह आरएसएस ने भी असंख्य लोगों को समृद्ध किया है। संघ की शाखा का मैदान एक ऐसी प्रेरणा भूमि है जहां स्वयंसवेक की अहं से वयं तक की यात्रा शुरू होती है।

धीरज धर्म मित्र अरु नारी
आपद काल परिखिअहिं चारी

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने चढ़ावा चोरी मामले में अपना पक्ष तुलसीदास की इन पंक्तियों से रखा। हालांकि चंपत राय को अपने मित्रों से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आस्था पर इतने बड़े प्रहार के बाद भी बहुत दबाव के बाद उनसे महज इस्तीफा भर लिया गया है। चारों तरफ से चंपत राय की सादगी और निष्कलंक होने के प्रमाणपत्र आ रहे हैं। जहां तक धर्म की बात है, उसे चंपत राय से कई शिकायतें होंगी। धर्म और आस्था की नगरी का तो दृश्य ऐसा होना चाहिए था कि आरोप लगते ही चंपत राय को अपना पद वैसे ही त्याग देना चाहिए था, जैसे श्रीराम ने अपनी प्रिया को त्यागा था। जिस अयोध्या नगरी के कोने-कोने में मानस की पंक्तियां लिखी हैं, वहां संघ का सौ साल का संघर्ष भी चढ़ावा चोरों को धर्म याद नहीं दिला पाया। शताब्दी वर्ष में अयोध्या से मिले संघ को संदेश पर बेबाक बोल।

बेबाक बोल

शताब्दी संदेश

मुकेश भारद्वाज

संघ केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जो रोज शाखा आते हैं, बल्कि इसका असली बल वह व्यापक समाज है जो संघ के विचारों से सहमत है और समाज में रहकर काम कर रहा है।

संघ के तृतीय सरसंघचालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस ने संघ की शक्ति के आधार की व्याख्या कुछ इस तरह से की थी। संघ के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि संघ उन लोगों के दम से है जो संघ में नहीं हैं और संघ के हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद पिछले दिनों संघ सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मान कर गंभीरता से व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए जाएं, ताकि अयोध्या-मंदिर पर करोड़ों रामभक्तों की आस्था-श्रद्धा अखंड और अटूट बनी रहे।

होसबाले की अपेक्षा उचित है। लेकिन बात अयोध्या-मंदिर पर आस्था की नहीं है। अयोध्या पर राम भक्तों की आस्था तब से है, जब इतिहास के दस्तावेजी पन्ने शुरू नहीं हुए थे। अयोध्या पर भक्तों की आस्था तब से है, जब से उन्होंने वाल्मीकि की रामायण और तुलसी के मानस को मंदिर की तरह माना। अयोध्या पर आस्था तब भी थी, जब रामलला तंबू में विराजमान थे। अयोध्या पर राम भक्तों की आस्था तब से है, जब संघ ने रामजन्मभूमि मंदिर की लड़ाई की अगुआई अपने हाथ में नहीं ली थी। अयोध्या पर आस्था तब भी रही, जब मंदिर के उद्घाटन में सत्ता पक्ष की घोर राजनीति देखी गई और आस्था तब भी अक्षुण्ण है जब राम के धाम पर चढ़ावा चोरी का संकट आया।

आज सवाल अयोध्या पर आस्था का नहीं, संघ पर आस्था का है। देश के करोड़ों रामभक्त संघ की शाखा में गए बिना ही संघ के हो गए क्योंकि उसने राम-मंदिर के लिए संघर्ष की अगुआई की। संघ की अनगिनत शाखाएं हर उस घर में लगने लगी, जहां राम-मंदिर के निर्माण में योगदान देने के लिए बचत की जाने लगी। हर घर की नानी-दादी संघ की हो गई जिनकी गुल्लक में मंदिर के लिए चढ़ावा जमा होने लगा।

आस्था का नेतृत्व करना आसान नहीं होता है। इसमें आपको अयोध्या-नगरी जैसी होना होगा। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है, जिसे युद्ध के द्वारा न जीता जा सके, जो युद्ध के योग्य न हो। अयोध्या की भव्यता उससे जुड़ी आस्था ही है। राम वनवास गए तो अयोध्या की आस्था रही कि आराध्य यहीं लौटेंगे। अयोध्या पर आस्था तब भी रही, जब भरत ने वहां के सिंहासन पर श्रीराम की चरण-पादुका रख दी। अवध का वध नहीं हो सकता। अयोध्या अमर है।

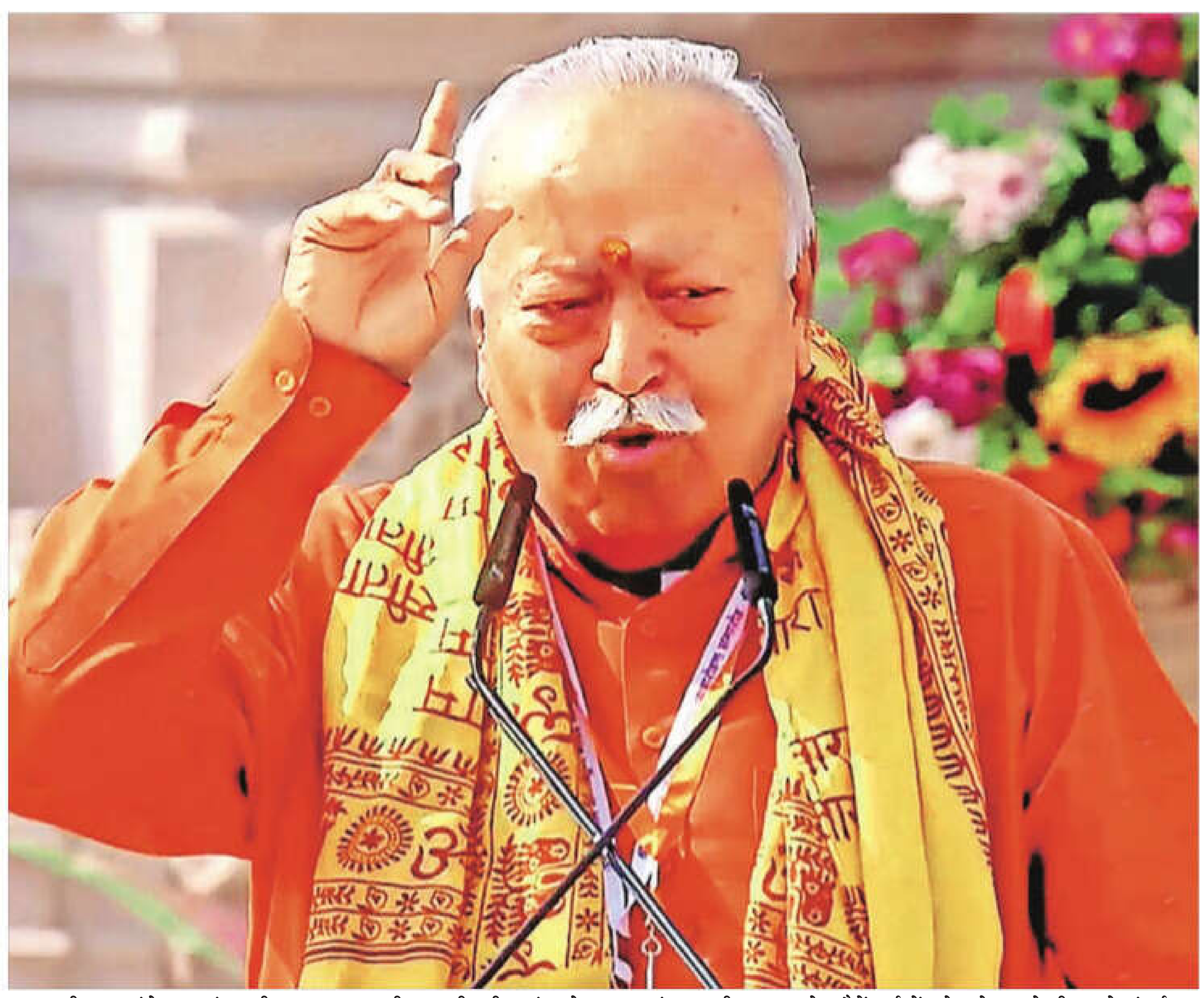

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भव्यता उसकी सादगी थी। संघ के स्वयंसेवकों का जुड़ाव जल-जंगल-जमीन वाले मुहावरे से था। स्वयंसेवकों को जहां आसरा मिलता था सो जाते थे, जो उपलब्ध होता था, खा लेते थे। जिन्हें कल के लिए संचय की चिंता नहीं हो वही उस मंदिर के लिए लड़ाई लड़ सकते थे, जिसके बनने की तारीख उसे पता नहीं थी। संघ आस्था के बल पर ही कहता था-मंदिर वहीं बनाएंगे, और उसके इस नारे पर राम-भक्तों की आस्था हुई। अब राम-मंदिर के निर्माण को एक तारीख मिल चुकी है।

संघ अपनी स्थापना के सौवें वर्ष में प्रवेश के पहले ही अपने संघर्ष पर विजय प्राप्त कर चुका था। मंदिर-निर्माण को एक तारीख मिलते ही उसके पास संघर्ष का मीठा फल आने लगा। अब संघ स्वभावतः सादगी से संपन्नता की ओर बढ़ने लगा।

संघ के नेतृत्व से जुड़े लोगों की महंगी गाड़ियों के कारवां को देख कर भी भक्तों ने कहा, इन्हें हक है। दिल्ली में आपकी कर्मभूमि झंडेवालान में भव्यता का झंडा गड़ने लगा, अन्य जगहों पर बन रहे दफ्तरों को भी आपका जायज हक माना गया। मंदिर तो राम-भक्तों के धन से बना, लेकिन अब आपको जनता के आयकर से मिली सरकारी सुरक्षा पर भी रामभक्तों ने सवाल नहीं उठाए। आस्था के अगुआ को सरकारी सुरक्षा की जरूरत क्यों आन पड़ी यह सवाल बेमानी था। आपके संघर्ष के बीज से खड़ी हुई सत्ता के पेड़ का फल भला आपके लिए निषिद्ध क्यों रहता?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सादगी से संपन्नता की ओर जो गति थी, उसमें राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मामला अब सबसे बड़ा बाधक बन गया है। इसके कारण साफ हैं। इतने बड़े मसले पर सत्ता का शीर्ष नेतृत्व चुप्पी क्यों साधे हुए है? आखिर संघ के नेतृत्व को बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि संगठन का मूलभूत सिद्धांत है कि महज मांग के आधार पर बयान की आपूर्ति नहीं करनी है। अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ सिर्फ अपने मंच से बोलना है। पहले संघ के नेता साक्षात्कार भी नहीं दिया करते थे। इसलिए लोगों को इंतजार रहता था, संघ- सरसंघचालक के विजयादशमी-संदेश का। अब विजयादशमी-संदेश की उत्सुकता भी खत्म होती जा रही है क्योंकि सत्ता का पितृ-पक्ष होने के कारण आपको किसी भी सप्तमी, अष्टमी या नवमी पर बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

राम-मंदिर के चढ़ावा चोरी को केंद्र सरकार से जोड़ कर नहीं देखा जा रहा है। राम मंदिर न्यास को बनाया तो सरकार ने था, लेकिन उसमें ज्यादातर पदाधिकारी संघ से जुड़े थे। इसलिए सबसे ज्यादा सवाल संघ पर ही उठे। चढ़ावा चोरी के बाद न्यास में जो परिवर्तन हुआ है, उसमें भी संघ से ही जुड़े लोग हैं। राम-मंदिर के इतिहास के पांच सदी के पन्नों पर संघ ने अपना दावा किया तो संघ के इतिहास के सौवें साल में चढ़ावा चोरी के आरोप से उसकी विजय-पताका पर सवालों के दाग तो लग गए हैं।

ऊपर उद्धृत किया गया है कि किस तरह से संघ विचारकों का मानना था कि संघ उनसे है, जो संघ में नहीं होकर भी संघ के हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय सत्ता पक्ष के विजय भरे गर्व से कहते हैं-राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद हर सरकारी अधिकारी खुद को आरएसएस का बताने लगा है। अफसर अपनी कमर दिखा कर बताते हैं कि वे भी संघ की शाखा में जाते थे, उन्होंने चड्डी पहनी है और बेल्ट लगाई है। सरकार आने के बाद सभी संघ के हो गए। अब एक तरीके से बहुत भीड़ हो गई है। भीड़ में अच्छे इंसान की कमी हो गई है। संगठन बढ़ रहा है, कहने के लिए विचारधारा भी बढ़ रही है। मगर अच्छे इंसान नहीं होंगे...।

संघ के साथ कौन हैं? बालासाहेब देवरस से लेकर विजयवर्गीय के कथन का अंतर आपके शताब्दी-संघर्ष को गहरा संदेश भी दे रहा है। संघर्ष को सफल होने में सौ साल तक का समय लग सकता है। लेकिन संघर्ष की सफलता को निष्कलंक रखना सबसे बड़ी चुनौती है, तब तो और भी ज्यादा जब आपके संघर्ष के आंगन में सत्ता की कामधेनु खड़ी हो। चढ़ावा चोरी मामले में न्यास के लोगों ने जब बोलना शुरू किया तो समझ में आया कि संघर्ष की राह में कम बोलना क्यों जरूरी होता है? संघ ने सौ साल में जो राजनीतिक सफलता पाई है वह उस संगठन के लिए अभूतपूर्व है जो खुद को राजनीतिक नहीं मानता है। संघर्ष का सफर अनाथ के रूप में शुरू होता है, लेकिन सफलता के सभी सगे हो जाते हैं। सौवें वर्ष पर सगों की भीड़ में अयोध्या-संदेश को जरूर सुनें।

राजपाट

पीके का खौफ

चुनाव आयोग पर विपक्ष अकसर आरोप लगाता है कि वह भाजपा के पक्ष में फैसले करता है। आयोग के हाल के एक फैसले से फिर विपक्ष को आरोप लगाने का मौका मिला है। यह फैसला तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों के उपचुनाव के संबंध में है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की हैं ये सीटें। बिहार में बांकीपुर सीट राज्यसभा के लिए चुने जाने पर नितिन नवीन के त्यागपत्र के कारण खाली हुई है। उपचुनाव तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की कुछ विधानसभा सीटों का भी होना है। पर चुनाव आयोग ने उनकी तारीखों का अभी एलान नहीं किया। उसे तो जल्दी बांकीपुर की थी। जबकि अभी जिन तीन सीटों का 30 जुलाई को उपचुनाव कराया जा रहा है, उनकी भी कोई जल्दी नहीं थी। बेहतर तो यही होता कि पांचों राज्यों की सारी खाली सीटों का उपचुनाव एक साथ कराया जाता। बांकीपुर की जल्दी क्या थी? आरोप है कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग ने यह फैसला किया क्योंकि बांकीपुर से लड़ने का एलान जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने उपचुनाव की घोषणा से पहले ही कर दिया था। बांकीपुर सीट पर वैसे तो नौ बार से लगातार भाजपा ही जीती है। पहले नितिन नवीन के पिता जीते थे। फिर नितिन नवीन जीतते रहे। पिछले चुनाव में उन्होंने राजद की रेखा कुमारी को 50 हजार से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। आरोप है कि भाजपा पीके को तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती थी।

चन्नी से डर नहीं

चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस आलाकमान पर दबाव की रणनीति अपना ली है। पंजाब के कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल इसी हफ्ते सूबे के दौरे पर थे। लेकिन चन्नी ने उन्हें भाव नहीं दिया। वे अपने समर्थक नेताओं की अलग बैठक करते रहे। एलान किया कि दिल्ली जाकर आलाकमान से मिलेंगे। चन्नी चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। आलाकमान किसी को चुनाव से पहले चेहरा नहीं बनाना चाहता। रही चन्नी के अलग पार्टी बनाने की आशंका, तो एक तो उसके लिए अब ज्यादा वक्त है नहीं, दूसरे दलितों में भी विभाजन है। मजहबी दलित और हिंदू दलित। इस विभाजन को बसपा के कांशीराम भी खत्म नहीं कर पाए थे। आलाकमान समझ रहा है कि अलग पार्टी बनाकर चन्नी को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। हां, इतना जरूर है कि दबाव बनाकर वे अपने समर्थकों के लिए ज्यादा टिकट जरूर पा सकते हैं।

छोटे मंत्री जी का बड़ा भाषण

हाल ही में केंद्र सरकार ने एक मंत्रालय का वार्षिक कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया। आयोजन में विभिन्न राज्यों के सहकारिता प्रतिनिधि मौजूद थे, जिनकी उपलब्धियों पर चर्चा होनी थी। मंच पर एक बड़े नेता आसीन थे। पहले संबंधित विभाग के अधिकारियों ने पीपीटी से समझाया। इसके बाद नेताओं के भाषण की शुरुआत हुई। जब राज्य स्तरीय मंत्री ने भाषण के लिए अपना माइक संभाला, तो माना जा रहा था कि बड़े मंत्री बैठे हैं, इसलिए चंद मिनटों में ही इनका भाषण समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब भाषण चलता रहा और छोटे मंत्री जी नहीं थमे, तो बड़े मंत्री जी को एक पर्ची भेजनी पड़ी। पर्ची देखते ही छोटे मंत्री जी का भाषण खत्म हो गया, इसके बाद बड़े मंत्री के भाषण का नंबर आया।

चुनौती बढ़ी

कांग्रेस उम्मीद लगा रही है कि वह इस बार गोवा में सरकार बनाएगी। गोवा में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ ही अगले साल फरवरी में होंगे। लेकिन एक नई पार्टी के चुनाव मैदान में उतरने की संभावना ने कांग्रेस के नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। गोवा कांग्रेस पार्टी के नाम से नए राजनीतिक दल के पंजीकरण की बाबत अखबार में सूचना छपी तो कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा विरोधी मतदाताओं को गुमराह करने की मंशा से इस पार्टी को भाजपा ने बनवाया है। गोवा कांग्रेस पार्टी के कारण कांग्रेस के मतदाता भ्रमित हो सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चौडनकर ने तो खुलेआम आरोप लगाया कि इस पार्टी का अध्यक्ष मर्चेंट नेवी का एक नाविक है, जिसे भाजपा आर्थिक मदद दे रही है। मुश्किल यह है कि कांग्रेस कानूनी रूप से गोवा कांग्रेस पार्टी का पंजीकरण रोक नहीं सकती। तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नाम में भी तो कांग्रेस है। दरअसल गोवा में पिछली बार भी भाजपा बहुकोणीय मुकाबलों के कारण ही जीत पाई थी। उसे 40 में से 20 सीटें मिली थीं। भाजपा विरोधी वोट टीएमसी, एनसीपी, एमजीपी और आम आदमी पार्टी में भी बंट गया था। नतीजतन भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा वोट और सीटें मिल गई थी। इस बार टीएमसी, एनसीपी और आम आदमी पार्टी में पहले जैसा दमखम नहीं दिख रहा है। जिससे कांग्रेस आशान्वित है पर गोवा कांग्रेस पार्टी ने उसका पारा चढ़ा दिया है।

एथेनाल से मिलेगी सियासी ऊर्जा!

एथेनाल मिश्रित पेट्रोल को आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया है। केजरीवाल मध्य-वर्ग के बीच अपनी पुरानी पकड़ वापस पाना चाहते हैं। पंजाब के विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिल सकता है। उन्होंने देश की सभी आटोमोबाइल कंपनियों को पत्र लिखा है। उनसे कहा है कि वे बताएं कि ई-20 मिश्रित पेट्रोल से 2023 से पहले बने वाहनों के इंजन को कोई नुकसान होता है या नहीं। दरअसल केंद्र सरकार कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए पेट्रोल में एथेनाल मिलवा रही है। सरकार एथनाल से वाहनों के इंजन में खराबी की चर्चा को अफवाह बताकर खारिज कर चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल आगे तक की सोचे बैठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आटोमोबाइल कंपनियां कभी गारंटी नहीं लेंगी कि एथनाल का प्रतिकूल असर नहीं होता। वे तो कई ग्राहकों के इंजन खराबी के दावों को मिलावटी पेट्रोल की देन बताती हैं। इसी तरह बीमा कंपनियां भी मिलावटी पेट्रोल को आधार बनाकर खराब वाहनों का मुआवजा देने से कन्नी काटती हैं। अरविंद केजरीवाल इन सब शिकायतों को भी अपने आरोप के समर्थन में जुटा रहे हैं।

संकलन : मृणाल वल्लरी

आपके पत्र

सफेद पोशाक दागदार

‘चंदा चुरावेति चुरावेति’ से आस्था और सियासत के बीच उलझी वारदात के हर पहलू को बारीकी से कुरेदा गया है। अयोध्या से जुड़ी सैकड़ों सालों की कहानी पर यकीन न हो, मगर ‘राम मंदिर’ से की गई चोरी पर यकीन करना होगा। यकीन से इतर बात सपने की है, जिसने सालों पुराने मजहबी झगड़े का रुख मोड़ दिया तो आस्था के सौदागरों के लिए कोई फरिश्ता सपने में आ जाए तो किसे हैरानी होगी? बहरहाल इस वारदात ने सियासी गलियारों तक फैले छोटे-बड़े कई नामों को अपने दायरे में ले रखा है। गलियारों से याद आया कि सियासत की बुनियाद पर खड़े मंदिर के कोने में दुबकी अपने वजूद की गवाही देती ‘चोरी’ से दूर सबूत अवाम से मांगे जा रहे हैं। हालात ऐसे कि सफेद लिबास पहने सारे गुनहगार पिछली हुकूमत को भ्रष्ट बताने में लगे हैं। बदनसीबी इस मुल्क की कि आंखों पर चढ़े धर्म के चश्मे ने सियासत और मजहबी यकीन में फर्क करना छोड़ दिया है। लिहाजा आस्था के खजाने पर पड़े डाके को ‘मामूली सी बात’ कही जाए तो हैरानी नहीं होगी। सियासत और मजहब की भूलभुलैया में जनता की आंखें फिर से धोखा खा जाएं तो जुबान पर ‘हे राम’ का तैर जाना लाजिम है।

-एमके मिश्रा, रांची, झारखंड।

सवालों के घेरे में

सप्ताह भर से मैं भी ग्लानि से भरा हुआ हूं। यकायक दिमाग में सुदर्शन की कहानी ‘हार की जीत’ दिमाग में कौंधी। डाकू खड्गसिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। बिना दल बल, बाबा भारती को अपना घोड़ा मिल गया था। आठ दिन से समाचारपत्र व टीवी न्यूज देख रहा हूं। आलोचना से पन्ने भरे हैं। सुशासन वाली भाजपा व सांस्कृतिक मूल्यों की धरोहर ढो रहा आरएसएस सवालों के घेरे में है। फौज की भर्ती में कब कवायद करता कौन गद्दार घुस जाए। फौज की निंदा नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसमें खुदा के बंदे सरीखे लोग भी रहे हैं। चोर कहां नहीं हैं? राजनीति के विशाल फलक पर यकायक दल-बदल के लिए होते हृदय परिवर्तन को खुलेआम चोरी न कहना, पत्रकारिता की शिष्टता है। दिल्ली के राज सिंहासन से आदेश हुआ ‘गरीबी हटाओ’, वह अब तक नहीं हटी, चाहे चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। शिष्ट चोरियों पर बोलना मना है। रामायण में त्यागी राम और सीता भी आरोपों से आहत हुए थे। चोरी होती थी, होती है और होती रहेगी। जागते रहो की चेतावनी के बावजूद चोरी हो जाती है। क्यों, शायद एक रोटी चुराने वाले बच्चे से पूछा जाए।

-अरविंद पुरोहित, रतलाम, मध्य प्रदेश।

आहत आस्था

तीन सदी की लंबी लड़ाई के बाद रामभक्तों को हासिल हुआ है, यह राम मंदिर। कानूनी लड़ाई के दौरान राम भक्तों ने लाठियां तथा विभिन्न प्रकार के अत्याचार सहन करते हुए अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण किया। यह पूरे देश के लिए भावुक पल था। रामभक्तों ने इतिहास लिखा। अयोध्या आस्था की राजधानी बन गई। रामजन्मभूमि मंदिर न्यास पर भी पूरे देश को भरोसा हुआ। पूरे देश से रामभक्त अयोध्या आने लगे और अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीराम के चरणों में चढ़ावा अर्पित किया। एक भी रामभक्त ने यह नहीं सोचा होगा कि उनके चढ़ावे की चोरी होगी। रामभक्त उस चढ़ावे के लिए आहत नहीं हैं, जो उन्होंने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। वे अपनी आस्था पर पहुंचाई गई विश्वासघात की चोट से आहत हैं। इस मुद्दे पर जिस तरह से कार्रवाई की गई है, वह भी सवालों के घेरे में है। अब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। इसके साथ ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे माहौल में भी आहत रामभक्तों की आस्था ही होगी।

-मीना धानिया, सिरसपुर।

ऐसा विचलन कैसे?

श्रीराम मंदिर से जुड़ा चोरी का विवाद इतना बड़ा न होता, अगर जिम्मेदारों ने जिम्मेदारी से काम लिया होता। मर्यादा के पुरुषोत्तम के मंदिर में मर्यादा ही भुला दी गई। कोई तो एक होता जो आगे आकर कहता कि इस हादसे की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मेरे खिलाफ जो कार्रवाई होगी वह मंजूर होगी। अगर विपक्ष हंगामा नहीं करता तो मामले को रफा-दफा करने की पूरी कोशिश हो गई होती। राम मंदिर पर शोर मचाने वालों के हृदय में भी राम की मर्यादा के लिए कोई जगह नहीं बची। सोच रहा हूं कि श्रीराम क्या वहां उमड़े भक्तों से कहते होंगे कि मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। क्या यह मामला भी रामजी के विधान के तहत ही सामने आया? आज जो लोग सवालों के घेरे में हैं कल वही संघर्ष के मैदान के योद्धा थे। आखिर ऐसा विचलन कैसे हुआ। प्रभु के मंदिर में चोरी करते हुए प्रभु से डर क्यों नहीं लगा? सब कुछ बहुत कष्टकारी है। भक्तों को रामजी का ही आसरा है कि इस कष्ट को भुला कर आस्था के सफर में आगे बढ़ने में मदद करें।

-अंकुर सिंह, गाजियाबाद।

पहरेदारों पर प्रश्न

मंदिर में चोरी पर लिखे बेबाक बोल के लिए सलाम। यह बात सही है कि अपराध तो कहीं भी हो सकता है। मुद्दा यह है कि आपने अपराध के साथ क्या बर्ताव किया? अपराध के अनुपात में तो हर जगह सजा देनी चाहिए, लेकिन जब मामला श्रीराम मंदिर का हो तो क्या उम्मीद करनी चाहिए थी? जो जिम्मेदार शीर्ष पर था, उसे तुरंत अपनी जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्र को एक सकारात्मक संदेश देना चाहिए था। लेकिन हर जिम्मेदार मजबूरी में ही पद छोड़ने को तैयार हुआ। राम के मंदिर में पद और धन को लेकर ऐसी आसक्ति देख कर मन खट्टा हो गया। श्रीराम मंदिर से जुड़ा यह अध्याय सामने नहीं आता तो ही अच्छा होता। मंदिर पर भक्तों की आस्था तो कहीं से भी कम नहीं होनेवाली है, लेकिन आस्था के केंद्र के पहरेदारों पर प्रश्न तो लग ही गए हैं।

-एकता, पटना।

सधे हुए स्वर

बेबाक बोल ने बहुत सधे स्वरों में मंदिर प्रकरण पर अपनी नाराजगी जताई है। इस नाराजगी को हम जैसे लोगों की नाराजगी भी समझी जाए जो राम के मंदिर में भ्रष्टाचार से आहत हैं। मंदिर परिसर में इस तरह अपराधी सक्रिय थे, यह जान कर हैरत होती है। मंदिर के अंदर रह कर भी इनके मन राम और मर्यादा के प्रति समर्पित क्यों न हो सके?

-मीना, गाजियाबाद।

विशेष पन्ना कैसा लगा

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है :
vishesh.jansatta@expressindia.com

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

किसी नई सोच को अपनाने से ज्यादा मुश्किल पुरानी सोच से बाहर निकलना होता है। -बी एच लिडेल हार्ट

यूरेनियम की राह

प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच यूरेनियम आपूर्ति पर बनी सहमति बदलते वैश्विक सामरिक समीकरणों में भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता और स्वच्छ ऊर्जा आधारित विकास की दीर्घकालिक रणनीति के लिहाज से एक अहम उपलब्धि है। जिस देश ने कभी परमाणु अप्रसार के नाम पर भारत के साथ इस क्षेत्र में कोई संबंध रखने से इन्कार कर दिया था, वही आज उसे भरोसेमंद साझेदार मानते हुए उसके लिए अपने विशाल यूरेनियम भंडार खोल रहा है, तो यह भारत की विदेश नीति की एक बड़ी सफलता ही है। दरअसल, 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद कई देशों ने भारत पर व्यापक प्रतिबंध लगाए थे, जिससे भारत को यूरेनियम मिलना तकरीबन बंद ही हो गया था। अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौते के बाद भारत को यूरेनियम आयात करने की अनुमति मिली। 2014 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु समझौता हुआ, हालांकि यूरेनियम का निर्यात शुरू नहीं हो सका, जिस पर अब 12 वर्ष बाद सहमति बनी है। इस बीच, भारत की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ती रहीं और बिजली की मांग का आने वाले वर्षों में भी बढ़ना तय है। दूसरी ओर, जलवायु परिवर्तन की चुनौती और 2070 तक नेट-शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत को कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए बाध्य कर रहा है। ऐसे में, परमाणु ऊर्जा एक भरोसेमंद, स्वच्छ और दीर्घकालिक विकल्प के रूप में उभरी है। सौर व पवन ऊर्जा भी जरूरी हैं, पर उनकी उपलब्धता मौसम पर निर्भर करती है। जबकि, परमाणु ऊर्जा चौबीसों घंटे स्थिर बिजली उत्पादन में सक्षम है। भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता अभी लगभग आठ गीगावाट है, जबकि 2047 तक इसे 100 गीगावाट का लक्ष्य पूरा करना है, जिसके लिए उसे यूरेनियम की जरूरत है। विश्व के ज्ञात यूरेनियम भंडार का करीब एक-तिहाई हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के पास है और अब तक वह चीन, जापान, ताइवान और अमेरिका को यूरेनियम की आपूर्ति करता रहा है। अब भारत को इसमें शामिल करने की वजह दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई प्रगाढ़ता को माना जा सकता है। दरअसल, दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत के मद्देनजर क्षेत्रीय संतुलन के समर्थक हैं और यही साझा इच्छा दोनों को नजदीक लाई है। बहरहाल, ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देगा, पर स्थायी आत्मनिर्भरता के लिए आयातित यूरेनियम के साथ स्वदेशी थोरियम तकनीक, घरेलू परमाणु ईंधन चक्र और अनुसंधान को भी समान गति से आगे बढ़ाना होगा। तभी यह समझौता भारत की ऊर्जा संप्रभुता का आधार बन सकेगा।

क्या ट्रंप के पास कोई और योजना है

बमबारी तथा शुरुआती समझौते के नाकाम होने के बाद, अगर ट्रंप और उनके सहयोगियों के पास अब कोई 'प्लान सी' है, तो दीगर बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो ट्रंप प्रशासन को क्यों लगता है कि आर्थिक युद्ध और बमबारी के मिले-जुले तरीके से इस बार कुछ अलग नतीजा निकलेगा?

डेविड ई सैंगर
पत्रकार एवं लेखक

ईरान के साथ शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले, राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सहयोगियों ने अपनी रणनीति बताई थी। वह यह थी कि होर्मुज जलडमरूमध्य को आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा, और अमेरिका तेल के निर्यात पर लगी रोक हटा देगा, ताकि ईरान अरबों डॉलर का तेल बेच सके। ट्रंप का मानना था कि वर्षों की पाबंदियों के बाद, ईरान को तेजी से भारी कमाई और पश्चिमी देशों के बैंकों में डॉलर तक आसानी से पहुंच मिलने लगेगी। पर, शायद ऐसा नहीं है।

समझौते के एक महीने से भी कम समय में, होर्मुज से गुजर रहे तीन जहाजों पर ईरान की तरफ से हमले हुए। इसके बाद ट्रंप ने उस छूट को रद्द कर दिया, जिसके तहत ईरान तेल बेच सकता था। अमेरिका ने दो रातों में ईरान के 170 से अधिक सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। और, अब स्थायी समझौते पर बातचीत का कोई कार्यक्रम नहीं है, जिस पर दोनों पक्षों ने 60 दिनों में बातचीत पर सहमति जताई थी। बमबारी और शुरुआती समझौते के नाकाम होने के बाद, अगर ट्रंप और उनके सहयोगियों के पास अब कोई 'प्लान सी' है, तो उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। इसके बजाय, ऐसा लगता है कि वे तेल पर पाबंदियों और बमबारी की कार्रवाई की ओर लौट रहे हैं, जिन्हें ट्रंप विनाशकारी बताते हैं, और जिनसे अब तक सिर्फ मौजूदा उलझन ही पैदा हुई है।

बुधवार को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, 'बात बिल्कुल साफ है। अगर वे जहाजों पर गोलीबारी करते हैं, तो हम उन्हें बुरी तरह से तबाह कर देंगे।' दूसरे शब्दों में कहें, तो लालच की नीति छोड़ दी गई है और सख्ती का तरीका फिर से अपनाया जा रहा है। लेकिन, ट्रंप प्रशासन ने अभी तक यह नहीं बताया है कि उसे क्यों लगता है कि आर्थिक युद्ध और बमबारी का यह मिला-जुला तरीका इस बार अलग नतीजा देगा। अनुभवी राजनयिक रिचर्ड एन हास ने कहा, 'अमेरिका एक तरह से रणनीतिक गतिरोध में फंस गया है। दुविधा यह है कि वह जितना ज्यादा हमला करता है, ईरान भी खाड़ी क्षेत्र के तेल और ऊर्जा से जुड़े ढांचे पर उतने ही हमले करने लगता है। वहीं, अमेरिका अभी तक यह नहीं समझ पाया है कि इन ठिकानों की सुरक्षा कैसे की जाए।'

ऐसा लगता है कि ईरान को तेल बेचने से फायदा उठाने देने का फैसला ट्रंप के लिए पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। अपने पहले कार्यकाल में, और कुछ समय पहले तक, वह सख्त रवैया अपनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। लेकिन, लगता है कि ट्रंप भी ईरान में मौजूद गहरे मतभेदों के बीच फंसे हुए हैं। ये मतभेद इस हफ्ते ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान भी साफ तौर पर दिखाई दिए। मुख्य वार्ताकारों में से एक विदेश मंत्री अब्बास अराघची पर भी अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान पत्थर फेंका गया और उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया गया। हमलावरों ने उन्हें बुरा-भला कहा और उनकी मौत की मांग की। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को भी गुस्साई भीड़ से बचाने के लिए सुरक्षा टीम को आगे आना पड़ा। लेकिन, जब ट्रंप ईरान के बारे में सबके सामने बात करते हैं, तो वह समाज में फैली फूट के बारे में बहुत कम बात करते हैं।

नाटो शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद, ट्रंप और उनके सहयोगियों ने अपने अगले कदमों के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम कहा। नाम न बताने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि प्रशासन अब भी शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है, और उन्हें उम्मीद है कि 'तकनीकी बातचीत' जारी रहेगी। लेकिन, इसमें भी विरोधाभास है, क्योंकि तेहरान और वाशिंगटन के बीच मतभेद 'तकनीकी' नहीं हैं, बल्कि वे राजनीतिक हैं, और निचले स्तर के वार्ताकारों के पास उन्हें हल करने का अधिकार नहीं होगा।

एक उदाहरण परमाणु कार्यक्रम के भविष्य से जुड़ा है। जून में हुए संघर्ष विराम समझौते में सभी अहम मुद्दों पर स्थिति साफ नहीं है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या ईरान अपने परमाणु ईंधन के भंडार पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। बराक ओबामा के कार्यकाल में 2015 के एक समझौते के तहत, ईरान ने अपने तब के भंडार का 97 प्रतिशत हिस्सा सौंप दिया था। ट्रंप इस बात को लेकर बहुत संवेदनशील हैं कि उन्हें ओबामा से कम हासिल हो सकता है। लेकिन, पहला राजनीतिक संघर्ष इस सवाल पर हो सकता है कि जलडमरूमध्य पर किसका नियंत्रण होगा। इस मामले में प्रशासन को उस समझौता ज्ञापन में अस्पष्ट भाषा वाले पैराग्राफ की कीमत चुकानी पड़ रही है, जिस पर ट्रंप ने वर्साय में हस्ताक्षर किए थे। यह इसका बेहतरीन उदाहरण है कि जब दस्तावेज में मतभेदों को स्पष्ट करने के बजाय उन्हें अस्पष्ट छोड़ दिया जाता है और बाद में उनकी अलग-अलग तरह से व्याख्या की जाती है, तो क्या होता है।

समझौते के पैराग्राफ पांच में लिखा है-'इस एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद, ईरान अपनी पूरी कोशिश करके वाणिज्यिक जहाजों के लिए फारस की खाड़ी से ओमान सागर तक और ओमान सागर से फारस की खाड़ी तक सुरक्षित आवाजाही का इंतजाम करेगा, जिसके लिए सिर्फ 60 दिनों तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।' ट्रंप और उनके सहयोगियों को लगा कि यही जहाजों की आवाजाही शुरू करने का मुख्य तरीका है और इससे ईरानियों पर जिम्मेदारी आ जाएगी। ईरानियों ने इसे तेल ले जाने वाले अहम रास्ते पर नियंत्रण करने के मौके के तौर पर देखा और जोर दिया कि जहाज उनके तट के सबसे करीब वाले रास्ते से गुजरें। आखिरकार, ईरान ने संकेत दिया है कि वह इस जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए शुल्क लेने की योजना बना रहा है। जब अमेरिकी नौसेना ने ओमान के पास एक अलग रास्ते से जहाजों को सुरक्षित ले जाना शुरू किया, तो ईरान ने कुछ जहाजों पर गोलीबारी की। अब, लॉयड्स ऑफ लंदन के अनुसार, इस जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही बहुत कम हो गई है। इसी बात से ट्रंप परेशान हुए और उन्होंने घोषणा कर दी कि यह समझौता 'खत्म' हो गया है।

ट्रंप के सहयोगियों का कहना है कि वह समझौते का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह समझौता कामकाज के आधार पर है और ईरान के काम इस कसौटी पर खरे नहीं उतरे। इन सब बातों से ट्रंप फिर उसी स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां वह अप्रैल में थे, जब उन्हें पता चला था कि सैन्य ताकत से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ईरान में कई लोग किसी भी कूटनीतिक समाधान को अगले इस्राइली-अमेरिकी हमले तक का समय काटने का माध्यम ही मानते हैं।

©The New York Times 2026

मुद्दा

बढ़ती नहीं, घटती आबादी है चुनौती

शिक्षा, बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा के चलते आज का युवा शादी और बच्चों से दूरी बना रहा है, जिससे घटती आबादी की नई चुनौती जन्म ले रही है।

डॉ. विवेक एस अग्रवाल

दस वर्ष पूर्व जहां बढ़ती जनसंख्या पूरी दुनिया के लिए चिंता थी, वहीं आज घटती जनसंख्या को लेकर मंथन किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में इस शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों की जनसंख्या संबंधी नीति का स्मरण हो आता है। उन देशों में बच्चे पैदा करने, विशेष तौर पर तीसरे बच्चे, के लिए अनेकानेक प्रोत्साहन-जैसे सवेतन अवकाश, रेल यात्रा में छूट, सरकारी परिलाभ आदि प्रचलित थे। उस समय भारत जहां बढ़ती आबादी से जूझ रहा था, वहीं वे देश घटती जन्म दर और प्रवासी श्रमिकों पर बढ़ती निर्भरता को लेकर चिंतित थे। हालांकि, भारत दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश हो गया है, किंतु वर्तमान युवा पीढ़ी की संतानोत्पत्ति के प्रति बढ़ती बेरुखी के चलते, आने वाला समय निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होने वाला है।

संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण-पूर्व एशिया में पिछले बीस वर्षों में बाल विवाह की दर आधी रह गई है। इसकी बड़ी वजह युवाओं का शिक्षा की ओर बढ़ता रुझान, बेरोजगारी, आवास की लागत और समाज की बदलती सोच है। दुनिया के कई देशों में युवा शादी से दूरी बना रहे हैं। इसके पीछे अच्छा जीवनसाथी या स्थायी नौकरी न मिलना, आर्थिक परेशानियां और निजी आजादी में कमी का डर जैसे कारण हैं। यह सभ्यता के लिए सकारात्मक लक्षण नहीं है। जीने की औसत आयु और स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता में बढ़ोतरी और सामाजिक परिवर्तन के चलते बच्चे पैदा करना अब लोगों की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। इसके अलावा, संकोच और सामाजिक वर्जनाओं के कारण परिवारों में शादी, यौन संबंध, गर्भधारण और मातृत्व जैसे विषयों पर खुलकर बात नहीं हो पाती। यही बंधन विद्यालयों में भी है। नतीजतन, हर स्तर पर लोगों के अपने अलग-अलग विचार हैं। इन विषमताओं को देखते हुए अब युवाओं के लिए रुकावटें खड़ी करने के बजाय नए विकल्प तैयार करने की सोच पर जोर दिया जा रहा है। अस्सी के दशक में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डॉ. महिंदर वात्सा और अवाबाई वाडिया व नेशनल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन की ओर से विद्यालयों में पारिवारिक जीवन शिक्षा के तहत इन विषयों हेतु अभियान चलाया गया था, पर वह परवान न चढ़ सका। वर्तमान सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत इस विषय को प्रमुखता से प्रसारित करने की मंशा जाहिर की है। युवा से वृद्ध होती आबादी के लिए चीन और जापान के उदाहरण नजीर हैं कि समय रहते कदम उठाए जाने चाहिए।

इसी वजह से इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या दिवस की थीम युवाओं की इच्छाओं और जरूरतों पर केंद्रित रखी है, ताकि वे अपने अधिकारों का सही उपयोग करते हुए अपनी पसंद का बेहतर भविष्य बना सकें। आवश्यकता युवा संवाद द्वारा युवाओं में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करते हुए आने वाली संतति के लिए उपयुक्त वातावरण और अवसर के प्रति आश्वस्त करने की है। सामाजिक बदलावों के कारण परिवारों में आपसी विश्वास व समझ कम हुई है, जिससे दूरी और टकराव बढ़ा है। ऐसे में, कुटुंब प्रबोधन के जरिये परिवार की ताकत का एहसास कराना और दूरियों को कम करना जरूरी है, ताकि तेजी से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव की गति को रोका जा सके। हर व्यक्ति को इस विषय पर जागरूक होकर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

edit@amarujala.com

एआई वैज्ञानिक खोजों और नए आविष्कारों की रफ्तार को इतना बढ़ा सकता है, जिसकी कल्पना मनुष्य अकेला कभी नहीं कर सकता था।
-सैम अल्टमैन

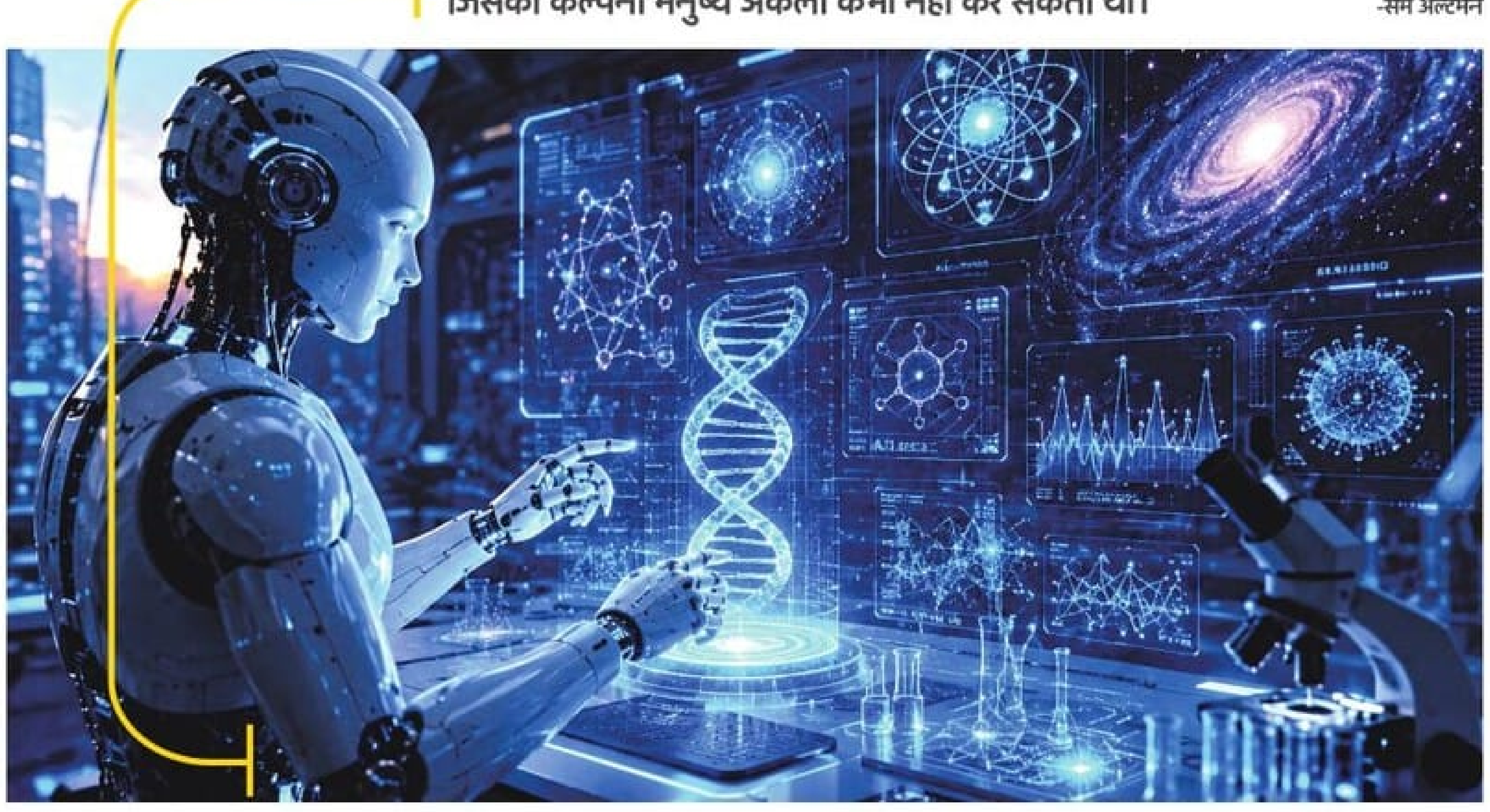

जिज्ञासा ही सबसे बड़ी ताकत

जब तक इन्सान सवाल पूछना नहीं छोड़ेगा, तब तक वह आगे बढ़ता रहेगा। ब्रह्मांड का हर रहस्य हमें यही याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत उत्तरों में नहीं, बल्कि उन्हें खोजने की अटूट इच्छा में छिपी है।

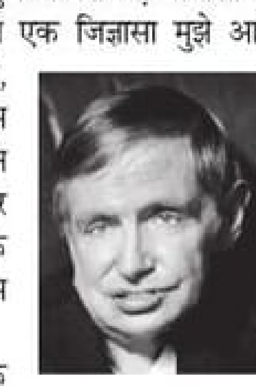

स्टीफन हॉकिंग

जीवन धारा

मैं ने अपना जीवन ब्रह्मांड से जुड़े कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब खोजने में बिताया। हमेशा एक जिज्ञासा मुझे आगे बढ़ाती रही कि हम कहां से आए हैं, ब्रह्मांड कैसे बना, क्या इसमें हम अकेले हैं, और हमारा भविष्य क्या होगा? विज्ञान ने बताया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं, बल्कि लगातार फैल रहा है, तब यह समझना संभव हुआ कि इसकी शुरुआत एक बिंदु से हुई होगी, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं।

मेरे लिए असली सवाल सिर्फ यह नहीं था कि ब्रह्मांड कैसे बना, बल्कि यह भी था कि क्या प्रकृति के नियम स्वयं उसकी उत्पत्ति की व्याख्या कर सकते हैं। वर्षों के शोध ने मुझे इस विश्वास तक पहुंचाया कि ब्रह्मांड को समझना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों को ही जानना है। इसी खोज ने मुझे एक और सवाल तक पहुंचाया कि क्या जीवन केवल पृथ्वी तक ही सीमित है? मेरा मानना है कि अगर सही परिस्थितियां मिलें, तो जीवन ब्रह्मांड के दूसरे कोनों में भी जन्म ले सकता है। आज हमारे पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, पर विज्ञान की खूबसूरती यही है कि वह कल्पनाओं पर नहीं, सबूतों पर आगे बढ़ता है। इसलिए, मैं हर उत्तर से अधिक उस खोज को महत्व देता हूं, जो हमें नए प्रश्न पूछने का साहस देती है।

इन्सान ने विज्ञान व तकनीक के सहारे अद्भुत प्रगति तो की है, पर प्राकृतिक संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव भी डाला है। ऐसे में, मानव सभ्यता को लाखों वर्षों तक जीवित रखने के लिए केवल पृथ्वी पर निर्भर नहीं रहना होगा। हमें अंतरिक्ष की ओर भी बढ़ना होगा।

मेरी शारीरिक सीमाएं कभी मेरी कमजोरी नहीं बनीं। उन्होंने मुझे यह सिखाया कि मनुष्य का वास्तविक बल उसके शरीर में नहीं, उसकी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प में होता है। मैं मानता हूं कि जब तक इन्सान सवाल पूछना नहीं छोड़ेगा, तब तक वह आगे बढ़ता रहेगा। ब्रह्मांड का हर रहस्य हमें यही याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत उत्तरों में नहीं, बल्कि उन्हें खोजने की अटूट इच्छा में छिपी है।

अपनी सोच एआई के हवाले न करें

एआई सेकंडों में जवाब तो दे देता है, पर उसी तेजी से वह कुछ नया जानने या सीखने की इच्छा को भी खत्म कर रहा है।

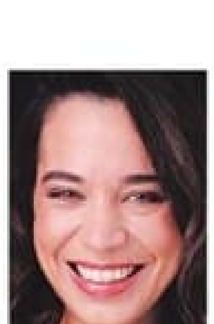

ऐन-लॉर ले कनफ
द न्यूयॉर्क टाइम्स

AI समय

कल्पना कीजिए कि आपने गूगल या किसी एआई टूल पर एक सवाल पूछा। कुछ ही सेकंड में पूरा जवाब सामने आ गया। न किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत, न अलग-अलग वेबसाइटों पर भटकने की। काम आसान हो गया, समय बच गया। लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि इस सुविधा की कीमत पर हम कुछ खोते भी जा रहे हैं?

वर्तमान में अधिकतर गूगल सर्च में उपयोगकर्ता किसी भी वेबसाइट पर क्लिक ही नहीं करता। बस सवाल टाइप करता है, एआई से तैयार सारांश पढ़ता है और आगे बढ़ जाता है। यही तरीका कई अन्य एआई टूल्स भी अपना रहे हैं। पहले लोग जानकारी पाने के लिए अलग-अलग स्रोतों से पढ़ते थे। इस दौरान उन्हें कई नई और दिलचस्प बातें भी पता चल जाती थीं। अब यह खोजबीन धीरे-धीरे कम होती जा रही है। पर, क्या तेज जवाब मिलना हमेशा फायदेमंद होता है? जवाब है- नहीं। एआई टूल्स अब हर सवाल का जवाब तुरंत दे देते हैं। इससे नई बातें खोजने और जानने की हमारी जिज्ञासा धीरे-धीरे कम होती जा रही है।

करीब दस साल पहले मैं गूगल में काम करती थी। उस समय हम कंटेंट की उपयोगिता का आकलन इस आधार पर करते थे कि लोग उस पर कितना समय बिताते हैं, कितने लिंक खोलते हैं और कितनी गहराई तक पढ़ते हैं। तब गूगल लोगों को ज्यादा खोजबीन करने के लिए प्रोत्साहित करता था। लेकिन, अब उसके एआई उत्पाद उसी खोजबीन की जरूरत को कम करने के लिए बनाए जा रहे हैं।

शोध बताते हैं कि जब किसी रोचक सवाल का जवाब मिलने में थोड़ा समय लगता है, तो उस दौरान मिली दूसरी जानकारी, उससे जुड़ी न होने वाली बातें भी हमें ज्यादा अच्छी तरह याद रहती हैं। दरअसल, जवाब का इंतजार करते समय दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम सक्रिय हो जाता है और हिप्पोकैंपस नई यादें बनाने के लिए अधिक तैयार रहता है। यानी, जिज्ञासा हमारे पूरे दिमाग को सीखने के लिए तैयार कर देती है। यह केवल उस सवाल का जवाब समझने में मदद नहीं करती, जिसे हम जानना चाहते हैं, बल्कि उससे जुड़ी दूसरी जानकारियों को भी बेहतर ढंग से ग्रहण करने में मदद करती है।

जिज्ञासा एक खुली खिड़की की तरह काम करती है। जब तक यह खिड़की खुली रहती है, सीखने की प्रक्रिया गहरी व व्यापक होती जाती है। पर, यदि एआई कुछ ही सेकंड में जवाब दे दे, तो यह खिड़की समय से पहले ही बंद हो जाती है। आपको जवाब तो मिल जाता है, पर वह अवसर खो जाता है, जब कोई दूसरा लेख, नया विचार या दो अवधारणाओं के बीच अप्रत्याशित संबंध सामने आ सकता था। शोधकर्ता इसे इंसीडेंटल लर्निंग, यानी अनजाने में होने वाली सीख कहते हैं। इतिहास की कई बड़ी खोजें इसी प्रक्रिया का परिणाम रही हैं। जब लोग किसी सवाल के पीछे अधिक समय तक लगे रहते हैं, तब उन्हें ऐसी बातें भी पता चलती हैं, जिनकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होती। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण 1964 का है। भौतिक वैज्ञानिक अर्नो पेन्जियास और रॉबर्ट विल्सन ने अपने रेडियो एंटीना में एक अजीब-सी आवाज सुनी। वे उसे अनदेखा कर सकते थे, पर उन्होंने उसकी वजह तलाश की। इसी जिज्ञासा ने उन्हें बिग बैंग के बाद बची हुई कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की ऐतिहासिक खोज तक पहुंचा दिया।

हिग्सफील्ड एआई

यह केवल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या किसी तस्वीर की मदद से उच्च गुणवत्ता वाली छवि व वीडियो तैयार कर सकता है। यह कई प्रमुख एआई मॉडल्स को एक साथ जोड़कर काम करता है और उपयोगकर्ता के निर्देश के अनुसार सबसे उपयुक्त मॉडल का चयन करता है। इसमें टेक्स्ट से इमेज, टेक्स्ट से वीडियो, कैमरा एंगल नियंत्रण व एकसमान चेहरे की पहचान बनाए रखने जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसकी मदद से पेशेवर वीडियो एडिटिंग सीखे बिना भी आकर्षक और प्रभावशाली वीडियो बनाए जा सकते हैं। यह कंटेंट क्रिएटर्स, मार्केटर्स व डिजिटल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।

आज की तकनीक सवाल-जवाब के बीच के समय को बेकार मानकर खत्म करना चाहती है, जबकि सीखने की प्रक्रिया इसी दौरान सबसे गहरी होती है। जब लोग कम खोजबीन करेंगे, तो धीरे-धीरे वे अपने दम पर नई खोज व नए विचार बनाने के बजाय तैयार जवाबों पर अधिक निर्भर हो जाएंगे। आज भी लोग इंटरनेट पर अलग-अलग वेबसाइट देख सकते हैं, लिंक से लिंक तक पहुंच सकते हैं और खोजते-खोजते नई जगहों और विचारों तक पहुंच सकते हैं। पर, एआई टूल्स का मौजूदा डिजाइन कुछ इस तरह है कि अब ऐसा होने की संभावना कम होती जा रही है। हालांकि, जो एआई कंपनियां अपने उपयोगकर्ताओं के हित को महत्व देती हैं, वे ऐसे सर्च इंजन विकसित कर सकती हैं, जिनका उद्देश्य केवल तेज जवाब देना नहीं, बल्कि नई जानकारियां खोजने और गहराई से समझने के लिए लोगों को प्रेरित करना हो। सवाल और जवाब के बीच का समय मूल्यवान होता है और डिजाइन के नाम पर उसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए।

यदि हम ऐसी दुनिया बना देंगे, जहां हमें केवल वही मिले, जो हमने पूछा है, तो हम उन खोजों तक पहुंचने की क्षमता खो देंगे, जिनके बारे में हमें यह भी नहीं पता था कि उनसे जुड़े सवाल कभी पूछे जा सकते हैं।

आईटी शेयरों ने फिर संभाला बाजार, सेंसेक्स 827 अंक चढ़ा

कच्चे तेल में नरमी के बीच घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद

नई दिल्ली। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के जून तिमाही के बेहतर नतीजों के बाद सूचना प्रौद्योगिकी शेयरों में आई तेजी, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और कमजोर डॉलर से बाजार की धारणा को बल मिला। इससे शुक्रवार को भारतीय बाजार बढ़त के साथ बंद हुए।

बीएसई सेंसेक्स 827.57 अंक यानी 1.08 फीसदी उछलकर 77,569.39 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 900.41 अंक यानी 1.17 फीसदी चढ़कर 77,642.23 तक पहुंच गया था। निफ्टी 244.10 अंक यानी 1.02 फीसदी की बढ़त के साथ 24,206.90 पर बंद हुआ। इस तेजी के बाद दोनों सूचकांकों ने अपनी साप्ताहिक गिरावट कम करके 0.3 फीसदी पर ला

दिया। सप्ताह के मध्य में अमेरिका-ईरान तनाव और कच्चे तेल में उछाल के कारण बाजारों में गिरावट देखी गई थी। इस कारण मुख्य सूचकांकों की लगातार चार हफ्तों से चली आ रही बढ़त का सिलसिला टूट गया, जो साल 2026 में उनकी सबसे लंबी साप्ताहिक बढ़त थी। इस हफ्ते सेंसेक्स 194.25 अंक यानी 0.25 फीसदी और निफ्टी 63.95 अंक यानी 0.26 फीसदी के नुकसान में रहे। ■ बोनस डेस्क

रुपया 9 पैसे बढ़कर 95.38 पर

शुक्रवार को रुपया 9 पैसे की मजबूती के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.38 पर बंद हुआ। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की बिकवाली के कारण रुपये पर लगातार दबाव बना रहा। *अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 95.27 प्रति डॉलर पर खुला। कारोबार के दौरान यह 95.22 के उच्च स्तर और 95.42 के निचले स्तर के बीच रहा।*

बाजार में बना रहेगा उतार-चढ़ाव

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। आगे निवेशकों की नजर मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के नतीजों और घरेलू महंगाई के आंकड़ों पर रहेगी, जबकि वैश्विक निवेशकों का ध्यान अमेरिका के कोर इन्फ्लेशन डाटा और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की टिप्पणियों पर केंद्रित रहेगा।

चीन के साथ नई औद्योगिक रणनीति डिक्सन-वीवो डील से बदलेगा खेल

नई दिल्ली। सरकार द्वारा वीवो मोबाइल इंडिया और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के संयुक्त उपक्रम को मंजूरी देना केवल स्मार्टफोन विनिर्माण से जुड़ा फैसला नहीं, बल्कि यह चीनी निवेशों के प्रति भारत की बदलती नीति का भी स्पष्ट संकेत माना जा रहा है।

वर्ष 2020 में गलवां घाटी संघर्ष के बाद सरकार ने प्रेस नोट-3 लागू किया था। इसके तहत भारत से भूमि सीमा साझा करने वाले देशों विशेषकर चीन से आने वाले सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सरकारी मंजूरी के दायरे में लाया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि अब सरकार चीनी निवेश को पूरी तरह खारिज करने के बजाय ऐसे मॉडल को बढ़ावा दे रही है, जिसमें तकनीक और विशेषज्ञता तो चीन से मिले, लेकिन स्वामित्व और नियंत्रण भारतीय हाथों में रहे। चीनी कंपनियां डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराएंगी, जबकि संचालन और प्रबंधन भारतीय कंपनियों के पास रहेगा। नए संयुक्त उपक्रम में डिक्सन टेक्नोलॉजीज की 51 फीसदी और वीवो मोबाइल इंडिया की 49 फीसदी हिस्सेदारी होगी। नई कंपनी भारत में स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करेगी। शुरुआत में उत्पादन मुख्य रूप से वीवो के लिए होगा, लेकिन भविष्य में अन्य ब्रांडों के लिए भी विनिर्माण किया जा सकेगा। ब्यूरो

एक्सप्लेनर

रुपये को बचाते-बचाते खुद मुश्किल में

किस चक्रव्यूह में फंसा भारतीय रिजर्व बैंक?

आरबीआई के सामने बड़ी चुनौती...क्या देश के खजाने पर भारी पड़ने वाला है केंद्रीय बैंक का डॉलर वाला दांव?

पिछले दो साल से जब डॉलर पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखा रहा था, तब भारतीय रुपये को टूटने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने पारंपरिक तरीका छोड़कर डेरिवेटिव बाजार का सहारा लिया। आरबीआई ने दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्ट डॉलर फॉरवर्ड पोजीशन का दांव खेल डाला।

आरबीआई ने वादा किया कि वह एक तय तारीख पर डॉलर बेचेगा और रुपया खरीदेगा। मई 2026 तक गुप्त वादे की रकम 106.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

आरबीआई के सामने मुश्किल क्या है?

■ फॉरवर्ड बुक असल में टाल दी गई डॉलर की मांग है। इसे हमेशा के लिए आगे नहीं बढ़ा सकते। किसी न किसी दिन आरबीआई को बाजार से डॉलर खरीदकर इस वादे को पूरा करना ही होगा। और संकट यही है। जैसे ही आरबीआई इस वादे को पूरा करने के लिए बाजार से डॉलर खरीदने उतरेगा, बाजार में डॉलर की मांग बढ़ेगी और रुपया अपने आप और कमजोर होने लगेगा।

रुपये में लगातार नौवें साल गिरावट

जून में राहत के बाद जुलाई 2026 में रुपया 0.8 फीसदी टूट चुका है। यह लगातार नौवें साल सालाना गिरावट की राह पर है। इंडोनेशियाई रुपिया के बाद इस साल भारतीय रुपया एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन चुका है। एमके ग्लोबल के मुताबिक, समस्या गंभीर इसलिए है क्योंकि आरबीआई की 100 अरब डॉलर से ज्यादा की फॉरवर्ड बुक के लिए समय-सीमा बहुत कम है। बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि 2026 के अंत तक रुपया 98 प्रति डॉलर के स्तर को छू सकता है।

कैसे खड़ा हुआ सबसे बड़ा धर्मसंकट?

रिजर्व बैंक इस समय आगे कुआं, पीछे खाई जैसी स्थिति में है। यदि आरबीआई इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लंबे समय तक खींचता है, तो इसकी लागत बहुत बढ़ जाएगी। यदि वह पोजीशन को तेजी से खत्म करता है, तो विदेशी निवेशकों के जरिये आने वाला फंड रुपये को जो मजबूती दे सकता था, उसका असर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। 2025 में अमेरिकी टैरिफ और 2026 में अमेरिका-ईरान तनाव से कच्चे तेल की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। ऐसे में आरबीआई की एक भी गलत चाल बाजार में भारी उथल-पुथल मचा सकती है।

अब आगे क्या है रास्ता?

रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और बफर मौजूद है और बैंक रुपये में किसी भी अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए तैयार है। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक कच्चे तेल की कीमतें नीचे नहीं आतीं और विदेशी संस्थागत निवेशकों का भारत में स्थायी रूप से आना शुरू नहीं होता, तब तक आरबीआई के लिए रुपये को चोट पहुंचाए बिना इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना बेहद जटिल और जोखिम भरा रहेगा। ■ बोनस डेस्क

न्यूज डायरी

विदेशी मुद्रा भंडार 7.26 अरब डॉलर बढ़ा

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3 जुलाई 2026 को समाप्त सप्ताह में 7.26 अरब डॉलर बढ़कर 674.19 अरब डॉलर हो गया। इससे पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 5.65 अरब डॉलर घटकर 666.93 अरब डॉलर रह गया था। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 4.51 अरब डॉलर बढ़कर 545.57 अरब डॉलर हो गईं। गोल्ड रिजर्व 2.66 अरब डॉलर बढ़कर 105.20 अरब डॉलर हो गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास रिजर्व पोजीशन बढ़कर 4.78 अरब डॉलर हो गई। एजेंसी

सेबी ने रद्द किया 12 संस्थाओं का पंजीकरण

नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करने पर 12 रिसर्च एनालिस्ट संस्थाओं का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इनमें अर्जुन लेनिन, सीएनआई रिसर्च, ईस्ट ब्रिज एडवाइजर्स प्राइवेट लि., कुशांक कमल पोद्दार और आरके ग्लोबल शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जैसे नाम शामिल हैं। सेबी के नियमों के मुताबिक, प्रत्येक पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट को हर पांच वर्ष में नवीनीकरण शुल्क जमा करना अनिवार्य है। एजेंसी

एसआईपी निवेश 3 महीने के उच्च स्तर पर डेट फंड्स से निकले एक लाख करोड़ रुपये

एम्फी के आंकड़े : जून में इक्विटी म्यूचुअल फंड में आया 28,973 करोड़ का निवेश

बोनस डेस्क

नई दिल्ली। एक महीने की सुस्ती के बाद म्यूचुअल फंड निवेशकों की धारणा में सुधार आया है। म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश जून में तीन महीने के उच्च स्तर 31,781 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह मई के 30,954 करोड़ रुपये से तीन फीसदी अधिक है। सालाना आधार पर, एसआईपी निवेश पिछले साल जून के 27,269 करोड़ से 4,512 करोड़ रुपये बढ़ गया।

जून में इक्विटी म्यूचुअल फंड का कुल निवेश मासिक आधार पर 26.5 फीसदी बढ़कर 28,973 करोड़ रुपये हो गया, जो मई में 22,908 करोड़ रुपये था। हालांकि यह मार्च और अप्रैल के स्तरों से अब भी नीचे है। तब निवेशकों ने क्रमशः 40,000 करोड़ और 38,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया था। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इक्विटी योजनाओं के प्रबंधन के तहत कुल परिसंपत्तियां जून में बढ़कर 37.34 लाख करोड़ रुपये हो गईं, जो मई में सिर्फ 36.14 लाख करोड़ रुपये थीं। इक्विटी म्यूचुअल फंड की 11 उप-श्रेणियों में मिडकैप फंड निवेशकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बने रहे। इसमें 6,090 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश आया। स्मॉल-कैप फंड 5,602 करोड़ निवेश के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि फ्लेक्सी-कैप फंडों को 5,231 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। लार्ज और मिड-कैप फंडों में भी 4,321 करोड़ रुपये के निवेश के साथ निवेशकों की स्वस्थ रुचि बनी रही और मल्टी-कैप फंडों ने 3,070 करोड़ रुपये आकर्षित किए।

मासिक आधार पर, सेक्टोरल और थीमैटिक फंडों में निवेश में सबसे तेज वृद्धि देखी गई, जो 127 फीसदी उछलकर 1,469 करोड़ रुपये हो गई। वैल्यू/कॉन्ट्रा और फोकस्ड फंड की बात करें तो प्रत्येक में 35 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। डिविडेंड यील्ड फंड और ईएलएसएस फंडों से जून में क्रमशः 49 करोड़ और 633 करोड़ रुपये की निकासी की गई।

गोल्ड ईटीएफ की चमक फिर बढ़ी

जून में गोल्ड ईटीएफ के निवेश में मासिक आधार पर 570 फीसदी से अधिक का उछाल आया। गोल्ड ईटीएफ में इस दौरान 3,443 करोड़ रुपये का निवेश आया, जबकि पिछले महीने इसमें 725 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी। सिल्वर ईटीएफ में 300 फीसदी की मासिक तेजी देखी गई। द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड के उमेश शर्मा ने कहा, निवेशकों ने घरेलू गोल्ड ईटीएफ में आवंटन आक्रामक रूप से बढ़ाते हुए व्यावहारिक एंट्री पॉइंट्स का लाभ उठाया।

डेट म्यूचुअल फंड से भारी निकासी

डेट म्यूचुअल फंड्स में लगातार दूसरे महीने निकासी देखी गई। निवेशकों ने मई में 96,948 करोड़ निकालने के बाद इस महीने 1.09 लाख करोड़ रुपये निकाल लिए। इस अवधि में डेट फंड का एयूएम 18.25 लाख करोड़ से घटकर 17.38 लाख करोड़ रुपये रह गया। क्रेडिट रिस्क फंड और फ्लोटर फंड को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों में निकासी देखी गई। इनको क्रमशः 247 करोड़ और 452 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ। 16 उप-श्रेणियों में लिक्विड फंड में 42,293 करोड़ रुपये की सबसे अधिक निकासी हुई।

हाइब्रिड फंड्स में पैसा आना जारी

हाइबिड फंड्स निवेशकों की पसंद बने रहे। इसमें 12,893 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश आया, जो मई में 10,560 करोड़ रुपये था। आर्बिट्राज फंड 5,799 करोड़ के निवेश के साथ हावी रहे, जबकि मल्टी-एसेट एलोकेशन फंडों में 4,811 करोड़ आए। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंडों में निवेश सुधरकर 2,121 करोड़ रुपये हो गया। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंडों ने 553 करोड़ रुपये आकर्षित किए।

सोना 400 रुपये चढ़ा, चांदी में 5,000 की तेजी

नई दिल्ली। शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। सराफा बाजार में सोना 400 रुपये उछलकर 1,48,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले सत्र में इसका भाव 1,48,100 रुपये था। चांदी में भी तीन कारोबारी सत्रों की गिरावट थम गई। चांदी 5,000 रुपये की तेज छलांग लगाकर 2,37,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। बृहस्पतिवार को इसका भाव 2,32,000 रुपये था।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, लगातार तीसरे दिन डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आने से कीमती धातुओं की मांग बढ़ी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ कमोडिटी विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, कमजोर अमेरिकी डॉलर और निचले स्तर पर हुई खरीदारी के कारण शुक्रवार को सोने की कीमतों को समर्थन मिला। उधर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 17.57 डॉलर यानी 0.43% की गिरावट के साथ 4,106.25 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। एजेंसी

अमर उजाला Job Alert

Real-time job alerts amarujala.com/jobs

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन

प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी के पद खाली

6715 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 21 जुलाई, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 20 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष
यहां आवेदन करें : ibps.in

बीएचईएल, हरिद्वार में मौके ■ 187 पद

अप्रेंटिसशिप के लिए निकली भर्ती
आवेदन की अंतिम तिथि : 15 जुलाई, 2026
पात्रताएं : दसवीं, आईटीआई व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें : hwr.bhel.com/recruitment

डीटीयू में निकली भर्ती ■ 108 पद

अप्रेंटिसशिप के लिए करें आवेदन
आवेदन की अंतिम तिथि : 31 जुलाई, 2026
पात्रताएं : ग्रेजुएशन, डिप्लोमा व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें : dtu.ac.in

आईडीबीआई बैंक में मौके ■ 31 पद

स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि : 26 जुलाई, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम आयु 25 वर्ष व अधिकतम आयु 45 वर्ष
यहां आवेदन करें : idbi.bank.in

बीईएमएल लिमिटेड में अवसर ■ 23 पद

सीजीएम, जीएम, डीजीएम व अन्य पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 25 जुलाई, 2026
वेतनमान : रुपये 40,000 से लेकर रुपये 2,80,000 प्रतिमाह
यहां आवेदन करें : bemlindia.in

नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ■ 12 पद

सहायक संपादक व अन्य पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि : 23 जुलाई, 2026
योग्यताएं : ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन व अन्य पात्रताएं
यहां आवेदन करें : nbtindia.gov.in

यहां भी हैं रोजगार के अवसर...

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी : स्टोर कीपर का पद रिक्त।
■ आवेदन की अंतिम तिथि : 25 जुलाई, 2026
■ igrua.gov.in/

आईसीएफआरई वन अनुसंधान संस्थान : एलोपैथिक डॉक्टर (जनरल फिजिशियन) का पद खाली।
■ आवेदन की अंतिम तिथि : 24 जुलाई, 2026
■ fri.icfre.gov.in/hindi/

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

एजुकेशन & कॅरिअर

सही दिशा में निरंतर प्रयास करने से अंततः सफलता मिलती है।

यहां छात्रवृत्तियों की कमी नहीं

अगर आप अपने लिए उपयुक्त छात्रवृत्ति नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो एनएसपी पोर्टल आपकी मदद कर सकता है

सुनंदा राव
कॅरिअर सलाहकार

कॉलेज या स्कूल की पढ़ाई के दौरान कई छात्रों को फीस, किताबें और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति एक अच्छा विकल्प है। यदि आप छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर जाकर अपनी योग्यता के अनुसार उपलब्ध योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। समय पर आवेदन करके आप अपनी पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, यह पोर्टल छात्रवृत्ति आवेदन, सत्यापन और वितरण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी तथा तेज बनाता है।

■ सरल व पारदर्शी प्रक्रिया

छात्र इस पोर्टल के माध्यम से अपनी पात्रता के अनुसार उपलब्ध छात्रवृत्ति योजनाओं का चयन कर सकते हैं और आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन जांच सकते हैं। आवेदन स्वीकृत होने पर छात्रवृत्ति की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे छात्र के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे प्रक्रिया तेज और सुरक्षित बनती है।

■ आवश्यक योग्यता

आमतौर पर कक्षा एक से लेकर पीएचडी तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। छात्र का किसी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्ययनरत होना आवश्यक हो सकता है। कई योजनाओं में परिवार की वार्षिक आय का विवरण मांगा जाता है, जो निर्धारित सीमा के अंदर होनी चाहिए और कुछ योजनाओं में न्यूनतम शैक्षणिक अंक भी जरूरी होते हैं।

■ मिलने वाली स्कॉलरशिप

एनएसपी विभिन्न मंत्रालयों और संस्थाओं की अनेक छात्रवृत्ति योजनाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराता है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप (जैसे अल्पसंख्यक मामलों, उच्च शिक्षा, जनजातीय मामलों और गृह मंत्रालय की योजनाएं), राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की स्कॉलरशिप, यूजीसी और एआईसीटीई की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी योजनाएं, प्री-मैट्रिक (कक्षा एक से 10) और पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा 11, 12, कॉलेज एवं उच्च शिक्षा), स्कॉलरशिप, मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप (विशेष रूप से प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स के लिए), दिव्यांग, अनुसूचित जनजाति (एसटी), अल्पसंख्यक आदि वर्गों के लिए विशेष स्कॉलरशिप तथा नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं शामिल हैं।

- *पात्रता के अनुसार स्कॉलरशिप का चयन कर सकते हैं।*
- *दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध है।*
- *आवेदन और भुगतान की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।*
- *प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक व कई अन्य स्कॉलरशिप उपलब्ध हैं।*

■ ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल scholarships.gov.in/ पर जाकर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन करें और प्राप्त क्रेडेंशियल से लॉग इन करें। इसके बाद आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और बैंक संबंधी जानकारी भरकर अपनी पात्र स्कॉलरशिप योजना चुनें तथा आवश्यक दस्तावेज (जैसे आधार, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, मार्कशीट और बैंक पासबुक) अपलोड करें। सभी विवरणों की जांच करने के बाद आवेदन को सबमिट करें।

फेलोशिप प्रोग्राम

क्लाइमेट टेक फेलोशिप-2026

- पात्रताएं : आवेदक रिसर्चर, एंटरप्रेन्योर, इंजीनियर या इनोवेटर हों। वे शुरुआती चरण की क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हों।
- अवधि : छह माह
- लाभ : 10,000 डॉलर
- अंतिम तिथि : 01 अगस्त, 2026
- आवेदन लिंक : nyclimateexchange.org/climate-tech-fellowship

आवेदन आमंत्रित

निबंध लेखन प्रतियोगिता

- संस्थान : आईसीएआई
- विषय : वित्तीय पारदर्शिता और सुशासन व राष्ट्र निर्माण में करदाताओं की भूमिका
- शब्द सीमा : 500-600 शब्द
- भाषा : अंग्रेजी या हिंदी
- पुरस्कार : रुपये 2,000 से लेकर रुपये 25,000
- आवेदन की अंतिम तिथि : 30 सितंबर, 2026
- आधिकारिक वेबसाइट : tinyurl.com/bdf32sc2

एग्जाम अलर्ट

बीएलसीएल एग्जीक्यूटिव ट्रेनी परीक्षा

- **परीक्षा की तिथि :** 15 जुलाई, 2026
- भाग-1 में टेक्निकल/प्रोफेशनल डोमेन से संबंधित 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि भाग-2 में लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से संबंधित 60 अंकों के प्रश्न शामिल होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की है।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** tinyurl.com/3ektzr2k

एनटीए सीएसआईआर यूजीसी नेट

- **परीक्षा की तिथि :** 17 व 18 जुलाई, 2026
- इस परीक्षा में लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एवं प्लैनेटरी साइंसेज विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित की गई है।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** csirnet.nta.nic.in/

सामान्य ज्ञान

एस्टेरॉयड टोरिफ्यून

■ क्या है

टोरिफ्यून एक छोटा-सा क्षुद्रग्रह है, जो पृथ्वी के पास से सूर्य की परिक्रमा करता है। वैज्ञानिक इसके जरिये सौर मंडल की शुरुआत और एस्टेरॉयड से बचाव की तकनीकों का अध्ययन कर रहे हैं।

■ चर्चा में क्यों

जापान के अंतरिक्ष यान 'हायाबुसा2' ने पृथ्वी के पास मौजूद क्षुद्रग्रह 'टोरिफ्यून' के सिर्फ 800 मीटर पास से सफल उड़ान भरकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की।

परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स

■ क्या है

यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन को मापने वाला सूचकांक है। इसका उद्देश्य सभी का एक समान पैमाने पर मूल्यांकन करना है। पीजीआई 2.0 को दो श्रेणियों, छह डोमेन और 73 संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है।

■ चर्चा में क्यों

हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने वाली परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2025-26 की रिपोर्ट जारी की है।

आज का दिन

11 जुलाई, 1987

विश्व की आबादी पांच अरब होने पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने 'डे ऑफ फाइव बिलियन' मनाया था। इसका मकसद जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

■ 1859 : लंदन क्लॉक टॉवर 'बिग बेन' की घंटी को पहली बार बजाया गया था।
■ 1956 : अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार अमिताव घोष का जन्म हुआ था।
■ 2003 : प्रसिद्ध लेखक, नाटककार और अभिनेता भीष्म साहनी का निधन हुआ था।
■ 2006 : मुंबई की लोकल ट्रेनों में सात भीषण बम विस्फोट हुए थे।

व्रत त्योहार

आज : आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वादशी
कल : वर्षा ऋतु, सूर्य दक्षिणायने, उत्तर गोले।
राहुकाल : सायं 16.30 से 18.00 तक

■ सूर्योदय : 05.37
■ सूर्यास्त : 19.16
(भारतीय मानक समयानुसार)

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2083, 21 आषाढ़ मास शक 1948, आषाढ़ मास 28 प्रविष्टे, 26 मुहर्रम हिजरी 1448, आषाढ़ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 22.29 तक उपरांत चतुर्दशी, रोहिणी नक्षत्र 08.28 तक उपरांत मृगशिरा नक्षत्र, वृद्धि योग 20.05 तक उपरांत ध्रुव योग, गर करण 12.16 तक उपरांत वणिज करण, चंद्रमा मिथुन राशि में 19.04 बजे।

राशिफल

amarujala.com/astrology
■ पं. विनोद त्यागी

मेष : योजना अधूरी रहेगी। कार्य क्षेत्र में धैर्य बनाए रखें। अनैतिक कार्य से बचें। व्यवसाय में अचानक लाभ संभव है।

वृष : मनोत्साह बना रहेगा। नौकरी में जवाबदेहि बढ़ सकती है। नए कार्य में पूंजी निवेश से बचें। उदर कष्ट संभव है।

मिथुन : मान-सम्मान की चिंता रहेगी। वाणी पर संयम रखें। नौकरी में कार्य भार बढ़ सकता है।

कर्क : सहोदरों का सहयोग मिलेगा। संपत्ति में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। व्यवसाय में आशातीत लाभ होगा।

सिंह : शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा। नौकरी में उन्नति हो सकती है। व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा।

कन्या : चिंता से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में नूतन पद प्राप्ति संभव है। व्यवसाय में यथेष्ट लाभ होगा। विरोधी शांत रहेंगे।

तुला : पूर्वनियोजित कार्य में सफलता मिलेगी। मनोकामना पूर्ति का अवसर मिलेगा। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा।

वृश्चिक : नौकरी प्राप्ति संभव है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। व्यवसाय में लाभ कम होगा। घर में शांति रखें।

धनु : आरोग्य सुख मध्यम रहेगा। सरकारी क्षेत्र में परेशानी होगी। नौकरी में स्थिति यथावत रहेगी।

मकर : मन प्रसन्न रहेगा। अटका कार्य बनेगा। नौकरी में वर्चस्व बना रहेगा। व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा।

कुंभ : सकारात्मक सोच बनाए रखें। योजना में अवरोध आ सकते हैं। दिनचर्या अस्त-व्यस्त रहेगी।

मीन : आनंद में वृद्धि होगी। संतान से सुख मिलेगा। नई योजना में सफलता मिलेगी। अटका धन मिल सकता है।

सुडोकू

				5	8			
	5	1						9
7		4					2	5
			3		9		4	
2								1
	9		6		5			
3	4					2		8
1						7	3	
			9	8				

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

9	2	6	4	5	8	1	7	3
8	5	1	2	3	7	4	6	9
7	3	4	1	9	6	8	2	5
5	1	8	3	2	9	6	4	7
2	6	3	8	7	4	9	5	1
4	9	7	6	1	5	3	8	2
3	4	5	7	6	1	2	9	8
1	8	9	5	4	2	7	3	6
6	7	2	9	8	3	5	1	4